विषय - सूची

शासन व्यवस्था और प्रणाली

1. *Increasing expenditure in Lok Sabha elections-* लोकसभा चुनाव में निरंतर बढ़ता बेतहाशा खर्च (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)*.....
2. *Lokapal not provided staff and office-* लोकपाल ने कहा- न तो दफ्तर मिला, न पूरा स्टाफ; *5* सितारा होटल के *12* कमरों में चल रहा काम (*Relevant for GS Mains Paper II; Polity & Governance)*.....
3. *Supreme court allowed release of movie on PM Modi- PM Modi Biopic* को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, कांग्रेस की याचिका खारिज (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)*.....
4. *Election Commission stopped Modi's Bopic and Namo TV-*चुनाव आयोग ने मोदी की बायोपिक और नमो टीवी पर रोक लगाई (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
5. *Supreme Court asked the centre to make plan for cracker ban-* पटाखा बैन : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पटाखों के लिए प्लान बनाने को कहा (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
6. *Sufficient VVPAT slips to give credibility to election-* पर्याप्त वीवीपैट पर्चियों के मिलान से ही बढ़ेगी ईवीएम की विश्वसनीयता (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
7. *Electoral Bond:* क्या होता है चुनावी बॉन्ड (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
8. *Need to publish Supreme Court rules in English-* सुप्रीम कोर्ट नियमावली हिन्दी में प्रकाशित कराने का अनुरोध, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....

9. *EC order to BJP, don't broadcast NaMo TV without approval*- चुनाव आयोग का भाजपा को निर्देश, बिना प्रमाणन न करें नमो टीवी पर कोई प्रसारण (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
10. *Lateral entry at Joint Secreatry level* - प्राइवेट सेक्टर के इन लोगों को सरकार ने सीधे बनाया ज्वाइंट सेक्रेटरी (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .
11. *SC has not stayed ban on Tik tok app*- सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक को नहीं मिली राहत, ऐप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
12. *Legal proceedings against ex-president Bashir*-सूडान में चलेगा पूर्व राष्ट्रपति बशीर पर मुकदमा, मिलेगी मौत या होगा देश निकाला! (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
13. *Election Commission against leaders*- चार नेताओं पर चुनाव आयोग कार्रवाई *(Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)*.....
14. *Lack of office allocation to Lokpal*- देश का पहला लोकपाल दफ्तर दिल्ली के एक पांच सितारा होटल से काम करेगा (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)* .....
15. *Supreme Court* ने *RBI* को दिया लास्ट चांस, कहा-*RTI* के तहत करे बैंकों की जांच रिपोर्ट का खुलासा (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)*.....

अंतरराष्ट्रीय संगठन .....

1. UAE awarded Zayed medal to PM Modi- मोदी को मिलेगा जायेद मेडल, राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला यहां का सबसे बड़ा सम्मान (Relevant for GS Prelims; IOBR).....
2. Ausindex- ऑसिन्डेक्स -19 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के पोत और पनडुब्बी विशाखापत्तनम पहुंचे (Relevant for GS Prelims; IOBR) .....
3. Poor economic condition of Pakistan-पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).....

4. 360 prisoners to be released from Pakistan-360 भारतीय कैदियों को सोमवार से रिहा करेगा पाकिस्तान (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).....
5. Pakistan released 100 Indian Fishermen- पाकिस्तान ने 100 भारतीय मछुआरे रिहा किए, कहा- सद्भाव बढ़ाने के लिए उठाया कदम (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).....
6. America restricted H-1B visa seats to 65,000 Indians for year 2020- अमेरिका ने वर्ष 2020 तक के लिए H-1B वीजा की लिमिट को 65,000 तक सीमित किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).....
7. EU and UK ready to extend Brexit deadline till October- EU और UK ब्रेग्जिट की समयसीमा को अक्टूबर तक बढ़ाने पर हुए सहमत (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).....
8. Wikileaks founder Assange arrested in London- विकीलीक्स के संस्थापक असांजे गिरफ्तार, 2012 से इक्वाडोर दूतावास में ली थी शरण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).....
9. America ready to grant India status of NATO associate nation- भारत को 'नाटो सहयोगी देश' का दर्जा देने की तैयारी में अमेरिका, संसद में अहम बिल पेश (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
10. Netanyahu becomes Israel PM for fifth time- इजरायल के अंतिम नतीजे जारी, नेतन्याहू की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, पांचवीं बार पीएम बनने की तैयारी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
11. IMF may delay financial help to Pakistan- पाकिस्तान को झटका, आर्थिक मदद में देरी कर सकता है आइएमएफ (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
12. No trade through LoC on account of security reasons- LOC के जरिए व्यापार बंद आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
13. Appeal to Indians to leave Libya- सुषमा स्वराज की लीबिया में रह रहे भारतीयों से अपील, त्रिपोली छोड़ दें अन्यथा बाद में वापसी होगी मुश्किल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....

14. Serials blasts in Sri Lanka on occasion of Easter- ईस्टर के दिन चर्चों और होटलों को निशाना बनाकर किए गए 8 धमाके; 3 भारतीयों समेत 215 की मौत, 7 गिरफ्तार (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
15. UN Report: 20वीं सदी के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैसकांड (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
16. India will not be able to buy oil from Iran- ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद सकेगा भारत (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
17. Iran and Pakistan to constitute border reaction force to stop terror- आतंकी हमले रोकने के लिए बॉर्डर 'रिएक्शन फोर्स' बनाएंगे ईरान और पाकिस्तान (Relevant for GS Prelims; IOBR) .....
18. Iran conferred status of terror group on American forces- ईरानी संसद ने अमेरिकी सेना को आतंकी समूह का दर्जा दिया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
19. IS module took responsibility of terror attack- आइएस ने ली श्रीलंका आतंकी हमले की जिम्मेदारी, हमले में मरने वालों की संख्या हुई 321 (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
20. India to stop import of oil from Iran- ईरान से तेल का आयात बंद करेगा भारत, क्रूड के रेट 10% बढ़े तो महंगाई 0.24% बढ़ेगी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
21. Person of Indian origin won elections in Japan- भारतीय मूल के व्यक्ति ने पहली बार जापान में जीता चुनाव (Relevant for GS Prelims; IOBR) .....
22. Kim and Putin meet in Russia- 17 वर्ष पहले कभी यहीं पर किम के पिता से मिले थे पुतिन, जानें किम से मुलाकात के मायने (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
23. India rejected China's invitation to participate in 2nd BRI forum- भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियोजना पर किया कड़ा रुख अख्तियार, स्वीकार नहीं आमंत्रण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....

24. BCIM corridor out of China's BRI- चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से भारत की मौजूदगी वाले बीसीआईएम कॉरिडोर को बाहर किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
25. 200 American companies to shift manufacturing bases from America to India- 200 अमेरिकी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....
26. ISIS chief Baghdadi's video- 5 साल बाद सामने आया आईएस सरगना बगदादी, श्रीलंका में हमले की जिम्मेदारी ली (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) .....

अर्थशास्त्र.....

1. Last date to link PAN card and Aadhar- PAN Card और Aadhaar Card लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) .....
2. Regulatory sandbox guidelines-पेमेंट बैंक प्रमुखों से मिलेंगे RBI गवर्नर, सैंडबॉक्स गाइडलाइन जल्द (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) ...
3. Jet airways in financial touble- जेट एयरवेज ने 16 हजार कर्मियों की सैलरी रोकी, मंत्री ने इसे कंपनी का आंतरिक मामला बताया(Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) .....
4. Pension on the basis of full salary in private sector- निजी क्षेत्र में पूरी सैलरी पर पेंशन का रास्ता साफ, अधिकतम 15 हजार का फॉर्मूला लागू नहीं होगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
5. High chances of Mallya's- extradition प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ माल्या की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).

6. Relation between Fiscal deficit and economic growth- वित्तीय घाटे ओर आर्थिक विकास के बीच में संबंध (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) .....
7. Gold reserves with various nations-चीन लगातार खरीद रहा सोना, भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना अधिक गोल्ड रिजर्व (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
8. Population increase of India- 1/2% की दर से बढ़ रही भारतीय आबादी, चीन से दोगुनी तेज; प्रति महिला 2 से ज्यादा बच्चे (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) .....
9. SC stopped Arcelor Mittal fom making payment in Essar Steel case- एस्सार स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल को भुगतान करने से रोका (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) .....
10. Story of Jet Airways- जानें, बदहाली की कगार पर कैसे पहुंची कभी अरबों डॉलर का मुनाफा कमाने वाली जेट एयरवेज (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Economics).....
11. WTO Negotiations on Agriculture is full of challenges for India- विश्व व्यापार संगठन की चिंता जनक रिपोर्ट, खेती के मोर्चे पर भारत की नई चुनौतियां (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics) .....
12. Airlines closed down operations in 7 years- जेट एयरवेज 7 साल में बंद होने वाली छठी एयरलाइन, 20000 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
13. Present position of Jet airways- जेट एयरवेज का वर्तमान हाल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
14. I lakh crore rupee deposit in Jan dhan accounts- जन धन खातों में जमा रकम की राशी पहुंची एक लाख करोड़ के करीब, इतने रूपे डेबिट कार्ड जारी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
15. एसबीआई इन टच टैप एंड गो डेबिट कार्ड (sbiINTOUCH Tap Go debit card) क्या है? (Relevant for GS Prelims; Economics) .....

16. SEBI restrains Leelaventure from parting with property- होटल लीलावेंचर की प्रॉपर्टी बिक्री पर सेबी ने रोक लगाई, आईटीसी और एलआईसी ने शिकायत की थी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
17. Problems in airline industry- विमानन उद्योग की मुश्किलें (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
18. Increase in Provident fund interest rate- वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दर 8.65% करने को मंजूरी दी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....
19. India notified agreement with US to stop tax evasion by MNCs- मल्टीनेशनल कंपनियों की टैक्स चोरी पकड़ने के लिए भारत ने यूएस के साथ एग्रीमेंट नोटिफाई किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics).....

पर्यावरण एवं जैव विविधता.

1. Earth Day- पृथ्वी दिवस (Relevant for GS Prelims; Environment).....

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी .....

1. Successful launch of Emisat- 'इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटेलीजेंस सेटेलाइट' (एमिसैट) का सफल प्रक्षेपण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology).....
2. America agreed to sell 24 Sea Hawk helicopters to India- अमेरिका ने भारत को 24 सीहॉक हेलिकॉप्टर बेचने को मंजूरी दी (Relevant for GS Prelims; Science & Technology) .....
3. Project-75 aims to build 6 submarines-500 किमी. रेंज वाली मिसाइलों से लैस 6 पनडुब्बियां बनाने का प्रस्ताव, बजट 50 हजार करोड़ रु. (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology).....

4. Maximum Space debris due to America, India has contributed only 1.07%- अमेरिका की वजह से अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा, कुल कचरे का सिर्फ 1.07% भारत का (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) ६
5. South Korea- 1st nation to start 5G- दक्षिण कोरिया कल 5जी सर्विस शुरू करने वाला पहला देश बनेगा, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ेगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology).....६
6. C-DAC to make India's first 64-bit microprocessor- भारत का पहला 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर बनाएगी सी-डैक, 2022 तक तैयार होगा सुपर कम्प्यूटर (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)..... 3
7. First photographs of black hole released- Black Hole की पहली तस्वीर हुई जारी, जानें इससे जुड़े रोचक तथ्य (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)..90
8. First commercial drone delivery service- दुनिया की पहली कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू, 18 महीने ट्रायल के बाद मंजूरी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Tecnology) .....
9. Tik Tok removed from Play store- गूगल ने प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप हटाया, मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology).....
10. Tik Tok removed from Play store- गूगल ने प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप हटाया, मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....
11. Chances of Ban on PUBG- PUBG Mobile Ban: भारत और नेपाल के बाद अब इस देश के लोग भी नहीं खेल पाएंगे यह गेम (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....
12. Mars colony model in Gobi desert- गोबी के रेगिस्तान में बनाया मंगल ग्रह का मॉडल, लोग यहां देख सकेंगे कि लाल ग्रह पर जीवन कैसा होता है (Relevant for GS Prelims; Science & Tecnology) .....

13. Gene editing to treat lung disorders- वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक, जीन में बदलाव करके ठीक किए जाएंगे फेफड़े संबंधी रोग (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....
14. Possible health effects of E-cigarette: ई-सिगरेट पीने वाले हो जाएं सावधान, कैंसर समेत कई रोगों के हो सकते हैं शिकार (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....
15. Removal of Ban on Tik Tok app - आप फिर से बना पाएंगे TikTok, जानें ऐप पर लगे बैन की पूरी कहानी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....
16. What is card cloning- कैसे होती है कार्ड क्लोनिंग, जान लीजिए आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....
17. Payment of small amount without swiping from the card-बिना स्वाइप किए इस कार्ड से हो जाता है छोटी रकम का पेमेंट, जानें कैसे करता है यह काम (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology) .....

सामाजिक मुद्दे.....

1. Hearing in Supreme Court to ban Tik Tok app- सुप्रीम कोर्ट में TikTok ऐप बैन को लेकर सुनवाई (Relevant for GS Mains Paper I; Social Issues) .....
2. Problem of ageing in Japan- जापान में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी बन रही बड़ी चुनौती, 2050 तक 79 फीसद लोग होंगे बूढ़े (Relevant for GS Prelims & Mains Paper- I; Social issues).....
3. Muslim women seeking entry in moque- मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश और नमाज की इजाजत की मांग, कपल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Social Issues) .....

4. By 2020, Aged will constitute 20% of Indian population- 2050 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी बुजुर्गों की संख्या (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Social Issues) .....
5. TikTok App ban in India: जानें अब तक की हर छोटी बड़ी डिटेल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Social Issues) .....

आंतरिक सुरक्षा.....

1. Proect to acquire 6 submarines-नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियां हासिल करने की प्रक्रिया शुरू (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Internal Security).....
2. Raids against ISIS module in Hyderabad and Wardha- भारत में ISIS मॉड्यूल के खिलाफ NIA ने हैदराबाद और महाराष्ट्र के वर्धा में की छापेमारी (Relevnat for GS Mains Paper-III; Internal Security).....

विविध विषय .....

1. Facebook deleted 687 pages associated with Congress- फेसबुक का कड़ा कदम, डिलीट किए कांग्रेस से जुड़े 687 पेज (Read only for understanding).....
2. Nugen Mobility Summit- न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 (Relevant for GS Prelims)..
3. UPSC Civil Services Result 2018: कनिष्क, अक्षत, जुनैद, श्रेयांस और सृष्टि देशमुख हैं टॉपर्स, देखें लिस्ट (केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़े).....
4. Indian Air force presented evidence of shooting down F-16 - वायुसेना ने रडार इमेज जारी कर कहा- पाक के एफ-16 मार गिराने के हमारे पास विश्वसनीय सबूत (Read only for understanding).....
5. HRD ministry released ranking of educational institutions-एचआरडी मिनिस्ट्री ने जारी की देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की लिस्ट, IIT मद्रास टॉप पर (Relevant for GS Prelims).....

6. Highest polling station of the world- विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ऊंचाई है 15256 फुट; मतदाता की संख्या है मात्र 49 (Relevant for GS Prelims) .....
7. Census 2021 will make use of app for data collection- जनगणना 2021 -डाटा इकट्ठा करने में पहली बार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा (Relevant for GS Prelims) .....
8. PM Modi accorded Russia's highest honour- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान, दूतावास ने दी जानकारी (Relevant for GS Prelims) .....
9. France newspaper claim that Anil Ambani firm was given tax relaxation in France- फ्रांस के अखबार का दावा- अनिल अंबानी का 14 करोड़ यूरो का टैक्स माफ हुआ, रिलायंस का इनकार (Read only for understanding) .....
10. Higher income levels in Kasmir in comparison to rest of country- कश्मीरी लोग देश में सबसे समृद्ध, बाकी राज्यों से ज्यादा खर्च करते हैं (Relevant for GS Prelims).....
11. Fire in Nore Dame Church-आग से तबाह फ्रांस की ऐतिहासिक Notre Dame चर्च (Relevant for GS Prelims).....
12. New Japnese emperor- देश को 30 साल बाद मिलेगा नया राजा; अगली पीढ़ी में राज परिवार के पास इकलौता वारिस (Relevant for GS Prelims) .....
13. 3000 kgs of solid garbage cleaned from Mount Everest- माउंट एवरेस्ट से 3 हजार किलो कचरा साफ किया, पर्यावरण दिवस पर दिखाया जाएगा (Relevant for GS Prelims).....

शासन व्यवस्था और प्रणाली

1. Increasing expenditure in Lok Sabha elections- लोकसभा चुनाव में निरंतर बढ़ता बेतहाशा खर्च (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, पर इस ओर शायद ही किसी का ध्यान जाता है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव का आर्थिक लेखा-जोखा क्या है। अनुमान है कि 71 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च लोकसभा चुनाव में होगा। अमेरिका स्थित है एक चुनाव विशेषज्ञ का मानना है कि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के सबसे खर्चीले चुनाव में से 2019 का चुनाव होगा। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार 1996 में लोकसभा चुनाव में 2,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। साल 2009 में यह रकम 10 हजार करोड़ हो गई। हालांकि इसमें वोटरों को गैर-कानूनी तरीके से दी गई रकम भी शामिल है। हर चुनाव में देखा गया है कि राजनीतिक दल चुनाव द्वारा नियम संगत ठहराए गए खर्च से कई गुना अधिक धन व्यय करते हैं। यह चुनाव आयोग भी शायद जानता है। इससे ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता है। फलस्वरूप लोकतंत्र में ऐसे लोग चुने जाने से वंचित रह जाते हैं। यह महज आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की वह असल तस्वीर है जिससे शायद ही कोई अनभिज्ञ हो कि जिस भारत में लोकतंत्र इतना महंगा हो जाए उसी भारत में हर चौथा व्यक्ति अशिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं।

पिछले चार दशक की तुलना में बेरोजगारी सबसे बड़े आंकड़े के साथ बढ़त बनाए हुए है और बेरोजगार युवा कैरियर और लाइफ मैनेजमेंट के मामले में कहीं अधिक फिसड्डी सिद्ध हो रहे हैं। पिछले सात दशकों में लोकसभा के 16 बार हो चुके चुनाव में खर्च तेजी से बढ़त लिए हुए है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भी तुलनात्मक बढ़ोत्तरी व्यापक पैमाने पर हुई है। पहली लोकसभा चुनाव में करीब 10 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1952 से 1971 के बीच पांच लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्च 10.45 करोड़ रुपये से शुरू होकर 11.6 करोड़ रुपये तक ही थे। उसके बाद खर्च में बेतहाशा वृद्धि होने लगी।

वर्ष 1977 के चुनाव में यह खर्च 23 करोड़ था, वहीं तीन साल बाद 1980 में सातवीं लोकसभा के गठन में 54 करोड़ रुपये खर्च हुए। वर्ष 1984 में 81 करोड़ चुनावी खर्च आया, वर्ष 1989 के चुनाव में यह डेढ़ अरब रुपये हो गया। वर्ष 1991 में चुनाव साढ़े तीन अरब का और 1996 का चुनाव छह अरब के साथ दोगुना हो गया। वर्ष 1999 में खर्च नौ अरब रुपये के आस-पास हुआ, जबकि 2004 में कुल चुनावी खर्च 13 अरब रुपये थे। मौजूदा समय में यह चुनावी खर्च देश के एक माह की जीएसटी के आस-पास प्रतीत होता है। चुनाव में होने वाले खर्च में ज्यादातर हिस्सा काले धन का होता है। राजनीतिक दल इस रकम का प्रयोग स्वयं के खर्च में और मतदाताओं को प्रलोभन के रूप में करते हैं। चुनाव प्रचार की सामग्रियों आदि पर भी व्यापक पैमाने पर खर्च किया जाता है।

बेतहाशा खर्च पर क्या रोक संभव है? शायद इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। चुनाव में काले धन की बारिश आम बात है। पारदर्शिता ही इसमें लगाम लगा सकती है और इसका जिम्मा भी इन्हीं राजनीतिक दलों का है जो चुनाव जीतकर व्यवस्थापिका की हैसियत से कानून निर्माता होते हैं। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदा टैक्स के दायरे में नहीं है। यह पता लगाना भी मुश्किल है कि दलों को धन कहां से कितना प्राप्त होता है। कोई भी उम्मीदवार धन-बल के बूते लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगा, ऐसी उम्मीद हर बार जगती है, पर ऐसा होता नहीं है। निर्वाचन आयोग उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर कड़ा पहरा लगाता है, पर सफल कितना है कह पाना कठिन है। चुनाव में उम्मीदवार 70 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता, लेकिन हकीकत यह है कि वे इससे कई गुना अधिक खर्च करते हैं।

पार्टियां सबसे ज्यादा खर्च विज्ञापन और हवाई यात्र पर करती हैं। हैलीकॉप्टर का किराया दो लाख रुपये प्रति घंटा तक है, जबकि हवाई जहाज का किराया साढ़े तीन लाख रुपये तक है। लोकसभा चुनाव में करीब 125 हवाई जहाज और हैलीकॉप्टर के उड़ान की संभावना व्यक्त की गई है और यह डेढ़-दो महीने तक चलता है। मतदाताओं को रिझाने के लिए भी बड़ी तादाद में खर्च किया जाता है। झंडे, बैनर से लेकर रैली के लिए कुर्सी, टेंट आदि खर्च के अलावा कार्यकर्ताओं के खाने-पीने पर लाखों-करोड़ों खर्च किया जाता है जिसमें व्यापक पैमाने पर धन का कोई हिसाब-किताब नहीं मिलता।

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक दल कम, उम्मीदवार अधिक धन खर्च कर रहे हैं। बढ़ता खर्च यह इशारा कर रहा है कि देश में लोकतंत्र को सुसज्जित करने की फिराक में विकासशील भारत को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। वर्ष 1951 के चुनाव में लोकतंत्र को गढ़ने में प्रति वोटर 60 पैसे खर्च आया। वर्ष 2009 में यह 12 रुपये प्रति मतदाता हो गया। वर्ष 2014 में बढ़कर 17 रुपये हो गया। इस वर्ष यह खर्च और बढ़ेगा।
उम्मीदवार चुनाव जीत कर जब संसद पहुंचता है तो उसके बाद भी उस पर देश को अच्छी खासी रकम को खर्च करना होता है। वेतन भत्ता, कार्यालय खर्च, सचिवालयी सहायता के रूप में राशि, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता आदि के अलावा सांसदों को साल भर सीमित हवाई यात्रओं और असीमित रेल यात्र के लिए सरकारी खजाने से धन दिया जाता है। लोकसभा के संचालन में भी प्रति मिनट करीब तीन लाख रुपये का खर्च आता है। चुनाव से लेकर संसद बनने और उसके बाद संसदीय कार्यवाही समेत सभी संदर्भो को जोड़ा जाए, तो देश की एक बड़ी रकम लोकतंत्र को चुनने से लेकर उसे सुसज्जित करने में खर्च हो जाती है। ऐसे में यह जरूरी है कि देश के नागरिकों के मत और उनकी गाढ़ी कमाई से चल रही व्यवस्था में उनका विकास ईमानदारी से देना चाहिए।

लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी का प्रचार कर जनता का समर्थन पाने में जुटे हुए हैं। इस महान लोकतांत्रिक देश में मतदाता अब सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को अपनी अपेक्षा की कसौटी पर कसने लगे हैं। उनके मुद्दों, कार्यो तथा विजन का अवलोकन करने लगे हैं। ऐसे में चुनाव की दिशा बदलना स्वाभाविक है। सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव ऐसे चुनाव के रूप में दर्ज होगा, जब राजनेता वादों की पोटली खोलेंगे तो जनता डिजिटल इंडिया के इस दौर में अपने फोन से उनके इतिहास के वादों का हिसाब किताब टटोलने और उनसे सवाल पूछने से पीछे नहीं हटेगी। प्रत्येक चुनाव के अपने अलग मुद्दे होते हैं जिसके आधार पर चुनाव होता है। उन्हीं मुद्दों में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा आदि शामिल हैं। किंतु अब इन मुद्दों से हटकर समूचा विपक्ष इस बात पर चुनाव लड़ रहा है कि जैसे भी हो नरेंद्र मोदी को हटाना है।

हैरत में डालने वाला यथार्थ यह भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जनता के हित में एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्ष को एक भी ऐसा बड़ा अवसर नहीं दिया? प्रत्येक सरकार की कोई न कोई कमजोरी रहती है और यह स्वाभाविक है कि इतने बड़े देश में सभी किस्म की व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाना आसान नहीं है। यहां सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। यह भी हास्यास्पद है कि जब भी कांग्रेस किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी करती है, उसी मुद्दे पर भाजपा उसके काले अध्याय से उसको आइना दिखा देती है। कुल मिलाकर यह कहना अनुचित नहीं होगा कि इन पांच वर्षो के दौरान विपक्ष अपना मूल स्वभाव भूलकर प्रेस कांफ्रेंस करके अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेता है। एक नागरिक के नाते क्षोभ इस बात का भी है कि इसमें भी विपक्षी दलों के कई बार झूठे दस्तावेजों एवं मनगढंत बातों के सहारे व्यर्थ का विमर्श खड़ा करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है।

सरसरी तौर पर सरकार के कामकाज को देखें तो यह पांच साल एक ऐसी विकास यात्र नजर आएगी जिसमें प्रत्येक वर्ष भारत क्रमबद्ध ढंग से प्रगति के मार्ग पर बढ़ता गया है। केंद्र सरकार की विदेशी नीति से विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। सबसे ताजा उदारहण एयर स्ट्राइक पर किसी भी शक्तिशाली देश ने भारत का विरोध नहीं किया, वहीं पुलवामा आतंकी हमले पर समूचा विश्व हमारे दुख में सहभागी हुआ था। योग को वैश्विक मान्यता मिलना भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गरीबी इस देश की सबसे अधिक संभावनाओं वाला मुद्दा है। चुनाव आते आते राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस द्वारा गरीबी दूर करने की कसमें खाई जाने लगती हैं। पर चुनाव के पश्चात गरीब ठगे हुए महसूस करते हैं, किंतु भाजपानीत केंद्र सरकार ने इस मिथक को तोड़ा है। केंद्र सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया। साथ ही योजनाओं ने जमीन पर अपना असर दिखाया। आज देश के सभी कोने में बिजली पहुंची है। उज्ज्वला योजना के तहत सात करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा चुका है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत करीब 10 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसे सरकार की गरीबी दूर करने की प्रतिबद्धता और सफल क्रियान्वयन की इच्छाशक्ति के तौर पर देखा जाना चाहिए।

दुनिया की एक जानी मानी संस्था ब्रुकिंग्स के फ्यूचर डेवलपमेंट ब्लॉग में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में प्रति मिनट 44 लोग अत्यंत गरीब श्रेणी से बाहर आ रहे हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पहले ही भारत को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बता चुके हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उछाल जैसे कई अभूतपूर्व कार्य इस सरकार के कार्यकाल में संभव हुए हैं। दूसरी तरफ जब भी केंद्र सरकार कोई ऐतिहासिक एवं साहसिक राजनीतिक फैसला लेती है, तो विपक्ष राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर उसका विरोध करता है। कई बार यह विरोध खतरनाक और षडयंत्रकारी ढंग से भी किया गया। उदारहण के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने जिस ढंग से सेना के पराक्रम पर संदेह किया उससे विपक्षी दलों का असली चेहरा भी देश ने देखा। इस चुनाव में सरकार अपनी अभूतपूर्व उपलब्धियों को जोर-शोर से जनता के बीच रख रही है। जनधन योजना, उज्ज्वला, मुद्रा, स्वच्छ भारत आदि नरेंद्र मोदी सरकार की सफल क्रियान्वयन योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है जो जनता के बीच में यह विमर्श खड़ा करने में सहायक हो रहा है कि पांच वर्षो में जिस तरह से असरकारी परिवर्तन इस सरकार के दौरान देखने को मिले हैं, यदि आगे इस सरकार को जनादेश मिलता है तो भारत विकास के मोर्चे पर एक क्षितिज पर विराजमान होगा।

इस चुनाव में मुद्दा बहुत दिलचस्प हो चला है। एनडीए जहां नेतृत्वविहीन विपक्ष और सिद्धांतविहीन महागठबंधन के खिलाफ 60 साल बनाम 60 माह की विकास यात्र को लेकर आगे बढ़ रहा है, वहीं समूचा विपक्ष मोदी हटाओ के सहारे चुनावी मैदान में है।

(Adapted From Jagran)

2. Lokapal not provided staff and office- लोकपाल ने कहा- न तो दफ्तर मिला, न पूरा स्टाफ; 5 सितारा होटल के 12 कमरों में चल रहा काम (Relevant for GS Mains Paper II; Polity & Governance)

जिस लोकपाल के गठन के लिए 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, हजारों लोग झंडे-बैनर लेकर सड़कों पर उतरे, उसी लोकपाल ने जब 8 साल बाद अपना काम शुरू किया तो किसी को पता भी नहीं चला। 23 मार्च को शपथ लेने के 2 हफ्ते बाद लोकपाल और सभी 8 सदस्यों की पहली बैठक हुई। यह बैठक किसी दफ्तर में नहीं बल्कि दिल्ली के पांच सितारा होटल में करनी पड़ी।

क्या कारण है?

कारण- सरकार की तरफ से अब तक लोकपाल और उनके सदस्यों को दफ्तर न मिल पाना है। होटल में लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष से हमारी मुलाकात हुई। पूछा कि लोग लोकपाल को कब, कहां और कैसे शिकायत कर सकेंगे? घोष ने कहा, "अभी हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। होटल में ऑफिस चल रहा है। अभी न हमारे पास आने वाली शिकायतों को निपटाने की कोई तय प्रक्रिया और नियम हैं और न ही स्टाफ हैं। लोकपाल सदस्य सबकुछ तय करने में जुटे हैं। हमें लोकपाल सचिव, जांच निदेशक, अभियोजन निदेशक सहित बाकी स्टाफ मिलने पर काम में और तेजी आएगी।"

हालांकि घोष ने बाकी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक अन्य लोकपाल सदस्य जस्टिस दिलीप बाबासाहेब भोंसले ने बताया कि लोग लोकपाल से कैसे शिकायत करेंगे इसको लेकर हम नियम-कानून बना रहे हैं। शिकायत के प्रारूप पर भी चर्चा जारी है। लेकिन यह प्रारूप तभी लागू होगा जब सरकार इसे नोटिफाई करेगी। इस हिसाब से 26 मई को सरकार बनने के बाद जून में ही कुछ हो सकेगा। लोग ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे।

'5 स्टार होटल में दफ्तर खोलने पर लोकपाल से आपत्ति जताई थी'

पांच सितारा होटल में दफ्तर चलाने को लेकर जस्टिस भोंसले का कहना है कि होटल में दफ्तर पर मैंने आपत्ति जताई थी लेकिन चेयरमैन ने कहा कि अभी विकल्प नहीं है और खाली भी तो नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि फाइवस्टार में दफ्तर दिया जाए? मैं यहां खाना तक नहीं खाता। रोज सिर्फ चाय पीता हूं, बिस्किट तक की डिमांड नहीं की।

यह चर्चा खत्म होतेे ही जस्टिस भोंसले बोले ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकपाल सदस्यों ने हाईकोर्ट जज के दर्जे की मांग की है? हम ऐसा क्यों करेंगे? लोकपाल कानून में धारा-7 दिखाते हुए उन्होंने कहा, "चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के बराबर वेतन, भत्ता व सुविधाएं तो वैसे ही मिलेंगी। ऐसी बातें आने पर दिल दुखता है। हमारा मकसद यह भरोसा दिलाना है कि वाजिब शिकायत लेकर लोकपाल के पास आने वाले लोगों को यहां से न्याय मिलेगा।"

यह चर्चा खत्म होते ही जस्टिस भोंसले बोले ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकपाल सदस्यों ने हाईकोर्ट जज के दर्जे की मांग की है? हम ऐसा क्यों करेंगे? लोकपाल कानून में धारा-7 दिखाते हुए उन्होंने कहा, "चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के बराबर वेतन, भत्ता व सुविधाएं तो वैसे ही मिलेंगी। ऐसी बातें आने पर दिल दुखता है। हमारा मकसद यह भरोसा दिलाना है कि वाजिब शिकायत लेकर लोकपाल के पास आने वाले लोगों को यहां से न्याय मिलेगा।"

किन-किन लोगों की जांच नहीं कर सकेंगे लोकपाल

सुप्रीम कोर्ट जज और डिफेंस के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी लोकपाल जांच के दायरे में आएंगे। शिकायत मिलने पर पीएम, मंत्री व सांसद और ग्रुप ए व बी के अधिकारी, सरकारी बोर्ड, ट्रस्ट, कंपनी व सोसाइटी के सदस्यों के खिलाफ लोकपाल जांच शुरू कर सकेंगे।

आखिरी कमरे के बाहर लोकपाल का नाम

किसी सरकारी साइट पर लोकपाल दफ्तर का पता नहीं है। हमने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से पूछा कि तो पता चला लोकपाल दफ्तर अभी अशोक होटल में है। दूसरे तल पर 12 कमरों में यह दफ्तर है। लंबे गलियारे में दोनों तरफ 6-6 कमरे हैं। शुरुआती 8 कमरों में लोकपाल के ज्यूडिशियल व नॉन-ज्यूडिशियल सदस्यों की नंबर प्लेट लगी है। आखिरी कमरे के बाहर लोकपाल जस्टिस घोष का नाम लिखा हुआ है।

(Adapted from Bhaskar.com)

3. Supreme court allowed release of movie on PM Modi- PM Modi Biopic को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, कांग्रेस की याचिका खारिज (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

सुप्रीम कोर्ट में आज फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' (PM Narendra Modi) को लेकर सुवनाई होगी। अदालत ने याचिकाकर्ता से मामले में प्रमाण पेश कर ये बताने को कहा है कि फिल्म में उन्हें किस बात की आपत्ति है।

सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अमन पंवार से कहा कि पहले वह स्पष्ट करें कि फिल्म मे क्या दिखाया गया है और उन्हें किस बात पर आपत्ति है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया की आप फिल्म देखे बिना कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

यहीं नहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता अमन पंवार की मांग को खारिज करते हुए कहा था कि हम किसी को भी फिल्म की कॉपी देने का निर्देश नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से फिल्म की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म को निर्माता संदीप सिंह 12 अप्रैल को रिलीज करना चाहते थे, लेकिन बाद में रिलीज की तारीख को बदलकर 5 अप्रैल कर दिया गया। लोकसभा चुनाव के पहले फिल्म रिलीज करने को लेकर कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब 11 अप्रैल को रिलीज होने की बात कही जा रही है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अरोप लगाया गया है कि चुनाव से पहले फिल्म को रिलीज करने से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर असर पड़ सकता है।

(Adapted from Jagran.com)

4. Election Commission stopped Modi's Bopic and Namo TV-चुनाव आयोग ने मोदी की बायोपिक और नमो टीवी पर रोक लगाई (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर रोक लगा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने से जुड़ी याचिका रद्द कर दी। इसी के साथ चुनाव आयोग ने नमो टीवी चैनल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। आयोग ने आदेश में कहा कि ऐसी कोई भी प्रचार साम्रगी या पोस्टर जो किसी उम्मीदवार की छवि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए, ऐसे कंटेंट को आचार संहिता के दौरान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए।

आयोग ने कहा, इनमें एनटीआर लक्ष्मी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्यमा सिंहम नाम की फिल्में शामिल हैं। इन्हें रचनात्मक कंटेंट कहा गया। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि इनसे सभी उम्मीदवारों और पार्टियों को बराबरी नहीं मिलेगी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए आचार संहिता के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमा में इन फिल्मों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।

फिल्म के गाने का भाजपा के चुनाव प्रचार में हो रहा इस्तेमाल- याचिकाकर्ता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था- इस फिल्म का एक गाना भाजपा के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो वोटरों को प्रभावित करते हैं। इसमें चौकीदार कैंपेन को भी दिखाया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- दो मिनट के ट्रेलर से तय नहीं किया जा सकता कि यह वोटर्स को प्रभावित कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर छोड़ा था फैसला

शीर्ष अदालत ने कहा था- सेंसर बोर्ड ने अब तक इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया है। फिल्म देखना उसका काम है। अगर इससे लोकसभा चुनाव में कोई दिक्कत है, तो चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा। पहले इस फिल्म की रिलीज 5 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन विवाद के बाद इसे 11 तारीख तक बढ़ा दिया गया था। इस फिल्म में विवेक ओबेराय ने मोदी का किरदार निभाया है।

5. Supreme Court asked the centre to make plan for cracker ban- पटाखा बैन : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पटाखों के लिए प्लान बनाने को कहा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 15 मई तक हरित पटाखों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों के संबंध में योजना बनाने को कहा है।

पूरे भारत में पटाखों की ब्रिकी को बैन करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से योजना देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 15 मई तक हरित पटाखों में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों के संबंध में योजना बनाने को कहा है। फिलहाल, दिल्ली में प्रदूषण के चलते पटाखों की ब्रिकी को बैन किया जा चुका है।

पूरे भारत में बैन को मना कर चुका है कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मार्च में इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि पूरे देश में पटाखों को बैन करने के लिए समान मापदंड लागू नहीं हो सकते। कोर्च ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पटाखे ही प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं हैं। कार और ऑटोमोबाइल्स कहीं अधिक मात्रा में वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वहीं, कोर्ट ने इसको लेकर रोजगार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम श्रमिकों को भूखा नहीं छोड़ सकते हैं।

पूरी तरह से बैन लगाने से मना कर चुकी है कोर्ट

पटाखों पर पिछले साल दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से बैन लगाने से मना कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में कहा था कि पटाखों को केवल लाइसेंस पाए व्यवसायी ही बेच सकते हैं। मालूम हो कि वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

(Adapted from Jagran.com)

6. Sufficient VVPAT slips to give credibility to election- पर्याप्त वीवीपैट पर्चियों के मिलान से ही बढ़ेगी ईवीएम की विश्वसनीयता (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

चुनाव आयोग वीवीपैट से निकली ज्यादा से ज्यादा पर्चियों का ईवीएम में पड़े वोटों से मिलान करके ही मतदाताओं की नजर में विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों की इस मांग का चुनाव आयोग विरोध क्यों कर रहा है? अभी आयोग हर असेंबली में केवल एक बूथ में पड़े मतों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करने पर राजी है। यह संख्या कुल ईवीएम का एक फीसदी भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उप चुनाव आयुक्त से जोर देकर आग्रह किया कि आयोग को संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, ताकि शुद्धता और विश्वसनीयता बढ़े।

जब उप चुनाव आयुक्त ने तर्क दिया कि पर्चियों से मिलान के लिए संख्या बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए। तब उन्होंने यह याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के जोर देने पर 2013 में वीवीपैट की शुरुआत हुई। 2014 के चुनाव में 60 फीसदी से अधिक वोट पाने वाली इन पार्टियों की अपील का आयोग की ओर से विरोध करना समझ से परे

है। सत्ताधारी दल का इस प्रस्ताव का समर्थन न करना और भी चौंकाने वाला है। विपक्षी दल चाहते हैं कि कम से कम 50 फीसदी मतदान केंद्रों पर पर्चियों और ईवीएम में पड़े वोटों का मिलान हो। यह काफी बड़ी संख्या है, लेकिन रैंडम तौर पर 20 से 30 फीसदी बूथों पर सहमति का फार्मूला निकाला जा सकता है। प्रक्रिया की वजह से परिणाम में 48 घंटे की देरी भी होती है तो कोई नुकसान नहीं है।

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर रहे प्रत्याशी को पर्चियों के मिलान के लिए उसकी मर्जी से बूथ चुनने की अनुमति दे दी जाए। जैसे कि क्रिकेट में थर्ड अंपायर के पास फैसला भेजा जाता है। दलों को इसके लिए निश्चित मौके तय कर दिए जाने चाहिए।

चुनाव आयोग को विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की बजाय अपना ही कोई समाधान पेश करना चाहिए। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की बात हो तो संवैधानिक संस्थाओं के बीच किसी तरह का अहम आड़े नहीं आना चाहिए। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनमें गड़बड़ी नहीं की जा सकती। इस बारे में दोनों ही तरह के विचार हैं। सांख्यिकीय तौर पर यह साबित हो चुका है कि पांच फीसदी मशीनों में गड़बड़ी आ जाती है और इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोगों ने विदेश में निजी कंपनी द्वारा डिजाइन होने वाली ईवीएम चिप में पारदर्शिता को लेकर भी संदेह व्यक्त किया है।

आयोग ने संदेहों को दूर करने के लिए आईआईटी जैसे संस्थानों के टॉप एक्सपर्ट का पैनल बनाकर इसके तकनीकी पैरामीटर की भी जांच कराई थी। इस पर बहस हो चुकी हैं कि लेकिन संदेह दूर नहीं हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जर्मनी और अमेरिका जैसे देश बैलेट पेपर पर लौट गए हैं। यह इसलिए संभव हुआ कि इन देशों में सोसायटी के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अहम है।

भारत में भी इस तरह की बहस तो चल रही है पर कोई समाधान दिखाई नहीं देता। फिलहाल तो चुनाव आयोग को पूर्ण पारदर्शिता के लिए वीवीपैट सत्यापन के सैंपल साइज को बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि कोई भी संस्थान कितना भी ऊंचा क्यों न हो उसे खुद में सुधार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम इतने संदेह और अविश्वास के साथ 2019 के चुनावों में जाना मंजूर नहीं कर सकते।

7. Electoral Bond: क्या होता है चुनावी बॉन्ड (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी दल, जिनको चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के जरिए चंदा मिला है वो सील कवर में चुनाव आयोग को ब्योरा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond) के जरिये मिली रकम की जानकारी सील कवर में चुनाव आयोग के साथ साझा करें। कोर्ट ने जानकारी साझा करने के लिए 30 मई की समय-सीमा निर्धारित की है और कहा है कि पार्टियां प्रत्येक दानदाता का ब्योरा सौंपे। चुनाव आयोग इसे सेफ कस्टडी में रखेगा।

क्या है चुनावी बॉन्ड (Electoral Bond)

चुनावों में राजनीतिक दलों के चंदा जुटाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक करेंसी नोट लिखा रहता है, जिसमें उसकी वैल्यू होती है। ये बॉन्ड पैसा दान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बॉन्ड के जरिए आम आदमी राजनीतिक पार्टी, व्यक्ति या किसी संस्था को पैसे दान कर सकता है। इसकी न्यूनतम कीमत एक हजार रुपए जबकि अधिकतम एक करोड़ रुपए होती है। चुनावी बॉन्ड 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपये के मूल्य में उपलब्ध हैं।

जानिए खास बातें।।।

* कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था या फिर कंपनी चुनावी बॉन्ड को खरीद सकती है।
* बॉन्ड खरीदने के लिए KYC फॉर्म भरना होगा।
* जिसने बॉन्ड दिया है उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। खरीदने वाले का भी नाम गुप्त रहेगा, लेकिन बैंक खाते की जानकारी रहेगी।
* चुनावी बॉन्ड की अवधी 15 दिन के लिए होगी। जिसमें राजनीतिक दलों को दान किया जा सकेगा।
* हर पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव आयोग को बताना होगा कि बॉन्ड के जरिए उनके कितनी राशी मिली है।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

8. Need to publish Supreme Court rules in English- सुप्रीम कोर्ट नियमावली हिन्दी में प्रकाशित कराने का अनुरोध, मुख्य न्यायाधीश से आग्रह (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

हिन्दी भाषा जानने वाली आम जनता को सुप्रीम कोर्ट के नियम कानूनों की जानकारी हो और वे लोग अपने कानूनी हक के बारे में सरलता से जान सकें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नियमावली हिन्दी में प्रकाशित कराने की मांग की गई है। दिल्ली निवासी हरपाल सिंह राणा ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि आम जनता की सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 का हिन्दी में प्रकाशन कराया जाए। अभी यह नियमावली सुप्रीम कोर्ट रूल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

राणा ने पहले इस बाबत सुप्रीम कोर्ट मे एक रिट याचिका दाखिल कर अपनी मांग रखी थी। याचिका 2017 में दाखिल की गई थी लेकिन गत फरवरी में इस याचिका को चैम्बर में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने यह कहते हुए निपटा दिया कि यह मसला प्रशासनिक है। इस याचिका पर कोर्ट में न्यायिक छोर पर सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता चाहे तो अपनी मांग प्रशासनिक स्तर पर रख सकता है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका निपटने के बाद राणा ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया है कि वह देश हित में इस पर विचार करें।

मुख्य न्यायाधीश से किये गए आग्रह में राणा ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत का संविधान सहित महत्वपूर्ण नियम कानून का अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी प्रकाशन कराया जाता है उसी प्रकार उच्चतम न्यायालय की नियमावली 2013 का हिन्दी में प्रकाशन कराया जाए। उच्चतम न्यायालय नियमावली का हिन्दी मे प्रकाशन न होने के कारण जिन लोगों को अंग्रेजी की जानकारी नहीं है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के नियमों और अपने हकों का सही से ज्ञान नहीं हो पा रहा है। नियमावली का हिन्दी में प्रकाशन होने से देश के नागरिक अपने अधिकार के लिए इसका सरलता से उपयोग कर सकेंगे।

(Adapted from Jagran.com)

9. EC order to BJP, don't broadcast NaMo TV without approval- चुनाव आयोग का भाजपा को निर्देश, बिना प्रमाणन न करें नमो टीवी पर कोई प्रसारण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Electoral Officer) की ओर से भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित किया गया है वह बिना प्रमाणन नमो टीवी (NaMo TV) पर किसी तरह का कोई भी प्रसारण नहीं करे। मिली जानकारी के मुताबिक, नमो टीवी पर दिखाए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को बिना प्रमाणन के नहीं दिखाए जाने के चुनाव आयोग के निर्देश के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने उसकी मंजूरी के बिना भाजपा को इस चैनल पर कोई कार्यक्रम नहीं प्रसारित करने का यह निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि सीईओ ने एक दिन पहले बृहस्पतिवार को कहा था कि नमो टीवी भाजपा चला रही है, इसलिए इस पर प्रसारित किए जाने वाले सभी रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को मीडिया प्रमाणन और दिल्ली के निगरानी समिति द्वारा पूर्व प्रमाणित किया जाना चाहिए और पूर्व-प्रमाणन के बिना प्रदर्शित सभी राजनीतिक प्रचार सामग्री को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए।

इतना ही नहीं, चुनाव आयोग (Election Commission) के दिशा-निर्देश के बाद दिल्ली के सीईओ ने भाजपा को पत्र लिख कर बिना मंजूरी वाली सभी राजनीतिक सामग्री हटाने के लिए कहा है। आयोग ने यह भी कहा कि प्रचार के लिए बिना पूर्व नमो टीवी पर इजाजत प्रसारित की जा रही राजनीतिक सामग्री को तुरंत हटा लेना चाहिए। नमो टीवी पर किसी भी राजनीतिक सामग्री को दिखाए जाने के लिए हर हाल में चुनाव आयोग के नियमों का पालन होगा। गौरतलब है कि भाजपा ने हाल ही में नमो टीवी लॉन्च किया था।

(Adapted from Jagran.com)

10. Lateral entry at Joint Secreatry level - प्राइवेट सेक्टर के इन लोगों को सरकार ने सीधे बनाया ज्वाइंट सेक्रेटरी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अलग-अलग फील्ड के नौ विशेषज्ञ पेशेवरों को संयुक्त सचिव बनाकर सरकारी सेवा में लेटरल प्रवेश प्रक्रिया (Lateral Entry Process) के जरिए सीधा प्रवेश दिया है। इनमें से ज्यादातर विशेषज्ञ प्राइवेट सेक्टर से हैं और देश में अपने क्षेत्र के धुरंधर माने जाते हैं। इन्हें अलग-अलग विभागों में संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। सरकार का ये कदम, महत्वपूर्ण नीतियों को मूर्त रूप देने के लिए पेशेवरों की प्रवेश प्रक्रिया में एक प्रमुख बदलाव की तरफ इशारा करता है।

बताया जा रहा है कि लेटरल प्रवेश प्रक्रिया के जरिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अलग-अलग मामलों के विशेषज्ञ सरकार में शामिल होंगे। मालूम हो कि सरकार में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। इस पद पर ज्यादातर उन्हीं अधिकारियों को तैनात किया जाता है जो यूपीएससी की सिविल परीक्षा से चयनित होकर आते हैं और जिन्हें संबंधित फील्ड में काम करने का लंबा अनुभव व अच्छा ज्ञान हो।

हाल में भी कुछ विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के जरिए वित्त, ऊर्जा व स्वच्छता मंत्रालयों में तैनात किया गया था। सरकार में शामिल होने वाले इन पेशेवरों में मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमला जालान, विजय केलकर (पूर्व पेट्रोलियम व वित्त सचिव), आरवी शाही (पूर्व ऊर्जा सचिव) इनके अलावा मौजूदा स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर और आयुष मंत्रालय के प्रमुख राजेश कोटेचा शामिल हैं। यूपीएससी ने शुक्रवार को सरकार में शामिल होने जा रहे विशेषज्ञों की पूरी सूची जारी की है। इन विशेषज्ञों को कृषि, नागरिक उड्डयन, वित्त, परिवहन और शिपिंग विभागों में अनुबंध के तहत तैनात किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा तैनात किए जाने वाले विशेषज्ञों में अंबर दुबे, बहुराष्ट्रीय कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी के साथ जुड़े हुए हैं। केपीएमजी में वह एयरोस्पेस और डिफेंस के प्रमुख हैं। सरकार द्वारा उन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में तैनात किया जाएगा। अंबर दुबे ने आइआइटी बॉम्बे व आइआइएम अहमदाबाद से पढ़ाई की है और उन्हें 26 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है।

दूसरी विशेषज्ञ काकोली घोष है, जो फिलहाल कृषि के अलग-अलग क्षेत्र के लिए काम करने वाली एजेंसी से जुड़ी हुई हैं। उन्हें उनके अनुभव के अनुसार कृषि मंत्रालय में तैनात किया जाएगा। तीसरे विशेषज्ञ हैं सुजित कुमार बाजपेयी, जो कि राज्य द्वारा संचालित NHPC में कार्यरत हैं, उन्हें पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया जाना है। पनामा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप के सीईओ दिनेश दयानंद जगदले, न्यू और रिन्यूबल ऊर्जा मंत्रालय में तैनात किए जाएंगे।

सौरभ मिश्रा को वित्तीय सेवा विभाग में संयुक्त सचिव, राजीव सक्सेना आर्थिक मामलों के विभाग में तैनात किए जाएंगे। अरुण गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, सुमन प्रसाद सिंह को सड़क परिवहन मंत्रालय और भूषण कुमार को शिपिंग मंत्रालय में तैनात करने के लिए चुना गया है।

केंद्र सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये पहली बार है कि प्राइवेट सेक्टर से इतनी बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को सरकारी विभागों महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जा रहा है। सबसे बेहतर चीज ये है कि विशेषज्ञों के चयन की पूरी प्रक्रिया यूपीएससी ने की है। चुने गए विशेषज्ञ, केंद्र सरकार के नियमों व शर्तों के तहत संबंधित विभागों में अपनी सेवा देंगे। इसके लिए उन्हें संचुक्त सचिव स्तर की तनख्वाह और सुविधाएं दी जाएंगी। मालूम हो कि सरकार नीति आयोग ने सरकारी विभागों के उच्च पदों पर विभिन्न फील्ड के विशेषज्ञों को तैनात करने के लिए लेटरल एंट्री को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी। नीति आयोग ने इस प्रयोग को सरकारी नीतियों को सही दिशा देने के लिए बेहद जरूरी बताया है।

(Adapted from Jagran.com)

11. SC has not stayed ban on Tik tok app- सुप्रीम कोर्ट में टिकटॉक को नहीं मिली राहत, ऐप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा टिकटॉक एप पर प्रतिबंध के लिए केंद्र सरकार को दिए गए आदेश पर रोक से इन्कार कर दिया। एप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का प्रतिबंध सिर्फ अंतरिम आदेश है। वहां इस मुद्दे पर मंगलवार (16 अप्रैल) को सुनवाई प्रस्तावित है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि अब इस मामले पर 22 अप्रैल को विचार किया जाएगा। चीनी कंपनी बाइटडांस की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि करोड़ों लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने एकपक्षीय आदेश दिया है। यहां तक कि नोटिस भी नहीं जारी किया गया।

इस पर पीठ ने कहा, 'हम इस मामले को खत्म कर रहे हैं। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने दें।' उल्लेखनीय है कि तीन अप्रैल को हाई कोर्ट ने टिकटॉक एप पर अश्लील तथा आपत्तिजनक सामग्री परोसे जाने की शिकायत की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

(Adapted from Jagran.com)

12. Legal proceedings against ex-president Bashir-सूडान में चलेगा पूर्व राष्ट्रपति बशीर पर मुकदमा, मिलेगी मौत या होगा देश निकाला! (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

तीन दशकों तक सूडान की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति उमर अल बशीर का तख्तापलट होने के बाद उन्हें कहां रखा गया है ये कोई नहीं जानता है। दरअसल, बशीर के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) ने दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें पहला गिरफ्तारी वारंट 4 मार्च 2009 और दूसरा 12 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। उनपर हत्या, जबरन विस्थापन, प्रताड़ना और बलात्कार के आरोप हैं। उन पर युद्ध अपराध के भी दो आरोप हैं। कोर्ट चाहता है कि बशीर को उनके हवाले किया जाए जिससे उनपर मुकदमे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सूडान की अंतरिम सैन्य काउंसिल ने आईसीसी की इस मांग को ठुकरा कर साफ कर दिया है कि बशीर पर सूडान के कानून के हिसाब से ही मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा भी वहीं सुनाई जाएगी।

सैन्य काउंसिल के पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमेन लेफ्टिनेंट जनरल उमर जाइन अब अब्दीन का कहना है कि यदि बशीर को आईसीसी को सौंपा जाता है तो देश की बड़ी बदनामी हो जाएगी, लिहाजा ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा। यही वजह है कि बशीर को तख्तापलट के तुरंत बाद किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है, जिसकी जानकारी कुछ खास लोगों के अलावा अन्य किसी

के पास नहीं है। लेकिन इन सभी के बीच यह बड़ा सवाल है कि आखिर बशीर को सजा ए मौत मिलेगी या फिर पूर्व प्रधानमंत्री की तरह ही उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। बहरहाल, इसका जवाब समय आने पर मिल जाएगा। लेकिन, फिलहाल सैन्य कांउसिल ने देश में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अमेरिका समेत दूसरे देशों में मौजूद अपने राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि तीन दशकों तक सूडान पर राज करने वाले बशीर भी कभी अपने शासक का तख्तापलट कर सत्ता में आए थे। वो 30 जून 1989 का दिन था जब सूडानी सेना के कर्नल उमर अल बशीर ने कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ मिल कर प्रधानमंत्री सादिक अल-महदी का तख्तापलट कर सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था। महदी को देश निकाला दे दिया गया था। इतना ही नहीं उन्होंने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को भंग कर दिया और शरिया कानून लागू कर दिया था। बशीर ने सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया और महदी के विश्वासपात्रों को बशीर ने मौत की सजा सुनाई। कई नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। 1993 में उन्होंने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया।

वर्ष 2000 में महदी स्वदेश वापस लौटे और 2014 के चुनाव में खड़े भी हुए। 2014 में महदी को बशीर का तख्तापलट करने के आरोपों के चलते फिर देश निकाला दिया गया था। इसके बाद वह जनवरी 2017 में दोबारा वापस लौट आए थे। बशीर ने कभी नहीं सोचा होगा उनका हश्र भी ऐसा ही होगा और उन्हें भी ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा। सत्ता में रहते हुए दारफूर में 2003-2008 उन्होंने संगठित हथियारबंद गुटों को खत्म करने के नाम पर कई लोगों को निशाना बनाया था। आरोप तो यहां तक है कि उन्होंने इसकी आड़ में सूडानीज लिबरेशन मूवमेंट और जस्टिस एंड इक्वलिटी मूवमेंट के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के दौरान फूर, मसालित और जाघावा समुदायों के खात्मे के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। इस दौरान करीब 3 लाख लोग मारे गए थे।

आपको बता दें कि बशीर के तख्तापलट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और नार्वे ने सूडान में नागरिक शासन की वकालत करते हुए सैन्य शासकों से इसकी पहल की अपील की है। तीनों देशों ने संयुक्त रूप से वार्ता शुरू करने के लिए यहां के सैन्य शासन से आग्रह किया है। तीनों देशों ने कहा है कि सूडान की नई सत्तारूढ़ सैन्य परिषद ने एक निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांरित करने का वादा किया है। सैन्य काउंसिल की पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन अल-अब्दीन ने कहा है कि वह ताकत के भूखे नहीं हैं। सैन्य काउंसिल का कहना है कि दो साल के भीतर नागरिक सरकार को सभी अधिकार दे दिए जाएंगे। इतना ही नहीं सरकार बनने के बाद सेना सरकार के काम में कोई में दखल नहीं देगी। हालांकि इसमें ये भी कहा गया है कि रक्षा और आतंरिक मंत्रालय सैन्य काउंसिल के अधीन ही रहेंगे। हालांकि तख्तापलट के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, इसमें अब तक करीब 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बशीर को हटाने के बाद जिनके हाथों में सत्ता सौंपी गई थी उन्होंने (जनरल अवद इब्ने ऑफ) ने भी इस्तीफा दे दिया था।

(Adapted from Jagran.com)

13. Election Commission against leaders- चार नेताओं पर चुनाव आयोग कार्रवाई (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

नेताओं के आपत्तिजनक भाषणों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संतुष्टि जताई। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि लगता है, चुनाव आयोग को उनकी शक्तियां वापस मिल गई हैं। ऐसी स्थिति में कोर्ट को किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं। आज कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। इससे पहले सोमवार को कार्रवाई में देरी को लेकर कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई थी।

शीर्ष अदालत शारजाह (यूएई) की एक एनआरआई योगा टीचर मनसुखानी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई थी, जो चुनाव के दौरान जाति-धर्म के आधार पर टिप्पणियां कर रहे हैं। अदालत ने 8 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था।

आयोग ने कहा था- कार्रवाई के मामले में शक्तिहीन हैं

सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने जब उत्तरप्रदेश में नेताओं द्वारा धार्मिक और विवादित बयान दिए जाने पर आयोग से कार्रवाई के बारे में पूछा तो आयोग ने कहा कि हम ऐसे मामलों में सिर्फ नोटिस भेजकर जवाब मांग सकते हैं। इस पर नाराज बेंच ने कहा कि वास्तव में आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप शक्तिहीन हैं।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आयोग ने की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा प्रमुख मायावती पर 48 और 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने की रोक लगाई थी। कुछ घंटे बाद ही आयोग ने भाजपा नेता मेनका गांधी और सपा नेता आजम खान पर भी 48 और 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अपील खारिज की

बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रचार पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उनके वकील ने कहा कि आयोग ने मायावती का पक्ष सुने बगैर एकतरफा कार्रवाई की है। यह आदेश रद्द किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में कोई आदेश दिया जाना चाहिए।

(Adapted from Bhaskar.com)

14. Lack of office allocation to Lokpal- देश का पहला लोकपाल दफ्तर दिल्ली के एक पांच सितारा होटल से काम करेगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

देश का पहला लोकपाल दफ्तर दिल्ली के एक पांच सितारा होटल से काम करेगा। लोकपाल अध्यक्ष और इसके सभी आठ सदस्यों और सहायक कर्मचारियों को होटल परिसर में जगह आवंटित की जा रही है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

उन्होंने कहा कि लोकपाल का कार्यालय चाणक्यपुरी स्थित द अशोक होटल से काम करेगा। हालांकि यह उसका अस्थायी कार्यालय होगा। बता दें कि 23 मार्च को राष्ट्रपति कोविंद ने देश के पहले लोकपाल अध्यक्ष के तौर पर पूर्व जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को शपथ दिलाई थी जबकि लोकपाल के आठ सदस्यों को पूर्व जस्टिस घोष ने 27 मार्च को शपथ दिलाई थी।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्यों के रूप में शपथ ली थी जबकि सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला प्रमुख अर्चना रामासुंदरम, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, पूर्व आइएएस अधिकारी महेंद्र सिंह और गुजरात कैडर के पूर्व आइएएस अधिकारी इंद्रजीत प्रसाद गौतम ने लोकपाल के गैर-न्यायिक सदस्यों के रूप में शपथ ली थी।

(Adapted from Jagran.com)

15. Supreme Court ने RBI को दिया लास्ट चांस, कहा-RTI के तहत करे बैंकों की जांच रिपोर्ट का खुलासा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को यह निर्देश दिया कि वह) सूचना के अधिकार (RTI) के तहत बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट और विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची का खुलासा करे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई से कहा कि वह उन सभी सूचनाओं का खुलासा करे जिनकी इजाजत कानून देता है। साथ ही नॉन-डिसक्लोजर पॉलिसी को वापस लेने की बात भी कही।

जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ ने आरबीआई से यह भी कहा कि वह आरटीआई कानून के तहत सूचना देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि आरबीआई की नॉन-डिस्क्लोजर पॉलिसी उसके 2015 के फैसले का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट- किया वह पारदर्शिता के नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आरबीआई को अंतिम अवसर दे रहा है। साथ ही यह भी कहा कि अगर भविष्य में इसका उल्लंघन होता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को अंतिम अवसर दिया है कि वह आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा मांगी गई जानकारियों जो बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट और अन्य मुद्दों से जुड़ी हैं, उस पर अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इस साल जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना जांच रिपोर्ट का खुलासा न करने को लेकर आरबीआई को कंटेम्ट नोटिस जारी किया था।

अंतरराष्ट्रीय संगठन

1. UAE awarded Zayed medal to PM Modi- मोदी को मिलेगा जायेद मेडल, राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला यहां का सबसे बड़ा सम्मान (Relevant for GS Prelims; IOBR)

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायेद अल नहयन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित करेंगे। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और सेना के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायेद ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। जायेद मेडल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। मोदी ने नहयन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भविष्य में हमारे रिश्तों को नई ऊंचाई मिलेगी।

मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच दोस्ती और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। मोदी से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, सऊदी अरब के किंग सलमान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी यह सम्मान मिल चुका है।

दोनों देशों के मजबूत संबंधों में मोदी का योगदान

शेख मोहम्मद ने ट्वीट में कहा, "दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने और अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग के नए आयाम बनाने के लिए हम अपने दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायेद मेडल देकर अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं।" उन्होंने भारतीय समाज की विविधता, सहिष्णुता, सह-अस्तित्व और सम्मान की संस्कृति की भी तारीफ की।

मोदी को इस साल मिले दो बड़े सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी साल फरवरी में दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मोदी यह पुरस्कार पाने वाले 14वें व्यक्ति थे। 1988 में सियोल ओलिंपिक के सफल आयोजन के बाद यह पुरस्कार शुरू किया गया था। हालांकि, मोदी ने पुरस्कार में मिली 1.30 करोड़ की रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दे दी थी। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मोदी को इसी साल संयुक्त राष्ट्र का चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नई दिल्ली में मोदी को इस सम्मान से नवाजा था।

(Adapted from Bhaskar.com)

2. Ausindex- ऑसिन्डेक्स -19 में भाग लेने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के पोत और पनडुब्बी विशाखापत्तनम पहुंचे (Relevant for GS Prelims; IOBR)

2 अप्रैल से 14 अप्रैल, 2019 तक चलने वाले ऑसिन्डेक्स के तीसरे संस्करण में एएसडब्ल्यू पर केन्द्रित तीनों आयामों वाले अभ्यास शामिल किये जाएंगे और इनका आयोजन विशाखापत्तनम किया जाएगा।

(Adapted from PIB)

3. Poor economic condition of Pakistan-पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था पहले ही दुनिया से छिपी नहीं है। लंबे समय से भीषण महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान, अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। ये सनसनीखेज खुलासा खुद पाकिस्तान के वित्तमंत्री असद उमर ने मीडिया में दिए अपने एक बयान के जरिए किया है। उनका बयान पाकिस्तान के भविष्य के लिए भी चिंताजनक है।

भारत-पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में बनी तनाव की स्थिति में पाक ने हमेशा भारत का मुकाबला करने का दंभ भरा। इसके विपरीत उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि युद्ध करना तो दूर, उसके लिए देश चलाना ही मुश्किल हो चुका है। पाक वित्तमंत्री के बयान से पता चलता है कि पाकिस्तान का अगले कुछ सालों में इस स्थिति से उबर पाना बहुत मुश्किल है। पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद पाक समर्थित आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की कूटनीति ने उसे और मुश्किल में डाल दिया है। यही वजह है कि हाल के तनाव के दौर में पाकिस्तान, भारत संग शांतिवार्ता का राग अलापने लगा था।

जियो टीवी के अनुसार, पाक वित्तमंत्री असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान का मूल्य ऋण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर चला गया है कि मुल्क कभी भी दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तानी वित्तमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया के साथ देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में सवाल-जवाब के विशेष सत्र में यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम भारी कर्ज के साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास जा रहे हैं। हमें अर्थव्यवस्था और कर्ज के भारी अंतर को कम करना होगा।

पाक वित्तमंत्री के अनुसार, अगर हम पीएमएलएन समय के नंबर को देखें तो उस वक्त महंगाई दहाई अंक में थी। राहत की बात है कि महंगाई अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। पूर्व की भांति महंगाई ने अभी दहाई का आंकड़ा नहीं छुआ है। पहले महंगाई ने समाज के हर तबके को परेशान किया था। पहले महंगाई ने गरीबों को ज्यादा प्रभावित किया था। मौजूदा सरकार में महंगाई की स्थिति थोड़ी भिन्न है। अभी गरीबों की तुलना में अमीरों पर महंगाई का असर काफी ज्यादा है। गरीब तबके पर महंगाई की उतनी मार नहीं पड़ी है।

असद उमर ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। इस वजह से देश में रोजगार की दर भी घटी है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इस दौरान पाकिस्तानी वित्तमंत्री ने मीडिया से कहा 'आप कह रहे हैं कि मेरी सारी नीतियां पूर्व वित्तमंत्री इशाक डार की तरह हैं। वहीं इशाक डार का कहना है कि मैंने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। वास्तविकता ये है कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान में पहली बार निर्यात नहीं बढ़ा। पहले की आर्थिक नीतियों की वजह से ही डॉलर लगातार मजबूत होता गया। इस वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा।'

एडीबी ने दिखाया पाकिस्तान को आईना

पाकिस्तान की खस्ताहालत को लेकर एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भी आईना दिखाया है। एडीबी ने पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए बताया है कि बीते वित्त वर्ष में पाकिस्तान की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत थी जो चालू वित्त वर्ष 2019-20 में गिरकर 3.9 फीसद ही रहने का अनुमान है। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है।

पांच वर्ष के उच्चतम स्तर पर महंगाई

पाकिस्तान में मार्च-2019 के दौरान महंगाई दर पांच वर्ष के उच्चतम स्तर पर रही है। पाकिस्तान में महंगाई दर 9.41 फीसद तक पहुंच चुकी है, जो नवंबर-2013 के बाद से सबसे अधिक है। अप्रैल-2019 में महंगाई दर ने 1.42 फीसद की और छलांग लगाई है। पाकिस्तान के सांख्यिकी ब्यूरो ने सोमवार को बयान जारी कर बताया था कि महंगाई दर बढ़ने से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 40 लाख और बढ़ गई है। ये भी आशंका जताई है कि महंगाई और बदहाल अर्थव्यवस्था की वजह से इस वर्ष 10 लाख और लोगों की नौकरियां छिन सकती हैं। सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, आर्थिक विकास की गति तीन फीसद नीचे रहने से पाकिस्तान मुद्रास्फीति जनित मंदी के जाल में फंस चुका है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और आर्थिक विकास धीमा पड़ रहा है।

ब्याज दरों में 50 फीसद का इजाफा

पाकिस्तान में खाने-पीने के सामान की कीमतों में वृद्धि के साथ ईंधन और परिवहन लागत में हुआ इजाफा पाकिस्तानी नागरिकों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। महंगाई को काबू में करने के लिए पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 50 फीसद का इजाफा करते हुए इसे 10.75 फीसद कर दिया है, जिसकी वजह से आर्थिक गतिविधियां और प्रभावित हुई है। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अस्थिर होते आर्थिक हालत की वजह से कुछ कंपनियों ने अपना कारोबार समेटने का भी फैसला ले लिया है। वहीं, आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को बढ़ते राजकोषीय घाटे और चालू खाता घाटे का भी सामना करना पड़ रहा है।

रुपये की खस्ता हालत, 100 रुपये बिक रहा पेट्रोल

पाकिस्तान में रुपये की कमजोर हालत की वजह से ईंधन की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार की वृद्धि के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत करीब 100 रुपये हो चुकी है। गौरतलब है कि पिछले एक साल में पाकिस्तानी करेंसी रुपये में करीब 25 फीसद से अधिक की गिरावट आई है। बुधवार की कीमत के मुताबिक एक डॉलर की कीमत करीब 141 रुपये है।

बेल आउट पैकेज की कोशिश में पाक

अर्थव्यवस्था को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट की मांग कर रही है। अगर आईएमएफ से पाकिस्तान को राहत मिलती है, तो 1980 के बाद से यह तेरहवां बेल आउट पैकेज होगा। गौरतलब है कि इमरान खान सऊदी अरब, यूएई और चीन से 8 अरब डॉलर का कर्ज लेने में सफल रहे हैं। इसके अलावा रियाद और यूएई के 3-3 अरब डॉलर के कर्ज के भुगतान में भी उन्हें राहत मिली है।

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी डर

आतंकवाद के मामले में वैश्विक स्तर पर घिरे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी डर सता रहा है। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि भारत की पैरवी के चलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) उनके मुल्क को काली सूची में डाल सकता है। भारत इसके लिए लॉबिंग कर रहा है। पाकिस्तान को अगर ग्रे लिस्ट यानी निगरानी सूची में भी कायम रखा जाता है तो देश को सालाना दस अरब डॉलर (करीब 69 हजार करोड़ रुपये) का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। मालूम हो कि 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस हमले की पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद ने जिम्मेदारी ली थी।

(Adapted from Jagran.com)

4. 360 prisoners to be released from Pakistan-360 भारतीय कैदियों को सोमवार से रिहा करेगा पाकिस्तान (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पाकिस्तान ने मानवीय आधार पर सोमवार से उन 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। पाकिस्तानी सरकार के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैजल के बयान के हवाले से रेडिया पाकिस्तान ने यह जानकारी दी है।

डॉ. फैजल ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं को बताया कि अगले मंगलवार को पहले 100 भारतीय कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसके बाद 15 अप्रैल को भारतीय कैदियों के दूसरे बैच को रिहा किया जाएगा। 22 अप्रैल को 100 और भारतीय कैदी रिहा किए जाएंगे। फैजल के मुताबिक, पाकिस्तान की जेलों में 537 भारतीय कैदी बंद हैं। इसमें से 483 मछुआरे हैं।

फैजल ने बताया कि पांच मछुआरों समेत 60 भारतीय कैदियों का आखिरी बैच 29 अप्रैल को रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने मानवीय आधार पर इन कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इसके अलावा फैजल ने भारत की ओर से करतारपुर कॉरिडोर को लेकर होने वाली बैठक को टालने पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकों से ही भारत-पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे और दोनों देश शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।

(Adapted from Jagran.com)

5. Pakistan released 100 Indian Fishermen- पाकिस्तान ने 100 भारतीय मछुआरे रिहा किए, कहा- सद्भाव बढ़ाने के लिए उठाया कदम (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पुलवामा में आतंकी हमले के बाद बनी तनाव की स्थितियों के बीच पाकिस्तान ने रविवार को 100 भारतीय मछुआरों को अपनी जेलों से रिहा किया। पाकिस्तान ने यह कदम दोनों देशों के

बीच सद्भाव बढ़ाने के लिए उठाया है। पाकिस्तान ने इस महीने चार चरणों में भारत के 360 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है।

रिहाई के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच 100 भारतीय मछुआरों का जत्था कराची कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस से इन रिहा मछुआरों को लाहौर लाया गया। नजदीक स्थित वाघा सीमा पर इन मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को हवाले किया गया। ये मछुआरे समुद्र में मछली मारते हुए पाकिस्तानी जलसीमा में पहुंच गए थे, वहां उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया था।

पाकिस्तान के सामाजिक संगठन ईधी फाउंडेशन ने रिहा हुए मछुआरों को यात्रा खर्च और उपहार इत्यादि भी दिए हैं। पाकिस्तान विदेश विभाग ने शुक्रवार को 360 भारतीय कैदियों को रिहा करने की घोषणा की थी। अपेक्षा की गई थी कि भारत भी जवाब में ऐसे ही सद्भावनापूर्ण कदम उठाएगा।

(Adapted from Jagran.com)

6. America restricted H-1B visa seats to 65,000 Indians for year 2020- अमेरिका ने वर्ष 2020 तक के लिए H-1B वीजा की लिमिट को 65,000 तक सीमित किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

भारतीयों, पेशेवरों समेत विदेशी नागरिकों की ओर से अधिक संख्या में एच-1बी वीजा के लिए आवेदन मिलने के बाद अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020 के लिए एच1बी वीजा की लिमिट 65,000 तक सीमित कर दी गई है।

आपको बता दें कि एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खासतौर से तकनीकी विशेषज्ञता वाले पेशों में नौकरी देने की इजाजत देता है। तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए इस वीजा पर ही निर्भर रहती हैं।

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा, जो कि वीजा के आवेदनों को मंजूरी देने के काम से जुड़ी एक संघीय एजेंसी है ने कहा, "उसे वित्त वर्ष 2020 के लिए कांग्रेस की ओर से एच-1बी वीजा के लिए सीमित की गई 65,000 की संख्या के लिए पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं।"

वित्त वर्ष एक अक्टूबर 2019 से शुरू होगा और यूएससीआईएस को एक अप्रैल से वीजा के आवेदन मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि एजेंसी ने यह नहीं बताया कि उसे पहले पांच दिनों में कितने आवेदन मिले हैं।

(Adapted from Jagran.com)

7. EU and UK ready to extend Brexit deadline till October- EU और UK ब्रेग्जिट की समयसीमा को अक्टूबर तक बढ़ाने पर हुए सहमत (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

यूरोपीय संघ के नेता और ब्रिटेन गुरुवार को ब्रेग्जिट की समयसीमा को अक्टूबर तक बढ़ाने पर सहमत हो गए। यूरोपीय संघ के बाकी 27 सदस्यों के बीच 6 घंटे तक चली बैठक के बाद ब्रेग्जिट की समय सीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर सहमति बन पाई।

यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट डोनाल्ड टस्क ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे के सामने यह प्रस्ताव रखा। मे ने ब्रेग्जिट की समयसीमा को 30 जून तक बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। टस्क ने एक ट्वीट में लिखा, "ब्रिटिश नेता लंबे समय तक "लचीले" विस्तार के लिए सहमत थे। अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के समझौते की पुष्टि करता है तो वह अक्टूबर से पहले ईयू छोड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटेन को बेहतर संभव समाधान खोजने के लिए छह महीने का समय और मिलेगा।"

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की समयसीमा खत्म होने से दो दिन पहले ब्रिटेन के शीर्ष नेताओं ने रात्रिभोज बैठकों पर चर्चा की। इस बैठक में ब्रिटेन को ब्रेग्जिट से होने वाले संभावित नुकसानों पर विचार किया गया। मे ने कहा था कि 30 जून की समय सीमा ब्रिटेन की संसद के लिए ब्रेग्जिट सौदे की पुष्टि के लिए पर्याप्त समय था।

(Adapted from Jagran.com)

8. Wikileaks founder Assange arrested in London- विकीलीक्स के संस्थापक असांजे गिरफ्तार, 2012 से इक्वाडोर दूतावास में ली थी शरण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे (47) को गुरुवार को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असांजे ने 2012 से इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी। इक्वाडोर के राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लगातार उल्लंघन के चलते हमने असांजे को शरण देने से इनकार कर दिया। इक्वाडोर के इस फैसले के बाद 2012 में जारी वारंट के तहत असांजे को गिरफ्तार किया गया। उन्हें वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

हालांकि, विकीलीक्स ने कहा कि इक्वाडोर ने असांजे की राजनीतिक शरण को अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करार देकर गैरकानूनी कदम उठाया है। विकीलीक्स ने अमेरिकी जांच एजेंसी सीआईए को भी इस कदम के पीछे जिम्मेदार ठहराया है। ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जावीद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि असांजे पुलिस की गिरफ्त में हैं और ब्रिटेन में अदालत का सामना कर रहे हैं।

असांजे पर राष्ट्रपति से जुड़ी जानकारियां लीक करने का आरोप

इक्वाडोर के साथ असांजे के संबंध तब तल्ख हो गए, जब उन पर राष्ट्रपति मोरेनो से जुड़ी निजी जानकारियां लीक करने का आरोप लगा। मोरेनो ने भी असांजे पर शरण देने के समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने ब्रिटेन से अपील की कि असांजे को किसी ऐसे देश में प्रत्यर्पित ना किया जाए जहां उन्हें शारीरिक प्रताड़ना या मौत की सजा दी जाए।

असांजे पर लगे थे रेप के आरोप

2010 में स्वीडन की पुलिस ने रेप और यौन शोषण के दो मामलों में जूलियन असांजे से पूछताछ की। इसके बाद असांजे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया ताकि रेप और शोषण के आरोपों पर उनसे पूछताछ की जा सके। हालांकि, 2012 में असांजे के इक्वाडोर दूतावास में शरण लेने के बाद उन पर से रेप के आरोप हटा लिए गए थे। लेकिन, इसके बावजूद असांजे ने दूतावास से बाहर निकलने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि विकीलीक्स में किए गए काम के चलते उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा।

युद्ध से जुड़े दस्तावेज किए थे सार्वजनिक

मार्च 2018 से असांजे का इंटरनेट कनेक्शन भी काट दिया गया था। इसका कारण असांजे के द्वारा किया गया वादा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बाकी देशों से रिश्तों को लेकर कोई मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। असांजे ने विकीलीक्स की वेबसाइट पर इराक युद्ध से जुड़े चार लाख दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। इसके जरिए उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और नाटों की सेनाओं पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया था। असांजे पर यह भी आरोप है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रूसी खुफिया एजेंसियाेंं ने हिलेरी क्लिंटन के कैम्पेन से जुड़े ईमेल हैक कर उन्हें विकीलीक्स को दे दिया था।

(Adapted from Bhaskar.com)

9. America ready to grant India status of NATO associate nation- भारत को 'नाटो सहयोगी देश' का दर्जा देने की तैयारी में अमेरिका, संसद में अहम बिल पेश (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिकी संसद में करीब आधा दर्जन प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिका-भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अहम बिल पेश किया है। अगर यह बिल लागू होता है तो अमेरिकी विदेश विभाग भारत को नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) के सहयोगी का दर्जा देगा। 'अमेरिका ऑर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट' में भारत को नाटो सहयोगी देश के तौर पर तरजीह मिलेगी।

इस विधेयक पर काम कर रहे यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक, यह इस बात का प्रभावपूर्ण संकेत होगा कि रक्षा सौदों में भारत अमेरिका की प्राथमिकता में है। पिछले सप्ताह सांसद जो विल्सन ने बिल एचआर 2123 पेश किया था, वह 'हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी' के वरिष्ठ सदस्य हैं। विल्सन ने कहा, 'भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और क्षेत्र में स्थिरता का अहम स्तंभ है। भारत ने निर्यात नियंत्रण की नीतियों पर हमेशा प्रतिबद्धता दिखाई है।'

उन्होंने कहा, यूएस कानून में यह संशोधन भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में यूएस-भारत की साझेदारी को सुरक्षा प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। मैं यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआइएसपीएफ) को शुक्रिया अदा करता हूं जिसने इस विधेयक में अपना सहयोग दिया है। इस विधेयक को समर्थन देने वालों में एमी बेरा (यूएस कांग्रेस में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय-अमेरिकी) और जॉर्ज होल्डिंग (हाउस इंडिया कॉकस के उपाध्यक्ष), ब्रैड शेरमैन, तुलसी गबार्ड और टेड योहो का नाम शामिल है।

नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट (एनडीएए), 2017 में भारतीय-अमेरिकी रक्षा साझेदारी को देखते हुए भारत को यूएस के 'प्रमुख रक्षा सहयोगी' का दर्जा दिया गया था। इसमें भी भारत के साथ व्यापार और तकनीक साझा करने पर विशेष सहयोग और प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआइएसपीएफ) ने कहा, यह बदलाव भारत-अमेरिकी के रिश्तों को संस्थागत रूप देगी और एक मजबूत नींव बनेगी जिस पर दोनों देश अपनी रक्षा साझेदारी की ऊंची इमारत खड़ी कर पाएंगे।

यूएसआइएसपीएफ ने अपने बयान में कहा कि भले ही यह देखने में ताकतवर लगे लेकिन एनडीएए वर्ष 2017 में भारत को रक्षा क्षेत्र में ज्यादा तरजीह देने को लेकर किसी भी तरह की कानूनी बाध्यता नहीं थी। गौरतलब है कि अभी तक नाटो के सहयोगी देश का दर्जा इजरायल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिला हुआ है। एनडीएए वर्ष 2017 के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऑर्म्स एक्सपोर्ट एक्ट में संशोधन किया जाएगा। ताकि भारत नाटो के सहयोगी देशों की कतार में आ सके।

यूएसआइएसपीएफ के अध्यक्ष मुकेश अघि ने कहा कि वह कांग्रेस के विल्सन के नेतृत्व में इस विधेयक को फिर से पेश करने की सराहना करते हैं। वह आश्वस्त हैं कि यूएस कांग्रेस उन विधेयकों को लागू करती रहेगी जिनसे भारत-अमेरिका के द्वपक्षीय रिश्ते मजबूत हों। कांग्रेस के सदस्य भारत के साथ मजबूत रिश्तों की रणनीतिक अहमियत को समझते हैं।

यूएसआइएसपीएफ के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने कहा कि यह विधेयक अमेरिका-भारत के रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। वह अध्यक्ष के तौर पर इस कदम का समर्थन करते हैं क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। भारत-अमेरिकाके रिश्तों का भविष्य सुनहरा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यह विधेयक लागू कर दिया जाएगा।

(Adapted from Jagran.com)

10. Netanyahu becomes Israel PM for fifth time- इजरायल के अंतिम नतीजे जारी, नेतन्याहू की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें, पांचवीं बार पीएम बनने की तैयारी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

इजरायल में हुए संसदीय चुनाव के अंतिम नतीजे गुरुवार रात जारी कर दिए गए। केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख जज हनान मेलर के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सबसे ज्यादा 36 सीटें मिली हैं। जबकि मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी के खाते में 35 सीटें आई।

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत नहीं मिलने के बावजूद नेतन्याहू पांचवीं बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में जुट गए हैं। वह 2009 से इजरायल के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यकीन जताया है कि वह दूसरे राष्ट्रवादी और धार्मिक दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार बना लेंगे। चुनाव जीतने के बाद 69 वर्षीय नेतन्याहू ने समर्थकों से कहा था, 'गठबंधन सरकार बनाने के लिए दक्षिणपंथी धड़े और धार्मिक पार्टियों से बातचीत शुरू हो गई है।'

पूरी संभावना जताई जा रही है कि वह शास दल और यूनाईटेड तोरा जूडाइस्म के साथ गठबंधन कर सकते हैं। ये दोनों यहूदी पार्टियां हैं और उन्हें क्रमश: आठ और सात सीटें मिली हैं। इसके अलावा वह कुछ अन्य पार्टियों का समर्थन पाने में कामयाब हो जाएंगे।

किसी को बहुमत नहीं मिलने का था अनुमान

चुनाव पूर्व हुए तमाम सर्वे में नेतन्याहू को पूर्व सेनाध्यक्ष बेनी गेंट्ज से कड़ी चुनौती मिलने की बात कही गई थी। गेंट्ज की ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी नेतन्याहू की पार्टी से महज एक सीट पिछड़ गई। सर्वे में यह भी अनुमान लगाया गया था कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा और नेतन्याहू की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है।

(Adapted from Jagran.com)

11. IMF may delay financial help to Pakistan- पाकिस्तान को झटका, आर्थिक मदद में देरी कर सकता है आइएमएफ (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

क्यों आइएमएफ मदद में देरी कर सकता है?

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद में देरी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक कर्जदाता इस्लामाबाद पर सीपीइसी परियोजना पर पारदर्शी होने के लिए दबाव डाल रहा है और उससे यह लिखित गारंटी चाहता है कि मिलने वाली सहायता का वह चीन का ऋण चुकाने में इस्तेमाल नहीं करेगा। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

पाकिस्तान ने क्यों मदद मांगी थी?

पाकिस्तान ने खुद को भुगतान संतुलन की गंभीर स्थिति से बचाने के लिए आइएमएफ से आठ अरब डॉलर की सहायता मांगी है। चीन की सहायता से पाकिस्तान को अभी तक चालू वित्त वर्ष के दौरान मित्र देशों से आर्थिक सहायता पैकेज के तहत कुल 9.1 अरब डॉलर मिले हैं।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने इसी महीने कहा था कि आइएमएफ का एक दल विश्व बैंक के साथ ग्रीष्मकालीन बैठक के तुरंत बाद इस्लामाबाद आने वाला है। उन्होंने कहा था कि इसी महीने के अंत तक राहत पैकेज पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया, 'अब आइएमएफ का दल अप्रैल में नही बल्कि मई में यहां आ सकता है।'

गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में उमर ने कहा कि दोनों पक्ष आर्थिक मदद पर कमोवेश सहमत हो चुके हैं। एक दो दिनों में हम पूर्ण समझौते तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान-आइएमएफ वार्ता से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि इस्लामाबाद को जून से पहले समझौता होने की उम्मीद है। उनका विश्वास है कि आर्थिक मदद से बजट अपेक्षाओं को मदद मिलेगी।

(Adapted from Jagran.com)

12. No trade through LoC on account of security reasons- LOC के जरिए व्यापार बंद आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

विश्व भर में अपनी उच्च पौष्टिकता के लिए विख्यात अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के बादाम भारत की सुरक्षा और आर्थिक सेहत के लिए बेहद घातक साबित हो रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा (एलओसी) के रास्ते भारत में बेचे जाने वाले इस बादाम की कमाई पाकिस्तानी आतंकियों और अलगाववादियों को पहुंचती है। फिर वह इसका इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में करते हैं। बताया जाता है कि बादामों की इन बड़ी खेपों के साथ हथियारों, नशीली दवाओं और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी की जा रही है। भारत ने इसी के चलते विगत गुरुवार को नियंत्रण रेखा के आरपार बड़े-बड़े ट्रकों से होने वाले कारोबार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। यह रोक शुक्रवार से ही पूरी तरह से प्रभावी हो गई है।

नियंत्रण रेखा पर चकन-दा-बाग और सलामाबाद से पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर और जम्मू-कश्मीर के बीच व्यापारिक मार्ग खोला गया था ताकि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो सकें। लेकिन आतंकी संगठनों ने इसका दुरुपयोग किया। आतंकियों की फंडिंग के मामले में जेल में बंद व्यापारी जहू अहमद वटाली एलओसी ट्रेडर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष था। लेकिन वह कारोबार से होने वाली कमाई को आतंकियों और अलगाववादियों को देने में संलिप्त पाया गया, ताकि वह कश्मीर घाटी में अशांति फैला सकें। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही उसकी करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। इस मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसी एनआइए ने टेरर फंडिंग के लिए हवाला नेटवर्क को भी डिकोड कर लिया है।

नकली नोट, हथियारों की तस्करी

एलओसी के आरपार के कारोबार का दुरुपयोग नियमित रूप से ढंके-छिपे तौर पर कोकीन, ब्राउन शुगर और हेरोइन जैसी जानलेवा ड्रग्स को कश्मीर घाटी में पहुंचाने के लिए भी हो रहा है। इससे कश्मीरी युवाओं को बर्बाद करने की कोशिशें जारी हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में 66.5 किलो हेरोइन घाटी से बरामद हुई और यह एलओसी के पार से हुए व्यापार के जरिए यहां पहुंचाई गई थी। कई कनसाइनमेंट में फर्जी भारतीय नोट भी पकड़े गए थे। एक दफा 57 लाख रुपये के नकली नोट, 20 लाख, 15 लाख और 7.5 लाख रुपये के नकली नोट पकड़े गए। इनके साथ एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। नियंत्रण रेखा के उस पार से होने वाले कारोबार में हथियारों का जखीरे में बड़े पैमाने पर पिस्तौल, ग्रेनेड, भाले और गोलियां कश्मीर घाटी में इस्तेमाल के लिए भेजी जाती हैं। हाल ही में कुलगाम से केले के बड़े कनसाइनमेंट में छिपाकर हथियार कश्मीर घाटी लाए जा रहे थे। मजबूरन भारत सरकार को अनिश्चितकाल के लिए यह कारोबार बंद करना पड़ा।

हिजबुल जैसे आतंकी संगठन सक्रिय

सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी में यह बात आई है कि नियंत्रण रेखा के आरपार होने वाला अधिकांश कारोबार ऐसे लोगों के नियंत्रण में है जिनका प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से गहरा रिश्ता है। इसमें भी सबसे प्रमुख आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन है। कुछ भारतीय नागरिक जो सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए हैं और आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं उन्होंने पाकिस्तान में ही व्यापारिक कंपनियां खोल ली हैं। नतीजतन, ये पाकिस्तानी कंपनियां आतंकी संगठनों के इशारों पर काम करती हैं। इन कंपनियों के मालिकों के रिश्तेदार भारत में रहते हैं, जो उन्हें इस गोरखधंधे को चलाने में उनकी भरपूर मदद करते हैं।

कम कीमत पर बेच अधिक आय

कैलिफोर्निया में उपजे बादाम नियमित रूप से ट्रकों के काफिलों में भेजे जाते हैं। पाकिस्तानी व्यापारी कैलिफोर्निया के बादामों जैसे कई उत्पादों को उनकी असली कीमत से कम कीमत की रसीद पर खरीद दिखाते हैं। उसके बाद भारत पहुंचकर उन बादामों और अन्य जिन्सों को भारतीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। यह कर चोरी करके कारोबारी इन बादामों की खरीद से हुई अतिरिक्त आमदनी को उसके बाद आतंकवादियों या राष्ट्रविरोधी तत्वों को दे देते हैं। यही राष्ट्रविरोध तत्व कश्मीर घाटी में उत्पात मचाते हैं।

(Adapted from Jagran.com)

13. Appeal to Indians to leave Libya- सुषमा स्वराज की लीबिया में रह रहे भारतीयों से अपील, त्रिपोली छोड़ दें अन्यथा बाद में वापसी होगी मुश्किल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को बताया कि लीबिया से भारी लोगों की निकासी और यात्रा प्रतिबंध के बाद भी त्रिपोली में 500 से अधिक भारतीय मौजूद हैं। त्रिपोली में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। फिलहाल, उड़ानें चालू हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया अपने संबंधियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से त्रिपोली छोड़ने के लिए कहें क्योंकि हम बाद में उन भारतीयों को नहीं निकाल पाएंगे।

बता दें कि लीबिया की राजधानी त्रिपोली में कब्जे को लेकर दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच जारी खूनी टकराव में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों ही गुटों के बीच यह लड़ाई इस महीने की शुरुआत में भड़की थी। अब इसके गृह युद्ध में बदलने की आशंका है। सनद रहे कि साल 2011 में भड़के ऐसे ही विद्रोह में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की हत्या हो गई थी। इन सबके बीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा टकराव को देखते हुए उसने घायलों के इलाज के लिए डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर के जरिए विदेशों में फंसे भारतीय की मदद करती रही हैं। हाल ही में अली नामक शख्स जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फंसे हैं, ट्वीट के जरिए सुषमा स्वराज तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने ट्वीट में भारत वापस ना लौटने पर खुदकुशी करने की बात कही थी। इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को खुद उनकी हिम्मत बढ़ाई और हर संभव मदद का भरोसा दिया।

(Adapted from Jagran.com)

14. Serials blasts in Sri Lanka on occasion of Easter- ईस्टर के दिन चर्चों और होटलों को निशाना बनाकर किए गए 8 धमाके; 3 भारतीयों समेत 215 की मौत, 7 गिरफ्तार (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

श्रीलंका में रविवार को ईस्टर के मौके पर तीन चर्च और चार होटलों समेत आठ जगहों पर धमाके हुए। इनमें 33 विदेशियों समेत 215 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 भारतीय भी शामिल

हैं। 500 जख्मी हो गए। रक्षा राज्य मंत्री रूवन विजयवर्धने ने 7 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही है।

शुरुआती छह धमाके लगभग एक ही समय पर सुबह 8:45 बजे हुए। बाकी दो धमाके दोपहर में दो से ढाई बजे के बीच कोलंबो में हुए। 2009 में श्रीलंका में तमिल विद्रोही संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) का खात्मा हो गया था। इसके बाद हुआ यह सबसे बड़ा हमला है।

पहला धमाका राजधानी के चर्च में हुआ

पहला धमाका कोलंबो के कोच्चिकड़े स्थित सेंट एंथनी चर्च में हुआ, इसके बाद नेगोंबो के कटुवपिटिया स्थित सेंट सेबेस्टियन चर्च और बट्टीकलोआ स्थित चर्च में धमाके हुए। इनके अलावा कोलंबो के फाइव स्टार होटलों शांगरी ला, किंग्सबरी और सिनेमन ग्रैंड में भी ब्लास्ट हुए। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, कोलंबो में होटलों में हुए ब्लास्ट में करीब 45 लोग मारे गए। वहीं नेगोंबो चर्च में 90 और बट्टीकलोआ में 27 लोग मारे गए।

'सभी धमाकों के आत्मघाती होने की पुष्टि नहीं'

मीडिया ब्रीफिंग में गुणाशेखरा ने कहा, "अभी हम यह नहीं कह सकते कि सभी धमाके आत्मघाती हमले थे। हालांकि कटुवपिटिया (नेगोंबो) चर्च धमाका फिदायीन हमले जैसा प्रतीत होता है।" इससे पहले एक अधिकारी ने कहा था कि एक आत्मघाती हमलावर ने सिनेमन होटल के रेस्त्रां में खुद को उड़ा लिया था। सोशल मीडिया पर अस्थायी प्रतिबंध के साथ देशभर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

33 में से 12 विदेशियों की पहचान हुई

नेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनिल जयसिंघे ने मारे गए 33 विदेशियों में से 12 की पहचान कर ली। इनमें 3 भारतीय, 2 चीनी समेत पोलैंड, डेनमार्क, जापान, पाकिस्तान, अमेरिका, मोरक्को और बांग्लादेश का एक-एक व्यक्ति शामिल है।

भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तीनों मृतकों की पहचान लक्ष्मी, नारायण चंद्रशेखर और रमेश के तौर पर की।

पुलिस-डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल

धमाकों के मद्देनजर पुलिस अफसरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। छुट्टी पर चल रहे डॉक्टरों-नर्सों को भी ड्यूटी पर बुला लिया गया है। सोमवार और मंगलवार को सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

बौद्ध सिंहला और मुस्लिम समुदाय में हो चुका है टकराव

अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने देश में जड़ें जमाई हैं। पिछले साल श्रीलंका में बौद्ध सिंहला और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव की कुछ घटनाएं सामने आई थीं। मार्च 2018 में इसके चलते सरकार को इमरजेंसी तक लगानी पड़ी थी।

दिगमपाठना हमले में मारे गए थे 120 नाविक

लंका में इससे पहले 2006 में हमला हुआ था। ये हमला लिट्टे ने करवाया था। इस हमले को दिगमपाठना बॉम्बिंग के नाम से जाना जाता है। लिट्टे ने बम से भरे ट्रक से मिलिट्री की 15 बसों पर हमला किया था। इसमें 120 नाविक मारे गए थे।

10 साल पहले हुआ था लिट्टे का खात्मा

लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) की स्थापना वेलुपिल्लई प्रभाकरण ने 1976 में की थी। इसका मकसद उत्तर और पूर्व श्रीलंका में तमिल ईलम (तमिलों के लिए स्वतंत्र राज्य) बनाना चाहता था। 1983 से 2009 तक श्रीलंका गृहयुद्ध की चपेट में रहा। 25 जनवरी 2009 को लिट्टे के अंतिम इलाके मुल्लईतिवू को जीत लिया गया। 16 मई 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने 26 साल चले गृहयुद्ध और लिट्टे के खात्मे का ऐलान किया।

(Adapted from Bhaskar.com)

15. UN Report: 20वीं सदी के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक भोपाल गैसकांड (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में हजारों लोगों की मौत हुई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। यह 20वीं सदी में हुई दुनिया की सबसे 'बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं' में से एक है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि हर साल 27.8 लाख श्रमिक व्यावसायिक दुर्घटनाओं और काम से संबंधित बीमारियों से मारे जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र की श्रम एजेंसी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 1984 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस हादसे में छह लाख से अधिक श्रमिक और आसपास रहने वाले लोग भी प्रभावित हुए थे।
सरकारी आंकड़ों में अनुमान लगाया गया है कि उस आपदा की वजह से कई वषरें में 15,000 लोगों की मौतें हुई। विषाक्त सामग्री अभी भी वहीं है और हजारों जीवित बचे लोग और उनके वंशज श्वसन रोगों, आंतरिक अंगों व प्रतिरक्षा प्रणाली को हुए नुकसान से पीड़ित हैं।

यूएन की इस रिपोर्ट को 'द सेफ्टा एंड हेल्थ एट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ वर्क-बिल्डिंग ऑन 100 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस' के शीर्षक से प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भोपाल की आपदा साल 1919 के बाद दुनिया की 'बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं' में से एक थी।
चेर्नोबिल पावर स्टेशन के परमाणु रिएक्टर में धमाका हुआ था

साल 1919 के बाद रिपोर्ट में शामिल की गई अन्य नौ बड़ी औद्योगिक हादसों में चेर्नोबिल और फुकुशिमा परमाणु आपदाओं के साथ-साथ राणा प्लाजा की इमारत के ढहने की घटना को भी शामिल किया गया था। अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल आपदा में यूक्रेन में चेर्नोबिल पावर स्टेशन पर चार परमाणु रिएक्टरों में से एक में धमाका हो गया था। इससे जापान के दो प्रमुख शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक विकिरण हुआ था। विस्फोट के साथ ही 31 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि बाद में इसकी वजह से हुए रेडिएशन से हजारों लोग मारे गए।

पांच फैक्ट्री वाली ढाका की राणा प्लाजा इमारत ढह गई थी

बांग्लादेश में सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक ढाका की राणा प्लाजा इमारत में हुआ हादसा था। अप्रैल 2013 में यह इमारत ढह गई थी, जिसमें कपड़ों के पांच कारखाने चल रहे थे। इस हादसे में कम से कम 1,132 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2,500 से अधिक लोग घायल हुए थे।

27.8 लाख श्रमिक कार्य संबंधी हादसों और बीमारियों से हैं मरते

रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 27.8 लाख श्रमिक व्यावसायिक दुर्घटनाओं और कार्य-संबंधी बीमारियों से मर जाते हैं। अतिरिक्त 37.4 करोड़ श्रमिक गैर-घातक व्यावसायिक दुर्घटनाओं से पीडित हैं। रिपोर्ट में बताया है कि बिना भुगतान के काम कराने से किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य, सुरक्षा या जीवन को खतरा हो सकता है। एजेंसी ने बढ़ती चिंता के कई नए या मौजूदा व्यावसायिक जोखिमों की पहचान की जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि 36 प्रतिशत कर्मचारी लंबे समय से अत्यधिक काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं।

(Adapted from Jagran.com)

16. India will not be able to buy oil from Iran- ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीद सकेगा भारत (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिका द्वारा ईरान से तेल लेने पर प्रतिबंध

भारत अब ईरान से कच्चा तेल (क्रूड) नहीं खरीद सकेगा। पिछले वर्ष ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद अमेरिका ने कुछ देशों को वहां से तेल खरीदने के लिए छह महीनों की जो छूट दी थी वह छूट की अवधि पहली मई को खत्म हो रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी देश के लिए यह अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। इसमें भारत, चीन और जापान समेत आठ देश शामिल हैं। छूट का लाभ उठा रहे कई देशों ने अमेरिका के इस फैसले की आलोचना की है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वह और उसके सहयोगी देश अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कमी नहीं होने देंगे।

ईरान के साथ भारत का तेल व्यापार

ईरान से इस वर्ष रोजाना तीन लाख बैरल तेल खरीदने की तैयारी में जुटे भारत के लिए अब दूसरे स्रोतों का इंतजाम करना होगा। भारत सरकार पहले ही सउदी अरब, इराक से इस कमी को पूरा करने की बातचीत शुरू कर चुकी है। अमेरिका से भी ज्यादा क्रूड खरीदने की राह निकलती दिख रही है।

तेल कीमतों पर असर पड़ेगा

अमेरिका के इस कदम का असर घरेलू बाजार में भी पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर पड़ने की आशंका है। क्योंकि ईरान अब अंतरर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। इसका असर क्रूड की कीमत पर भी पड़ेगा। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत 74.31 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है जो पिछले छह महीनों का उच्च स्तर है। अभी जबकि भारत में आम चुनाव का दौर चल रहा है तो क्रूड का महंगा होने का राजनीतिक असर भी दिख सकता है।

वैसे, पिछले एक महीने का अनुभव बता रहा है कि सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल व डीजल की कीमत बढ़ाने में काफी एहतियात बरत रही हैं।

नीतिगत तौर पर इन्हें क्रूड की कीमत को देखते हुए रोजाना पेट्रोल व डीजल की कीमत को तय करने का अधिकार है, लेकिन हाल के दिनों में ये ऐसा नहीं कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत इस बात से भी तय होगी कि आपूर्ति करने वाले दूसरे देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब अपना उत्पादन कितना बढ़ाते हैं।

मामला क्या है?

अमेरिका ने नंवबर, 2018 में ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया था। लेकिन भारत, चीन, दक्षिण कोरिया समेत आठ देशों को छह महीने की छूट दी थी कि वे ईरान से तेल खरीदना कम कर देंगे। भारत को उम्मीद थी कि इस छूट की अवधि और बढ़ जाएगी। लेकिन सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जिन देशों को ईरान के साथ कारोबार करने की छूट दी गई थी, उनके लिए छूट की अवधि अब नहीं बढ़ाई जाएगी। अमेरिका ने भारत को चाबहार बंदरगाह के निर्माण व विकास को लेकर भी छूट दे रखी थी।

बड़ा सप्लायर रहा है ईरान

ईरान के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार भारत ही है। वर्ष 2010-11 तक भारत सउदी अरब के बाद सबसे ज्यादा तेल ईरान से ही खरीदता रहा था। हालांकि फिलहाल ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर देश है। दोनों देशों की सरकारों के बीच अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने की स्थिति में भी तेल व्यापार जारी रखने को लेकर बातचीत जारी है। इसके लिए दोनों देशों के बीच रुपये में भुगतान करने को लेकर भी सहमति बनी थी।

सरकार कर रही समीक्षा

इस बारे में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बस इतना बताया है कि वे पूरे हालात की समीक्षा कर रहे हैं और उचित समय पर विस्तृत बयान जारी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि वे भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले दूसरे देशों के साथ लगातार संपर्क में है और तेल आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी।

(Adapted from Jagran.com)

17. Iran and Pakistan to constitute border reaction force to stop terror- आतंकी हमले रोकने के लिए बॉर्डर 'रिएक्शन फोर्स' बनाएंगे ईरान और पाकिस्तान (Relevant for GS Prelims; IOBR)

ईरान और पाकिस्तान ने संयुक्त बॉर्डर 'रिएक्शन फोर्स' गठित करने का फैसला किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भीषण आतंकी हमलों के बाद दोनों देशों ने यह फैसला किया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने दौरे पर आए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बैठक के बाद इसकी घोषणा की।

दोनों देशों के बीच सिस्तान-बलूचिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल के दिनों में आतंकी हमले बढ़ने से तनाव पैदा हो गया था।

पिछले साल प्रधानमंत्री बनने के बाद से इमरान खान की यह पहली ईरान यात्रा है। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान में 14 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए पाकिस्तान ने ईरान स्थित आतंकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया था।

इमरान खान ने कहा, 'सुरक्षा प्रमुख यहां अपने समकक्ष के साथ बैठक कर सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे।' हालांकि, संयुक्त बल के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई।

ईरान की अपनी दो दिन की यात्रा के आखिरी दिन सोमवार को खान ने कहा कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे।

(Adapted from Jagran.com)

18. Iran conferred status of terror group on American forces- ईरानी संसद ने अमेरिकी सेना को आतंकी समूह का दर्जा दिया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

ईरान की संसद ने मंगलवार को एक बिल पास किया। इसके मुताबिक अमेरिकी नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले समस्त सैन्यबलों, संगठनों को आतंकवादी समूह को दर्जा दिया गया। यह फैसला अमेरिका के द्वारा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गॉर्ड्स कॉर्प्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किए जाने के बाद लिया गया है। इस कदम के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब ईरान से तेल आयात नहीं करेगा। भारत ने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है।

अमेरिका के कदम पर ईरान में शुरू हुआ विरोध

1. न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के रिवोल्यूशन गॉर्ड्स कॉर्प्स को आतंकी बताए जाने के कारण ईरान के द्वारा वहां शांति स्थापित करने के प्रयास कमजोर हुए हैं। सोमवार को अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया था कि वह अब किसी भी देश को ईरान का तेल खरीदने के लिए ज्यादा अधिक रियायत देने के मूड में नहीं है।

2. वहीं अमेरिका के कदम से ईरान में खासी नाराजगी है। मंगलवार को ईरानी संसद में मौजूद 215 सांसदों में से 173 ने अमेरिका के खिलाफ लाए गए इस बिल का समर्थन किया। अमेरिका ने पिछले साल 2015 में हुई परमाणु संधि को तोड़ा था। ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए थे।

3. अमेरिका के द्वारा इस्लामिक रिवोल्यूशन गॉर्ड्स कॉर्प्स को आतंकी संगठन बताए जाने के विरोध में लोगों ने अमेरिका और इजरायल के झंडों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इन देशों के विरोध में नारे भी लगाए। वहीं भारत ने ईरान से तेल आयात करने पर रोक लगाने का मन बना लिया है। अब विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

4. सेंटकॉम का सुनियोजन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1 जनवरी 1983 को किया था। इसका उद्देश्य मिडिल ईस्ट देशों में अमेरिका के हितों को समर्थन देना था। इसमें अफ्रीका से सेंट्रल एशिया तक के हिस्से की सुरक्षा का दारोमदार अमेरिकी सेना के जिम्मे था।
5. सेंटकॉम के अंतर्गत अमेरिकी सैन्य बलों के साथ कुछ संगठन भी शामिल हैं। जिन पर इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत अरेबियन पेनिन्सुला, दक्षिणी लाल सागर और सेंट्रल एशिया के पांच गणराज्यों में अमेरिका के हितों की रक्षा करने का जिम्मा है।

(Adapted from Bhaskar.com)

19. IS module took responsibility of terror attack- आइएस ने ली श्रीलंका आतंकी हमले की जिम्मेदारी, हमले में मरने वालों की संख्या हुई 321 (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए भीषण आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। तीन चर्चो और तीन होटलों में हुए आत्मघाती हमलों में मरने वालों की संख्या 321 हो चुकी है। 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों में 10 भारतीय समेत 38 विदेशी हैं। इस बीच, मंगलवार को हमले का शिकार हुए सेंट सेबेस्टियन चर्च के निकट कई मृतकों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया।

सरकारी अधिकारियों ने हमले में स्थानीय मुस्लिम आतंकी संगठन नेशनल तौहीद जमात (एनटीजे) का हाथ होने की बात कही है। हालांकि इस बात से इन्कार नहीं किया गया है कि आतंकियों को बाहरी आतंकी संगठनों से मदद मिली थी।आतंकी संगठन आइएस ने आधिकारिक समाचार एजेंसी अल-अमैक के जरिये दावा किया कि आत्मघाती हमलावर आइएस के लड़ाके थे। उसने सातों आत्मघाती हमलावरों की पहचान अबू उबैदा, अबू अल-मुख्तार, अबू खलील, अबू हमजा, अबू अल-बारा, अबू मुहम्मद और अबू अब्दुल्ला के रूप में की है।

आतंकी संगठन ने हमले में 1,000 से ज्यादा लोगों के मरने और घायल होने का दावा भी किया है। आइएस ने अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कोई सुबूत नहीं दिया है। हालांकि उसके दावा करने से पहले ही सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो चलने लगा था, जिसमें यह स्थापित करने की कोशिश थी कि हमले के पीछे आइएस का हाथ है। इसमें कथित तौर पर तीन आत्मघाती हमलावरों की तस्वीर दिखाई गई थी। तीनों आइएस के काले झंडे के सामने खड़े थे।

अब तक 40 की गिरफ्तारी

श्रीलंका पुलिस ने अब तक इस मामले में 40 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें एक सीरियाई नागरिक भी है। स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है।

दो और भारतीयों की मौत की पुष्टि

हमले में दो और भारतीयों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 10 भारतीयों की जान जाने की बात सामने आई है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मंगलवार को जिन दो भारतीयों की मौत की पुष्टि की गई, उनके नाम ए. मारेगौड़ा और एच. पुत्तराजू बताए गए हैं। इससे पहले सोमवार को सामने आया था कि मृत भारतीयों में कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के पांच कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

45 बच्चों की गई जान

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का कहना है कि श्रीलंका में हुए भीषण आतंकी हमले में कम से कम 45 बच्चों की मौत हुई है। यह संख्या बढ़ने की भी आशंका है, क्योंकि कई बच्चे घायल हैं। यूनीसेफ के मुताबिक, मृतकों में 40 बच्चे श्रीलंकाई हैं और पांच विदेशी हैं।

आतंकियों ने न्यूजीलैंड का लिया बदला

हमले की शुरुआती जांच के बाद श्रीलंका के रक्षा मंत्री रुवान विजवर्दने ने बताया है कि आतंकियों ने न्यूजीलैंड की दो मस्जिदों में 15 मार्च को हुए हमले का बदला लेने के लिए धमाकों को अंजाम दिया। एक ऑस्ट्रेलियाई बंदूकधारी ने न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित दोनों मस्जिदों पर हमला किया था। इस हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि न्यूजीलैंड का कहना है कि दोनों घटनाओं में संबंध को लेकर कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली है।

(Adapted from Jagran.com)

20. India to stop import of oil from Iran- ईरान से तेल का आयात बंद करेगा भारत, क्रूड के रेट 10% बढ़े तो महंगाई 0.24% बढ़ेगी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिकी प्रतिबंधों से मिल रही रियायत खत्म होने के बाद भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर देगा। इसकी भरपाई के लिए सऊदी अरब, कुवैत, यूएई और मैक्सिको जैसे देशों से वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार के शीर्ष अधिकारियों और क्रूड इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

भारत डेडलाइन बढ़ाने के लिए यूएस पर दबाव डाल सकता है

1. ईरान की सप्लाई बंद होने से ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे। केयर रेटिंग्स के अनुसार इससे भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा और महंगाई दर में इजाफा होगा। तेल के दाम 10% बढ़े तो खुदरा महंगाई 0.24% बढ़ सकती है। रुपया 3-4% कमजोर हो जाएगा। चालू खाते का घाटा 0.4% बढ़ जाएगा।

2. ट्रम्प प्रशासन ने सोमवार को भारत समेत 8 देशों को ईरान से कच्चा तेल आयात करने को लेकर मिली छूट की अवधि आगे नहीं बढ़ाने के फैसले का ऐलान किया। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, 'जब तक छूट फिर से शुरू नहीं होती, भारत ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। इस महीने के आखिर में होने वाली बैठक में भारत अमेरिकी सरकार से छूट की समय सीमा को 2 मई से आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकता है।'

3. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कहा, 'भारतीय रिफाइनरियों को कच्चे तेल की पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक मजबूत योजना तैयार की गई है। रिफाइनरियां देशव्यापी मांग को पूरा करने के लिए तैयार हैं।'

4. ईरान तेल खरीदारों को 60 दिन का उधार देता है

भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। लगभग 10% आयात ईरान से होता है। ईरान से कच्चा तेल लेना रिफाइनरियों के लिए फायदेमंद होता है। ईरान उन्हें 60 दिन का उधार देता है। सऊदी अरब सहित अन्य देश यह सुविधा नहीं देते हैं। इनसे तेल खरीदने पर 15 दिनों में भुगतान करना पड़ता है।

5. पिछले साल ईरान से 2.4 करोड़ टन आयात हुआ था

इंडियन ऑयल के पास पूरे साल में मैक्सिको से 7 लाख टन अतिरिक्त कच्चा तेल लेने का विकल्प है। सऊदी अरब से 20 लाख टन, कुवैत से 15 लाख टन और संयुक्त अरब अमीरात से 10 लाख टन अतिरिक्त कच्चा तेल लेने का विकल्प है। 2018-19 में भारत ने ईरान से करीब 2.4 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा था।

6. 75 डॉलर के करीब पहुंची कच्चे तेल की कीमत

ईरान पर प्रतिबंध से छूट खत्म करने की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 74.5 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। यह 6 महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले साल जब ट्रंप प्रशासन ने परमाणु डील से हटने का फैसला किया था तब कच्चे तेल की कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी।

7. ईरान से तेल आयात पर छूट की मियाद 2 मई को खत्म होने वाली है

चीन: मध्य पूर्व में समस्याएं बढ़ेंगी

चीन ने अमेरिका के इस फैसले पर कहा है कि इससे मध्य पूर्व में समस्याएं बढ़ेंगी। साथ ही एनर्जी मार्केट भी असंतुलित होगा। एक बयान में इसने कहा कि चीन एकतरफा प्रतिबंध का विरोध करता है। चीन अपने हितों की रक्षा की कोशिश करता रहेगा।

8. ईयू: ईरान के साथ परमाणु डील जारी रहेगी

यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के फैसले को अफसोसजनक बताया है। ईयू ने कहा कि जब तक ईरान परमाणु समझौते को लेकर प्रतिबद्धता दिखाता रहेगा, उसके साथ डील जारी रहेगी।

9. सऊदी: ईरान पर दबाव जारी रखा जाए

ईरान पर प्रतिबंध से सबसे अधिक लाभ सऊदी अरब को होगा। इसने अमेरिका के फैसले को सही ठहराया है। सऊदी अरब की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गलत नीतियों और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ईरान पर दबाव जारी रखा जाए।

(Adapted from Bhaskar.com)

21. Person of Indian origin won elections in Japan- भारतीय मूल के व्यक्ति ने पहली बार जापान में जीता चुनाव (Relevant for GS Prelims; IOBR)

भारतीय मूल के पुराणिक योगेंद्र ने टोक्यो के एदोगावा वार्ड असेम्बली चुनाव में जीत हासिल की है। 41 वर्षीय योगेंद्र पहले भारतीय हैं जिन्होंने जापान में चुनाव जीता है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अप्रैल को हुए चुनाव में योगी को 6,477 मत मिले। योगी ने बताया कि 2011 में जापान में आए भूकंप के बाद मैंने तय किया कि न सिर्फ मैं जापान की नागरिकता लूंगा बल्कि राजनीति को करियर बनाऊंगा।

2005 में योगी वार्ड एदोगावा के रहवासी बने

1. पुराणिक योगेंद्र का निक नेम योगी है। उन्हें जापान की कांस्टीट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला। उन्होंने अपनी जीत पर कहा, "मैं जापानियों और विदेशियों के बीच एक सेतु बनना चाहता हूं।"

2. एदोगावा वार्ड में ज्यादा संख्या में भारतीय रहते हैं। टोक्यो के 23 वार्डों में रहने वाले 4,300 लोगों में दस फीसदी लोग भारतीय हैं। यूं तो जापान में 34,000 भारतीय रहते हैं। इस वार्ड में चाइनीज और कोरियन लोग भी रहते हैं।

3. चैंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडिया-जापान रिलेशन के लेखक शमशाद खान ने कहा, "जापान के चुनावों में भारतीय मूल के जापानी व्यक्ति की यह पहली जीत है। यह संकेत है कि जापान के समाज निर्माण में भारतीयों ने किस तरह अपना योगदान दिया है।"

4. योगी 1997 में जापान पहुंचे। वह भारत में यूनिवर्सिटी के छात्र थे। यहां पढ़ाई करने के दो साल बाद जापान लौटे। 2001 में इंजीनियर के तौर पर जापान में काम शुरू किया। इस दौरान बैंक और दूसरी कंपनियों में काम किया। 2005 से एदोगावा के नागरिक बन गए।

5. योगी ने जापान में अपने अनुभवों पर कहा, "जापान बहुत साफ है। हर कोई बेहद विनम्र है। 2011 में आए भूकंप के दौरान मुझे स्थानीय लोगों की मदद करने और उनसे जुड़ने का मौका मिला। मैंने महसूस किया कि यह समय है जब मैं जापानी बन जाऊं।"

(Adapted from Bhaskar.com)

22. Kim and Putin meet in Russia- 17 वर्ष पहले कभी यहीं पर किम के पिता से मिले थे पुतिन, जानें किम से मुलाकात के मायने (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

रूस का शहर व्लादिवोस्तोक एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एतिहासिक मुलाकात है। यह दोनों नेता पहली बार मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले पुतिन ने 23 अगस्त 2002 को इसी शहर में किम के पिता और तत्कालीन उत्तर कोरियाई प्रमुख किम जोंग इल से मुलाकात की थी। उस वक्त भी यह मुलाकात मीडिया की सुर्खियों में थी। जहां तक किम और उनके पिता की बात है तो दोनों में काफी कुछ मेल खाता है। किम जोंग इल ने भी अपने कार्यकाल के दौरान काफी कम विदेश यात्राएं की थीं। इतना ही नहीं वह भी चीन, रूस और जापान के अलावा शायद ही कहीं गए थे। ठीक वैसे ही किम भी इन देशों के आगे अब तक नहीं निकले। हालांकि, यह बात अलग है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली शिखर वार्ता के लिए पहले सिंगापुर और फिर हनोई गए थे।

मीडिया का जमावड़ा

अब किम जोंग उन अपने विदेशी रिश्तों को दोबारा से धार देने में लगे हैं। इसी वजह से बुधवार को वह चीन के बाद रूस से अपने पुराने रिश्तों को दोबारा तरोताजा बनाने के लिए पहुंचे थे। गुरुवार को जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एतिहासिक मुलाकात की तो यकायक ये शहर फिर सुर्खियों में आ गया। इस पल को अपने कैमरे में कैद करने के लिए यहां पर कई देशों की मीडिया का जमावड़ा भी था। वहीं कई देशों खासकर अमेरिका की निगाह भी इस बैठक पर लगी थी। आखिर हो भी क्यों नहीं किम अमेरिका के चिर-परिचित प्रतिद्वंदी से मुलाकात जो कर रहे थे।

मुलाकात के खास मायने

किम की पहले चीन और अब रूस की यात्रा के बेहद खास मायने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और रूस काफी लंबे समय से उत्तर कोरिया के साथी रहे हैं। इतना ही नहीं प्रतिबंधों के बाद भी यह दोनों देश किसी न किसी तरह से उत्तर कोरिया की मदद करते रहे हैं। अमेरिका से तनाव के बीच भी इन दोनों ने उत्तर कोरिया से अपने संबंध मधुर बना रखे थे। हालांकि, रूस पिछले कई सालों से उत्तरी कोरिया पर अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। रूस 2009 में इसके लिए हुई छह देशों अमेरिका, जापान, चीन, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की हुई बैठक में शामिल था।

आठ वर्ष बाद मुलाकात

आपको यहां पर ये भी बता दें कि किम जोंग उन के सत्ता में आने के बाद ये उनकी पहली रूसी यात्रा है। गौरतलब है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह मुलाकात आठ वर्ष बाद हो रही है। इससे पहले 24 अगस्त 2011 को किम जोंग इल की रूसी प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव से मुलाकात हुई थी। किम जोंग उन ने चीन की अपनी पहली यात्रा भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सिंगापुर में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले की थी। इसके अलावा हनोई यात्रा से पहले भी उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिन से मुलाकात की थी। वहीं अब जबकि किम और ट्रंप की तरफ से तीसरी मुलाकात की बात कही जा रही है तो उत्तर कोरिया के प्रमुख चीन के बाद रूस पहुंचे हैं। किम ने व्लादिवोस्तोक की यह यात्रा अपने चिरपरिचित अंदाज में ट्रेन से ही की है। इसके लिए पहले वह उत्तर कोरिया की सीमा से सटे रूसी इलाके खासन तक पहुंचे थे। यहां से वो व्लादिवोस्तोक पहुंचे। यहां पर उनका पारंपरिक तौर से स्वागत किया गया।

समर्थन जुटाने की है कोशिश

यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर कोरिया ने हाल ही में नया रॉकेट टेस्ट करने का दावा किया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने अब तक भी उत्तर कोरिया से प्रतिबंध नहीं हटाए हैं, ऐसे में किम विदेश यात्राओं के जरिए अपने प्रति समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। जहां तक पुतिन और किम की मुलाकात की बात है तो अभी तक इसके समय का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन, रूसी अखबार कॉमरसैंट ने इसके 25 अप्रैल को होने की बात कही है। इस मुलाकात से पहले किम के खास सलाहकार किम चांग सुन 21 अप्रैल को व्लादिवोस्तोक गए थे।

दक्षिण कोरिया का रुख

इस मुलाकात को लेकर दक्षिण कोरिया का कहना है कि रूस और उत्तरी कोरिया के बीच होने वाली इस मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों के अलावा परमाणु कार्यक्रम पर रोक और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिण कोरिया का कहना है कि रूस और हमारी सोच एक जैसी है। हम भी चाहते हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप पूरी तरह से परमाणु मुक्त हो और यहां शांति कायम हो। उम्मीद है कि इस मुलाकात से एक सकारात्मक विकास की एक उम्मीद मिलेगी।

किम-ट्रंप की मुलाकात

किम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ट्रम्प से वियतनाम की राजधानी हनोई में दो महीने पहले मुलाकात हुई थी लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही थी। इससे पहले इन दोनों के बीच पिछले वर्ष मुलाकात हुई थी। यह दोनों ही मुलाकात लगभग बेनतीजा रही हैं। इसकी वजह थी कि किम चाहते थे कि उनके देश पर लगे प्रतिबंधों को खत्म किया जाए, लेकिन इस पर अमेरिका राजी नहीं था।

(Adapted from Jagran.com)

23. India rejected China's invitation to participate in 2nd BRI forum- भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी बीआरआइ परियोजना पर किया कड़ा रुख अख्तियार, स्वीकार नहीं आमंत्रण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

भारत ने जब भी चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोट इनिशिएटिव यानी बीआरआइ पर कोई रुख अख्तियार किया है तो ऐसा करके उसने उसे और साथ ही दुनिया को कई संदेश देने का काम किया है। चीन एक बार फिर बीआरआइ से जुड़ा आधिकारिक आयोजन करने जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए उसने भारत को भी निमंत्रण दिया था। पहले की तरह इस बार भी भारत ने इस न्यौते को ठुकरा दिया। इससे पहले भी भारत ने चीन के इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। नई दिल्ली ने मई 2017 में प्रथम बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था जिसमें 129 देशों और कई राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। भले ही अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने उसमें भाग लिया हो, लेकिन भारत इसे लेकर अपने रुख पर मजबूती से टिका हुआ है। वह इस चीनी पहल पर अपनी आपत्तियों को जाहिर करता रहा है।

बीआरआइ के माध्यम से खुद को वैश्विक शक्ति के तौर पर पेश करने की चीनी आकांक्षाओं के लिए भारत का यह रुख एक बड़ा झटका था। भारत के इन्कार के बाद से चीन को ऐसे कई झटके लगे हैं जिन्होंने उसके लिए समस्याएं कई गुना बढ़ा दी हैं। चूंकि भारत ने एक बार फिर अपना विरोध जताया है तो बीजिंग भी इस पर अपने पत्ते फेंटेगा। इसके संकेत भी मिल गए हैं। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसका उल्लेख कुछ इस तरह किया है, 'अगर भारत बीआरआइ के तहत सहयोग से मुंह फेरता है या फिर कुछ परियोजनाओं में हस्तक्षेप करता है तो वह कई बड़ी विकास परियोजनाओं से जुड़ने का अवसर खो बैठेगा। साथ ही कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ बेहतर जुड़ाव की उसकी योजनाओं को भी नुकसान होगा।'

नई दिल्ली का हालिया निर्णय चीन के उस रुख के बाद सामने आया है जिसमें चीन मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित कराने की भारत की कोशिशों को लगातार झटका देता आया है। हाल के पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी चीन का रुख इस मसले पर बदला नहीं। अगर वुहान वार्ता को छोड़ दिया जाए तो भारत-चीन रिश्तों के मोर्चे पर कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। कुछ हालिया रपटों में यह सामने आया है कि डोकलाम पठार पर चीन अपनी स्थिति लगातार मजबूत बना रहा है। यह सीमा पर चुनौती को दर्शाता है। जो भी हो, भारत की संप्रभुता का मूल प्रश्न बीआरआइ को लगातार परेशान करता रहेगा। जैसा कि चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने दोहराया, 'कोई भी देश ऐसी परियोजना से नहीं जुड़ सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर उसकी मुख्य चिंताओं की अनदेखी करती हो।'

हालांकि बीआरआइ को लेकर बाकी दुनिया को लुभाने की चीनी मुहिम लगातार जारी है, लेकिन भारत अपने रवैये पर कायम है और उसे कायम रहना भी चाहिए। बीआरआइ से जुड़े कार्यक्रम में करीब सौ से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में लगभग 40 देशों के राष्ट्रप्रमुखों के भी शामिल होने की उम्मीद है। पश्चिमी देशों में बीआरआइ को लेकर कुछ संशय और संदेह के बावजूद अभी हाल में इटली इस परियोजना के साथ जुड़ा है। चीन ने दुनिया को यह समझाने में कामयाबी हासिल की है कि आर्थिक भूमंडलीकरण के अगले चरण के लिए बुनियादी ढांचा विकास और कनेक्टिविटी की तत्काल सख्त जरूरत है। अन्य प्रमुख शक्तियों को भी इस बात के लिए बाध्य किया गया है कि अपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी योजनाओं के लिए वे चीन की शरण में आएं।

दुनिया भर में इस मोर्चे पर बहुत बड़ी मांग पैदा हो गई है और चीन इस मांग को पूरा करने की कोशिश में समर्थ दिखने वाले प्रमुख देश के रूप में उभरा है। बहरहाल इस राह में आने वाली बाधाओं से पार पाने में बीजिंग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उसमें उसका रवैया और छवि भी आड़े आ रही है। भारत अपनी संप्रभुता के आधार पर चीन की बीआरआइ परियोजना का विरोध तो कर ही रहा है, इसके साथ ही वह परियोजना को लेकर वित्तीय और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी उठा रहा है। ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। कई ऐसे देश जो शुरुआत में बड़े उत्साह के साथ बीआरआइ परियोजना के साथ जुड़े उनमें से कुछ का रुख-रवैया अब बदला हुआ है और वे भारत के सुर में सुर मिला रहे हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने हाल में चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर कर्ज के जाल में फंसने की आशंका जताई। मालदीव और श्रीलंका से लेकर मलेशिया और थाईलैंड तक तमाम देशों में चीन की कई परियोजनाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि चीन की आर्थिक उद्दंडता पर पश्चिमी जगत भी सख्ती कर ही रहा है। जर्मन उद्योग परिसंघ ने हाल में यूरोपीय संघ से कहा है कि चीन के साथ वह सख्त शर्तों पर समझौता करे जो बाजार में उत्पाद डंप करके, आक्रामक तकनीक और वित्तीय बैंकिंग में असमानता जैसे संदिग्ध तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है।

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भारत ने कई तरह से वैश्विक विमर्श को दिशा दी है। इसमें चीनी बीआरआइ के शोषणकारी स्वरूप को भी उकेरा है। अपनी संप्रभुता के मुद्दे पर

बीआरआइ के विरोध से परे भी भारत इस मुद्दे पर सकारात्मक विमर्श पेश करने में सफल रहा है। इस कवायद में भारत को खुद अपनी क्षमताओं से साक्षात्कार करना पड़ा है कि वह स्वयं कैसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जैसे मोर्चे पर योगदान दे सकता है। अन्य देशों के साथ साझेदारी को लेकर मौलिक चिंतन के साथ ही उसे स्वयं अपना प्रदर्शन सुधारने पर मजबूर होना पड़ा है।

बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को लेकर भारतीय दृष्टिकोण में नए किस्म की वह गंभीरता देखने को मिली जिसका पहले अभाव नजर आता था। बीआरआइ के विरोध के साथ ही भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त परियोजनाओं से भी समान दूरी बनाकर इस मोर्चे पर संतुलन बिठाया है। इसके बजाय भारत द्विपक्षीय साझेदारियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके लिए दक्षिण एशिया में वह जापान के साथ काम कर रहा है। भारत एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं वाले मॉडल को तरजीह दे रहा है।

बीआइआइ को लेकर शुरुआती विरोध के बावजूद भारत इससे जुड़े मुद्दों पर वैश्विक विमर्श को दिशा दे रहा है। भविष्य में यह भारतीय नीति निर्माताओं पर निर्भर करेगा कि वे चीनी परियोजनाओं पर उठते संदेह के बादलों के चलते बनने वाले अवसरों को किस तरह भुनाते हैं ताकि भारत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने वाले बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर सके।

(Adapted from Jagran.com)

24. BCIM corridor out of China's BRI- चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से भारत की मौजूदगी वाले बीसीआईएम कॉरिडोर को बाहर किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

चीन ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) प्रोजेक्ट से बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार (बीसीआईएम) इकोनॉमिक कॉरिडोर को हटा दिया है। चीन ने रविवार को बीआरआई प्रोजेक्ट की नई सूची जारी की। शनिवार को खत्म हुए दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) में 37 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। इसमें 64 बिलियन डॉलर (करीब 4 लाख करोड़ रुपए) डील हुई। साथ ही कहा गया कि बीआरआई किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करेगा।

पहला बीआरएफ 2017 में हुआ था। इसमें भारत यह कहते हुए शामिल नहीं हुआ था कि चीन-पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है। सीपीईसी, पाक के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से गुजरेगा।

नई सूची में दक्षिण एशियाई के कई कॉरिडोर के नाम

बीआरएफ के अंत में संयुक्त बयान जारी करते हुए कनेक्टीविटी के लिए कई कॉरिडोर के नाम जारी किए। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सीपीईसी, नेपाल-चीन ट्रांसहिमालयन मल्टी डाइमेंशनल कनेक्टीविटी नेटवर्क, नेपाल-चाइना क्रॉस बॉर्डर रेलवे और चीन-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीएमईसी) शामिल हैं।

2013 में बीआरआई लॉन्च किया गया था। तब बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका हिस्सा था। अब बीआरआई की नई लिस्ट में 35 कॉरिडोर शामिल हैं लेकिन बीसीआईएम बाहर है।

2800 किमी प्रस्तावित था बीसीआईएम कॉरिडोर

बीसीआईएम इकोनॉमिक कॉरिडोर 2800 किमी का प्रस्तावित था। इसे चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग से कोलकाता तक बनाया जाना था। यह कॉरिडोर म्यांमार के मांडले और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भी होकर गुजरता।

1700 किमी लंबा चीन-म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन को हिंद महासागर तक पहुंच बनाने में एक और जरिया साबित होगा। यह चीन के युन्नान से मांडले में खत्म होगा। इसी तरह नेपाल-चीन ट्रांस-हिमालयन कनेक्टीविटी नेटवर्क चीन के चेंगडू से शुरू होकर तिब्बत को जोड़ते हुए नेपाल में खत्म होगा।

हमारा मकसद सभी का फायदा: जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि हमें व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान और साझा हितों के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी की राय सुनी जाती हैं, सभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं और सभी आपसी फायदे के लिए एकसाथ खड़े होते हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

25. 200 American companies to shift manufacturing bases from America to India- 200 अमेरिकी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

लोकसभा चुनावों के बाद करीब 200 अमेरिकी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से भारत में शिफ्ट करना चाहती हैं। अमेरिका के प्रमुख एडवोकेसी ग्रुप यूएस-इंडिया स्ट्रैटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) का ऐसा कहना है। फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक भारत में निवेश के लिए कंपनियां उनसे बात कर रही हैं।

सरकार को जमीन से लेकर कस्टम तक के मुद्दों पर ध्यान देना होगा: अघी

1. अघी का कहना है कि भारत में जो भी नई सरकार बनेगी उससे रिफॉर्म में तेजी लाने और फैसले लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का अनुरोध किया जाएगा। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अघी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 से 18 महीने में ई-कॉमर्स और डेटा लोकलाइजेशन जैसे मामलों में जो फैसले लिए उन्हें अमेरिकी कंपनियां ग्लोबल की बजाय घरेलू नजरिए से लिए गए फैसल मान रही हैं।

2. अघी के मुताबिक नई सरकार को यह समझना पड़ेगा कि अमेरिकी कंपनियों को कैसे आकर्षित किया जाए। इसके लिए जमीन से लेकर कस्टम तक के मुद्दों पर ध्यान देना होगा। आगे बहुत ज्यादा सुधारों की जरुरत है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेंगे।

3. यूएसआईएसपीएफ के अध्यक्ष अघी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर विचार करने की जरूरत है। इससे भारत को फायदा होगा। अगर भारत चीन से आने वाले सस्ते सामान के बारे में चिंतित है तो एफटीए से यह जरूरत पूरी हो जाएगी।

4. अघी का कहना है कि हमने अपनी सदस्य कंपनियों की उच्च स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग काउंसिल बनाई है। उनका कहना है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए बैकअप स्ट्रैटजी की जरूरत है। लेकिन, छोटे-छोटे मुद्दे उन्हें पीछे खींच सकते हैं। ज्यादातर कंपनियां चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। वो कंपनियां भारत आएंगी तो बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश भी आएगा। पिछले 4 सालों में हमारी सदस्य कंपनियों ने 50 अरब डॉलर का निवेश किया है।

(Adapted from Bhaskar.com)

26. ISIS chief Baghdadi's video- 5 साल बाद सामने आया आईएस सरगना बगदादी, श्रीलंका में हमले की जिम्मेदारी ली (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

आतंकी संगठन आईएस के सरगना अबु बकर अल-बगदादी का पांच साल बाद पहली बार वीडियाे सामने आया। इससे उसके जिंदा हाेने की अटकलें शुरू हाे गई हैं। सोमवार को आईएस ने एक वीडियाे जारी किया, जिसमें बगदादी काे दिखाया गया। अभी साफ नहीं है कि यह वीडियो कब शूट किया गया। इसके अलावा कथित तौर पर आईएस सरगना का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें उसने 21 अप्रैल को श्रीलंका में हुए धमाकों को आईएस के आखिरी गढ़ बगाैज में मारे गए आतंकियों का बदला बताया है। इन धमाकों में 253 लोग मारे गए थे। 18 मिनट का यह वीडियो आईएस के अल फुकरान मीडिया नेटर्वक ने जारी किया, जिसे सोमवार को अलजजीरा चैनल ने भी प्रसारित किया। इसमें बगदादी घनी दाढ़ी में दिखाई दे रहा है और तीन लाेगाेंं काे संबाेधित कर रहा है, जिनके चेहरे साफ नहीं हैं। इसमें बगदादी ने सीरिया में आईएस के आखिरी गढ़ बगाैज में लड़ाई का जिक्र किया है। वीडियाे में बगदादी

कहता है, यह लड़ाई अब खत्म हाे चुकी है। इसके बाद और लड़ाई आने वाली हैं, जो दुश्मन के खिलाफ कयामत तक जारी रहेंगी।

बगदादी ने 2014 में खुद को खलीफा घोषित किया था

बगदादी को आखिरी बार 2014 में एक मस्जिद में देखा गया था। तब भाषण देते हुए उसने खुद को ईराक और सीरिया का खलीफा घोषित किया था। ईराक-सीरिया में अमेरिका और उसकी सहयोगी सेनाओं ने आईएस के आतंकियों से लंबी लड़ई लड़ी। पिछले महीने अमेरिका सेना ने आईएस के आखिरी गढ़ बगाैज से आतंकियों के खात्मे का दावा किया था। संयुक्त सेना की कार्रवाई में कई बार बगदादी के मारे जाने की खबरें आई थीं।

(Adapted from The Bhaskar.com)

अर्थशास्त्र

1. Last date to link PAN card and Aadhar- PAN Card और Aadhaar Card लिंक करने की अंतिम तारीख अब 30 सिंतबर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

अंतिम तारीख एक बार फिर टाल दी गई

PAN card को Aadhaar card से लिंक करने की अंतिम तारीख एक बार फिर टाल दी गई है। पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 तक रखी थी। लेकिन अब सरकार ने PAN (Permanent Account Number) और बायोमैट्रिक आईडी Aadhaar को लिंक करने अंतिम तारीख 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना अनिवार्य रहेगा। यह छठा मौका है जब केंद्र सरकार ने PAN card Aadhaar card link के डेडलाइन बढ़ाई है।

याद रहे कि बीते साल जून महीने में सरकार ने कहा था कि देश के हर नागरिक को 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कर लेना होगा।

बताया गया है कि भले ही दोनों की कार्ड को लिंक की तारीख आगे बढ़ाई गई है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार कार्ड का ज़िक्र करना अनिवार्य होगा।

याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल केंद्र सरकार के आधार कानून को संवैधानिक तौर पर वैध माना था। साथ ही कहा था कि आईटी रिटर्न फाइल करने या पैन कार्ड के आवेदन के लिए आधार अनिवार्य होगा।

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के ये हैं तरीके

आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling।gov।in/) पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा।

1। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

2। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें।

3। यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें।

4। इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें।

5। अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।

6। इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें।

बता दें कि यह तरीका तब ही काम करेगा जब पैन कार्ड और आधार कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल खाते हैं। जिन लोगों के दोनों कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, उनके लिए सरकार ने इस प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी। इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी कूटसंदेश (वन टाइम पासवर्ड) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। ऐसा लगता है कि अभी इस विकल्प को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345।इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।

हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के जरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

2. **Regulatory sandbox guidelines-पेमेंट बैंक प्रमुखों से मिलेंगे RBI गवर्नर, सैंडबॉक्स गाइडलाइन जल्द (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)**

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास इस हफ्ते देश के अलग-अलग पेमेंट बैंक के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। शक्तिकांत दास की यह मुलाकात पेमेंट बैंक की दिक्कतों और उनकी समस्याओं को समझने के लिए है। शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा, "पेमेंट बैंकों के प्रमुखों से इस हफ्ते बैठक होगी। इस बैठक में पेमेंट बैंक की दिक्कतों और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की जाएगी।"

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगे कहा कि देश में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के मद्देनजर रिजर्व बैंक की निगरानी में छोटी कंपनियों को रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स की सुविधा देने को लेकर अगले दो महीने में दिशा-निर्देश जारी किये जाएंगे। सैंडबॉक्स तरीका एक ऐसा माध्यम है जो किसी नयी तकनीक या प्रणाली को अमल में लाने से पहले प्रयोग करने और सीखने की सहूलियत देता है। बता दें कि अभी तक 7 पेमेंट बैंक परिचालन शुरू कर चुके हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में बैंकिंग सेवाओं को घर-घर पहुंचाने के लिए पेमेंट बैंकों को कारोबार करने की इजाजत दी थी।

आरबीआई की बैठक 2 अप्रैल से

यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 2 से 4 अप्रैल को होनी है। इस नए वित्त वर्ष में मौद्रिक नीति समिति की कुल 6 बैठकें होंगी। आरबीआई के अनुसार एमपीसी की दूसरी बैठक 3,4 और 6 जून को, तीसरी बैठक 5 से 7 अगस्त को, चौथी बैठक 1, 3 और 4 अक्टूबर को, पांचवीं बैठक 3 से 5 दिसंबर तथा छठी बैठक 4-6 फरवरी 2020 को होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली समिति में केंद्रीय बैंक के दो प्रतिनिधि तथा तीन बाहरी सदस्य होते हैं।

(Adapted from aajtak.intoday.in)

3. Jet airways in financial touble- जेट एयरवेज ने 16 हजार कर्मियों की सैलरी रोकी, मंत्री ने इसे कंपनी का आंतरिक मामला बताया(Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

कर्ज में डूबी एयरलाइन जेट एयरवेज ने बुधवार को कहा कि कंपनी अपने 16,000 कर्मचारियों को मार्च 2019 की सैलरी नहीं दे पाएगी। कंपनी लगातार इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, "यह मामला बैंक और मैनेजमेंट के बीच का है। मंत्रालय इसमें किसी भी तरह से कोई डील नहीं कर रहा है।"

अधिकारी ने कहा- हालात ठीक करने में समय लगेगा

जेट एयरवेज के अधिकारी राहुल तनेजा ने कहा, "जेट एयरवेज मैनेजमेंट कंपनी के बेहतर संचालन और स्थिर भविष्य को लेकर काम कर रहा है। इसके लिए कुछ संस्थानों और कर्ज देने वालों से भी संपर्क किया जा रहा है। हालांकि इस तरह की परेशानियों को हल करने में अपेक्षा से ज्यादा समय लगता है। हम लगातार इसे ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान हालात में मार्च 2019 की सैलरी नहीं दी जा सकेगी।"

बीते कुछ महीनों से नहीं मिली है सैलरी

जेट एयरवेज कर्मचारियों को कब तक सैलरी दे पाएगी, इसका अपडेट 9 अप्रैल को मिलेगा। कंपनी बीते कुछ महीनों से पायलट, क्रू और कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे पाई है।

गोयल ने कहा- मैं हर शर्त मानने को तैयार

जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल ने जारी किए गए बयान में कहा, "मैं जेट एयरवेज के सुरक्षित भविष्य के लिए कर्ज देने वालों की हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। मैंने उन्हें समाधान योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर हर तरह की सहूलियत दे दी है।"

(Adapted from Bhaskar.com)

4. Pension on the basis of full salary in private sector- निजी क्षेत्र में पूरी सैलरी पर पेंशन का रास्ता साफ, अधिकतम 15 हजार का फॉर्मूला लागू नहीं होगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निजी क्षेत्र की कंपनियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। केरल हाईकोर्ट ने सितंबर 2014 के फैसले में अधिकतम 15 हजार रुपए मासिक वेतन पर ही पेंशन की गणना का नियम खत्म कर दिया था। साथ ही आखिरी साल के औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन तय करने का पुराना नियम बहाल कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। उसने कहा कि ईपीएफओ की अपील में कोई मेरिट नहीं है।

केंद्र सरकार की 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना के कर्मचारी के अंशदान के अलावा वेतन का 8.33% योगदान नियोक्ता को देना था। लेकिन, नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन की सीमा अधिकतम 6500 रुपए सालाना के आधार पर 8.33% तय कर दी गई। मार्च 1996 में सरकार ने इस नियम में संशोधन किया और नियोक्ता और कर्मचारी को आपत्ति ना होने की स्थिति में पेंशन का योगदान पूरे वेतन का 8.33% कर दिया।

1 सितंबर 2014 को ईपीएफओ ने नियम में संशोधन करते हुए 8.33% के योगदान के लिए 15 हजार की सीमा तय कर दी। इसके साथ ही कहा गया कि पूरी सैलरी पर पेंशन चाहने वाले लोगों का औसत वेतन पिछले 5 साल के दौरान मिले वेतन के आधार पर तय किया जाएगा। हालांकि, इस नियम के चलते कुछ कर्मचारियों को पेंशन में घाटा हो गया, क्योंकि पिछले नियम के तहत पेंशन एक साल की औसत सैलरी के आधार पर तय की जाती थी।

केरल हाईकोर्ट ने इस संशोधन पर रोक लगा दी और पुराने नियम को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2016 में ईपीएफओ को निर्देश दिया कि पूरी सैलरी के आधार पर कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह रास्ता साफ हो गया है।

1) मौजूदा नियमों के तहत 2029 में रिटायरमेंट, 33 वर्ष की नौकरी और 50 हजार रुपए अंतिम मासिक वेतन पर अभी इस तरह पेंशन तय करने का नियम है :

2014 में ईपीएफओ ने अधिकतम 15 हजार रुपए/महीना पर पेंशन तय करने का नियम बनाया था। इससे पहले 1996 में 6500 रुपए/महीना पर पेंशन तय करने का नियम था। इसलिए 33 वर्ष की नौकरी को दो हिस्सों में बांटा जाता है और उसी पर गणना होती है।

a) 2014-1996 = 18 साल

(18 वर्ष की नौकरी + 1.1 बोनस वर्ष)/70 * 6500 = 1773/-

b) 2029-2014 = 15 साल

(15 वर्ष की नौकरी + 0.9 बोनस वर्ष)/70 * 15000 = 3407/-

इस तरह मौजूदा नियमों के तहत 50 हजार रुपए के अंतिम वेतन पर भी 1773+3407 यानी 5180 रुपए प्रति माह की पेंशन ही तय होगी।

2) सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएफओ की याचिका खारिज कर देने के बाद केरल हाईकोर्ट का फैसला लागू हो गया। इससे अंतिम और पूर्ण वेतन पर पेंशन तय होगी। इसकी गणना इस तरह होगी:

(33 वर्ष की नौकरी + 2 बोनस वर्ष)/70 *15000 = 25000/-

इस तरह नया नियम लागू होने पर 50 हजार रुपए के अंतिम वेतन पर 25 हजार रुपए प्रति माह की पेंशन मिल सकेगी।

(Adapted from bhaskar.com)

5. High chances of Mallya's- extradition प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ माल्या की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (62) की प्रत्यर्पण के खिलाफ अर्जी हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने दिसंबर में माल्या के भारत प्रत्यर्पण की इजाजत दी थी। फरवरी में यूके के गृह विभाग ने भी मंजूरी दे दी थी। उसके बाद माल्या ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया

माल्या के खिलाफ फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा के उल्लंघन का आरोप है। माल्या पर भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। उसकी किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंकों से लोन लिया था। माल्या 2016 में लंदन भाग गया। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे भगोड़ा घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है।

(Adapted from Bhaskar.com)

6. Relation between Fiscal deficit and economic growth- वित्तीय घाटे ओर आर्थिक विकास के बीच में संबंध (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

अगर सरकार की आय कम हो तो अपने खर्च पूरा करने के लिए वह ऋण लेती है। यही ऋण वित्तीय घाटा कहलाता है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एकमत हैं। दोनों ने वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने की बात कही है। विषय को समझने के लिए जानना होगा कि इस मंत्र की शुरुआत कहां और क्यों हुई। बात अस्सी के दशक की है। दक्षिण अमेरिकी देशों के नेताओं ने भारी मात्रा में नोट छापे और उस रकम को तिकड़ में कर अपने स्विस बैंक खातों में जमा कराते गए। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं संकट में फंसने लगीं। चूंकि भारी मात्रा में नोट छापे जा रहे थे। इससे एक तरफ महंगाई बढ़ रही थी तो दूसरी ओर आर्थिक विकास दर न्यून बनी हुई थी, क्योंकि इन देशों की अपनी पूंजी बाहर जा रही थी। इस परिस्थिति में अमेरिका ने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की नीति बनाई। कहा गया कि विकासशील देशों की सरकारों को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए।

खर्च करने के लिए ऋण लेना बंद करना चाहिए। इसके पीछे सोच यह थी कि यदि विकासशील देशों की सरकारें वित्तीय घाटे को नियंत्रण में रखेंगी तो विदेशी निवेशकों का उन पर भरोसा बढेगा, विदेशी निवेश आएगा और आर्थिक विकास का पहिया घूमने लगेगा। मूल बात यह है कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण करने का मंत्र विकासशील देशों की सरकारों के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के अस्त्र के रूप में निर्मित हुआ था। इस मंत्र को अपनाकर सरकार परोक्ष रूप से स्वीकार करती है कि वह भ्रष्ट है। उसे अपनी ईमानदारी पर भरोसा नहीं है इसलिए खर्च ही कम कर देना चाहिए। जैसे यदि साफ-सुथरा भोजन बनाने का स्वयं पर भरोसा न हो तो भोजन बनाना ही बंद कर दिया जाए और होटल में जाकर भोजन किया जाए।

वित्तीय घाटे के दो हिस्से होते हैं। एयरपोर्ट और हाईवे बनाने जैसे पूंजी निवेश करने के लिए लिए गए ऋण को पूंजी घाटा कहा जाता है। अपने कर्मियों को वेतन देने अथवा अन्य खपत के लिए लिए गए ऋण को राजस्व अथवा चालू घाटा कहा जाता है। वित्तीय घाटे में पूंजी घाटा और चालू घाटा दोनों सम्मिलित होते हैं। अत: वित्तीय घाटे को पूंजी घाटे को कम करके यानी निवेश कम करके या चालू घाटे को कम करके यानी खपत को कम करके या दोनों तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि हमने वित्तीय घाटे पर नियंत्रण मुख्य रूप से निवेश कम करके किया है। वर्ष 2010 में हमारा वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.5 प्रतिशत था जो 2016 में 3.9 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि में सरकार के कुल खर्चों में विकास कार्यों का हिस्सा 57 प्रतिशत से घटकर 52 प्रतिशत रह गया है। अत: वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के साथ-साथ हमारे विकास कार्यों अथवा पूंजी निवेश में कमी आई है। विकास खर्चों की यह कमी ही हमारी आर्थिक विकास दर को सात प्रतिशत पर ही रोके हुए है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है।

एक दुकानदार ऋण लेकर मोटर साइकिल खरीदता है। वह अपनी दुकान पर सुबह समय से पहुंच जाता है। उसकी बिक्री बढ़ती है, मुनाफा बढ़ता है और वह मोटर साइकिल के लिए लिए गए ऋण की अदायगी कर देता है। इसी प्रकार यदि सरकार ऋण लेकर हाईवे बनाती है तो देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, व्यापारियों द्वारा टैक्स अधिक अदा किया जाता है और उस टैक्स से सरकार हाईवे बनाने के लिए लिए गए ऋण को अदा कर सकती है। इसके विपरीत यदि दुकानदार विदेशी पर्यटन के लिए ऋण ले तो उसकी आय पूर्ववत रहती है, जबकि उसे ऋण की अतिरिक्त अदायगी करनी होती है। तब वही ऋण भारी पड़ता है। इसी प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में यदि सरकार ऋण लेकर खपत को पोषित करे तो आय नहीं बढ़ती है, परंतु ऋण की अतिरिक्त अदायगी करनी होती है। तब वही ऋण भारी पड़ता है। इस प्रकार चालू घाटा देश की अर्थव्यवस्था को ले डूबता है।

पूंजी खर्चों के लिए यदि वित्तीय घाटे को बढ़ाया जाए तो सार्थक परिणाम आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज, बंगलुरु ने भारत की अर्थव्यवस्था का 1980 से 2013 की अवधि के बीच अध्ययन किया और पाया कि जिस समय वित्तीय घाटे से अर्जित धन को पूंजी निवेश के लिए उपयोग किया गया था उस दौरान विकास दर बढ़ी थी। अमेरिका की डीलर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बांग्लादेश पर किए एक अध्ययन में कहा गया कि कुछ हद तक वित्तीय घाटा आर्थिक विकास के लिए लाभप्रद होता है, यदि ऋण का उपयोग अच्छी योजनाओं को पोषित करने के लिए किया जाए। रिजर्व बैंक के दो पूर्व गवर्नरों सी रंगराजन और डी सुब्बाराव ने वित्तीय घाटे को काबू करने की वकालत की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि दीर्घकालीन विकास के लिए हमें चालू घाटे पर नियंत्रण करना होगा और ऋण का उपयोग निवेश के लिए करना होगा। वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम के एक अध्ययन में कहा गया है कि वित्तीय घाटे और आर्थिक विकास के बीच संबंध संदिग्ध है। इस प्रकार के तमाम अध्ययनों से साबित होता है कि वित्तीय घाटे पर नियंत्रण से विकास नहीं होता है, बल्कि यदि वित्तीय घाटे को बढ़ाकर निवेश किया जाए तो अर्थव्यवस्था में सार्थक प्रगति होती है। भारत की विकास दर के सात प्रतिशत पर टिके रहने का एक प्रमुख कारण है कि हमने अपना ध्यान वित्तीय घाटे के नियंत्रण पर ही लगा रखा है।

यहां से हम दो अलग-अलग रास्ते पकड़ सकते हैं। भाजपा तथा कांग्रेस ने कहा है कि वे वित्तीय घाटे को नियंत्रित करेंगे। इसका अर्थ है कि निवेश में कटौती जारी रहेगी। उनके द्वारा चालू घाटे में कटौती करने की बात नहीं की जाती है। ये सरकारी खपत पर नियंत्रण करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी विकास दर वर्तमान सात प्रतिशत के इर्दगिर्द ही रहने की संभावना है। सच यह है कि अमेरिकी सरकार, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने वित्तीय घाटे के मंत्र को पढ़ाकर हमें अपने पूंजी खर्चों में कटौती करने को प्रेरित किया है।

फिर निवेश की इस कमी की पूर्ति के लिए उन्होंने हम पर दबाव डाला कि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश दें जिससे कि विकसित देशों के हितों को बढ़ाया जा सके। इससे हमारी विकास दर बढ़ नहीं रही है और हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऋण तले दबते जा रहे हैं। हमें वित्तीय घाटे के नियंत्रण के मंत्रको कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। इसके स्थान पर चालू घाटे के नियंत्रण के मंत्र को लागू करना चाहिए। सरकार को पूंजी निवेश के लिए ऋण लेने की छूट मिलनी चाहिए एवं इसके लिए वित्तीय घाटे को बढ़ने देना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े और हमारी विकास दर में गति आए।

7. Gold reserves with various nations-चीन लगातार खरीद रहा सोना, भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना अधिक गोल्ड रिजर्व (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

भारतीयों में गोल्ड (सोना) को लेकर जबरदस्त क्रेज रहा है। लेकिन पिछले दशक के दौरान यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का पसंदीदा विकल्प बनकर सामने आया है। 2018 में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा किया है।

हालिया आई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास करीब 607 टन सोने का सुरक्षित भंडार है, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुकाबले दस गुना अधिक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सोने का कुल भंडार 64.6 टन का है।

रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल के वर्षों में गोल्ड के प्रति रुचि दिखाई है, जिसकी वजह से उसके रिजर्व में इजाफा हुआ है। लगातार चौथे महीने चीन के गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। चीन के पीपुल्स बैंक के पास करीब 1,864.30 टन सोने का भंडार है और वह सातवें स्थान पर बना हुआ है।

गोल्ड रिजर्व के मामले में पांच शीर्ष देशों की स्थिति पर एक नजर-

1.अमेरिका-8,133.50 टन
2.जर्मनी-3,369.70 टन
3.इटली-2,451.80 टन
4.फ्रांस-2,436 टन
5. रूस-2,149.20 टन

रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कुल 2,814 टन सोने का भंडार है। जबकि 1,040 टन के भंडार के साथ स्विट्जरलैंड, 765.20 टन के भंडार के साथ जापान और 612.50 टन के भंडार के साथ नीदरलैंड इस सूची में भारत से ऊपर है।

(Adapted from Jagran.com)

8. Population increase of India- 1/2% की दर से बढ़ रही भारतीय आबादी, चीन से दोगुनी तेज; प्रति महिला 2 से ज्यादा बच्चे (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड 2019 की एक रिपोर्ट ने भारतीय जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जनसंख्या चीन के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रही है। 2010 से 2019 के बीच भारत में 1/2% की सालाना दर से जनसंख्या बढ़ी है। जबकि इसी दौरान चीन की जनसंख्या वृद्धि दर 0/5% रही है। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और चीन का पहला स्थान है। भारत की जनसंख्या 136 करोड़ है, जबकि चीन की आबादी 142 करोड़ है।

भारत की जनसंख्या वृद्धि पाक से कम

देश का नाम	औसत आयु
जापान	84
ब्रिटेन	82
अमेरिका	80
चीन	77
रूस	71
भारत	69
पाकिस्तान	67

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एक महिला औसतन 2/3 बच्चों को जन्म दे रही है। इस जन्म औसत में पिछले पांच दशकों में काफी सुधार देखा गया है। 1969 में यह दर 5/6 थी। यदि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा देखा जाए, तो यह अभी 2/5 है। यदि औसत आयु की बात करें तो 2019 में यह 69 वर्ष (जीवन प्रत्याशा) है, जो 1969 में यह मात्र 47 साल थी।

इन देशों में एक महिला द्वारा बच्चों की औसतन जन्म दर

देश का नाम	जन्म दर
पाकिस्तान	3।3
इंडोनेशिया और भारत	2।3
अमेरिका	1।9
ब्राजील	1।7
चीन	1।6

पढ़ाई में पाक हमसे बहुत पीछे

• भारत- सेकंडरी स्कूलों में साल 2009 से 2018 के बीच सिर्फ 61 फीसदी लड़कों ने एडमिशन लिया है। लड़कियों के मामले में यह आंकड़ा 62% है।

• पाकिस्तान- सेकंडरी स्कूलों में साल 2009 से 2018 के बीच सिर्फ 49% लड़कों ने एडमिशन लिया है। लड़कियों के मामले में यह आंकड़ा 40% है।

अभी विश्व के बड़े देशों की औसत आयु

देश का नाम	औसत आयु
जापान	84
ब्रिटेन	82
अमेरिका	80
चीन	77
रूस	71
भारत	69
पाकिस्तान	67

(Adapted from Bhaskar.com)

9. SC stopped Arcelor Mittal fom making payment in Essar Steel case- एस्सार स्टील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल को भुगतान करने से रोका (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

एस्सार स्टील दिवालिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्सेलरमित्तल को 42,000 करोड़ रुपए के भुगतान से रोकते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) को इस केस से जुड़ी याचिकाओं पर जल्दी फैसला लेने को कहा है।

एस्सार स्टील के लिए आर्सेलरमित्तल की बोली को एनसीएलएटी की मंजूरी मिलने से कर्जदाताओं को बड़ी राहत मिली थी। एनसीएलएटी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल की 42 हजार करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दी थी।

पृष्ठभूमि

एनसीएलएटी ने कहा था कि वह एलएन मित्तल की कंपनी को 23 अप्रैल को अगली सुनवाई के दौरान एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपए की राशि को एक अलग खाते में जमा करने का निर्देश दे सकता है। ट्रिब्यूनल ने आर्सेलरमित्तल से एक हलफनामा भी देने को कहा था जिसमें कर्ज में डूबी एस्सार स्टील की समाधान योजना के क्रियान्वयन को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे इस बारे में पूरा ब्यौरा हो।

(Adapted from Bhaskar.com)

10. Story of Jet Airways- जानें, बदहाली की कगार पर कैसे पहुंची कभी अरबों डॉलर का मुनाफा कमाने वाली जेट एयरवेज (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Economics)

पिछले कई दिनों से मदद के लिए पंख फड़फड़ाती विमानन कंपनी जेट एयरवेज को मदद के अभाव में आखिरकार उड़ने की सभी उम्मीदें छोड़कर जमीन पर उतर जाना पड़ा। कंपनी ने बुधवार रात को अपनी आखिरी फ्लाइट संचालित की और गुरुवार से सभी उड़ानें अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया। बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई वाले बैंकों के कर्जदाता समूह ने जेट को 400 करोड़ रुपये की आपात वित्तीय मदद देने से इन्कार कर दिया।

जेट की अंतिम फ्लाइट

श्री गुरु रामदास अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजासांसी से बुधवार रात सवा दस बजे जेट एयरवेज की फ्लाइट ने अपनी अंतिम उड़ान भरी। इसमें 91 यात्री थे। जेट की दिल्ली-अमृतसर-मुंबई फ्लाइट बुधवार रात साढ़े नौ बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरी। इसी फ्लाइट ने रात सवा दस बजे मुंबई के लिए उड़ान भरी।

जेट की दुर्गति से 20 हजार नौकरियों पर तलवार

गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही जेट एयरवेज का परिचालन अस्थायी तौर पर बंद होने से कंपनी के करीब 20,000 कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। कंपनी के पास अपनी उड़ानों को चालू रखने के लिए पूंजी नहीं है, लिहाजा उड़ानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वर्तमान हालत यह है कि उस पर कर्जदाताओं के 8,000 करोड़ रुपये के अलावा कर्मचारियों का तीन महीने से ज्यादा वेतन, विमान पट्टेदारों का बकाया और रद हुई उड़ानों के एवज में यात्रियों का करोड़ों रुपये का रिफंड भी बकाया भुगतान करना है।

रद हो सकता है लाइसेंस

नागरिक विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक, यदि जेट की उड़ानें शीघ्र बहाल न हुईं तो इसका एयर ऑपरेटर लाइसेंस भी रद हो सकता है।इस बीच जेट एयरवेज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गुरुवार को दिल्ली में जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने का निर्णय लिया है। गुरुवार को ही सुबह इनकी यूनियन के पदाधिकारी जेट एयरवेज के मुंबई स्थित मुख्यालय सिरोया सेंटर में प्रबंधन से मुलाकात करेंगे। बुधवार को दिन में जेट एयरवेज के पांच-छह विमानों ने कुछ घरेलू उड़ाने भरीं, लेकिन इनमें यात्रियों की संख्या काफी कम थी।

परेशानी का सामना

जेट की उड़ाने बंद होने का असर दूसरी एयरलाइंस पर भी पड़ने लगा है। एक तरफ तो उनकी बुकिंग अचानक बढ़ गई है। दूसरी तरफ बढ़ती मांग की भरपाई के लिए अतिरिक्त संसाधन झोंकने में उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इन विमानन कंपनियों ने पायलटों की कमी से उबरने के लिए जेट के पायलटों को ऑफर देना शुरू कर दिया है। लेकिन, साढ़े तीन महीने से वेतन नहीं मिलने के बावजूद जेट के 1,100 पायलटों में बहुत कम इसे छोड़ने के इच्छुक हैं और एयरलाइन के साथ रहकर ही संघर्ष करना चाहते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि स्पाइसजेट जैसी लो-कॉस्ट विमानन कंपनियों ने जेट के इच्छुक पायलटों को उनके मौजूदा वेतन के मुकाबले 30 फीसद तक कम वेतन ऑफर किया है।

यात्री हुए हलकान

कई यात्रियों ने जेट की उड़ानों की अनिश्चितता से होने वाली परेशानियों के बारे में सरकार से शिकायत की है। वहीं, कई यात्री सोशल मीडिया के जरिए अपना कष्ट बयां कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।

संकट का निवारण

कंपनी की दिक्कत यह है कि सरकार ने भी बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जेट एयरवेज के संकट का निवारण मौजूदा रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क के तहत करेगी। लेकिन यात्रियों की समस्याओं का निवारण उसकी प्राथमिकताओं में ऊपर है। नागरिक विमानन मंत्रलय ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट में कहा कि मंत्रलय के सचिव प्रदीप सिंह खरोला गुरुवार को भी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे।

ऐसे आए बुरे दिन

- 3 अगस्त, 2018 को कंपनी ने उन खबरों का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि वह 60 दिनों से ज्यादा उड़ान नहीं भर सकती
- 11 अगस्त, 2018 को एसबीआइ चेयरमैन ने कहा कि जेट एयरवेज के कर्ज को 'वॉच' लिस्ट में रखा गया है
- 27 अगस्त, 2018 को कंपनी को उससे पिछली जून तिमाही में नुकसान हुआ, कंपनी ने कहा कि वह पूंजी निवेश करेगी और खर्च में 2,000 करोड़ रुपये की कटौती करेगी।
- 6 सितंबर, 2018 को कंपनी ने कहा कि वह 84 फीसद कर्मियों को अगस्त का वेतन दे पाई है।
- 5 नवंबर, 2018 को खबरें आईं कि टाटा ग्रुप जेट एयरवेज में 51 फीसद हिस्सेदारी खरीदना और उसका विलय विस्तारा एयरलाइंस में करना चाहता है।
- दिसंबर में एतिहाद एयरवेज द्वारा जेट एयरवेज के कर्जदाताओं से बातचीत की खबरें आईं।
- इस वर्ष जनवरी में एतिहाद ने मौजूदा हालात में जेट एयरवेज में नए निवेश से असमर्थता जताई।
- फरवरी में पट्टेदारों को बकाया भुगतान में विफलता के बाद चार विमानों का परिचालन रोका।
- फरवरी में ही जेट के निदेशक बोर्ड ने समाधान प्रक्रिया को मंजूरी देते हुए कर्जदाताओं को सबसे बड़ा शेयरधारक बना दिया।
- समाधान शर्तों के तहत मार्च में संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने कंपनी के निदेशक बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

यूं शुरू हुआ था सफर

- जेट एयरवेज की स्थापना पहली अप्रैल 1992 को नरेश गोयल के पुत्र निवाण व पुत्री नम्रता गोयल की कंपनी टेलविंड्स द्वारा की गई थी।
- इसने 5 मई, 1993 को मुंबई व अहमदाबाद से एयर टैक्सी ऑपरेटर के तौर पर अपने ऑपरेशंस शुरू किए।
- 12 मई, 1994 को जेट एयरवेज के सारे शेयर टेलविंड्स का ट्रांसफर कर दिए गए। टेलविंड्स में उस समय नरेश गोयल की इक्विटी 60 फीसद, जबकि गल्फ एयर और कुवैत एयर की 20-20 फीसद थी।

- 14 जनवरी, 1995 को इसे शेड्यूल्ड एयरलाइन का दर्जा मिला।
- इसकी पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान 2004 को दिल्ली से काठमांडू के लिए हुई थी।
- 2005 में इसने अपना पहला इक्विटी इश्यू निकाला।
- 2007 में इसने एयर सहारा को खरीद लिया और उसे जेटलाइट नाम दिया।
- 2008 में जेटलाइट का जेट एयरवेज में विलय कर दिया।
- 2009 में जेट एयरवेज ने जेट कनेक्ट नाम से एक और लो कॉस्ट सब्सिडियरी लांच की 2010 में कंपनी ने नंबर-वन एयरलाइन का दर्जा हासिल कर लिया।
- उसके बाद लो-कॉस्ट एयरलाइंस से स्पर्धा के चलते वर्ष 2012 में जेट एयरवेज दूसरे स्थान पर खिसक गई।
- नवंबर, 2013 में कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एयरलाइन एतिहाद एयरवेज के हाथों 24 फीसद इक्विटी बेचने का निर्णय लिया।
- अक्टूबर, 2017 तक जेट एयरवेज देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी हुई थी। इसके पास 23,000 कर्मचारियों के अलावा 124 विमानो का विशाल बेड़ा था। कंपनी देश-विदेश के 52 शहरों के लिए उड़ाने संचालित कर रही थी।
- वित्त वर्ष 2017-18 में जेट एयरवेज 252 अरब डॉलर के राजस्व के साथ 6.3 अरब डॉलर के लाभ में थी।

(Adapted from Jagran.com)

11. WTO Negotiations on Agriculture is full of challenges for India- विश्व व्यापार संगठन की चिंता जनक रिपोर्ट, खेती के मोर्चे पर भारत की नई चुनौतियां (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

आम चुनाव के इस दौर में जब खेती-किसानी के सवाल भी सामने आ रहे हैं तब इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि विश्व व्यापार संगठन यानी डब्लूटीओ यह चाह रहा है कि गेहूं, चावल, दलहन, कपास और गन्ने के खरीद मूल्यों में कटौती की जाए। अगर ऐसा हुआ तो किसानों की आफत और बढ़ सकती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और गन्ने जैसी फसलों के मामले में उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी को घटाने को लेकर डब्लूटीओ तब दबाव डाल रहा है कि जब नीति आयोग ने यह स्वीकार किया है कि बीते दो वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में लगभग शून्य बढ़ोतरी हुई है।

चीनी पर भारत की बढ़ती सब्सिडी को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील इस मसले को डब्लूटीओ के विवाद निपटान पैनल में उठा रहे हैं जहां व्यापार संबंधी विवादों का समाधान होता है। उनके अलावा ग्वाटेमाला, यूरोपीय संघ, रूस, कोस्टारिका और थाईलैंड भी इस मामले में पक्ष बनना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इन देशों ने भी भारत में चीनी पर दी जा रही सब्सिडी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जहां डब्लूटीओ भारत में चीनी पर दी जा रही भारी सब्सिडी पर सवाल उठा रहा है वहीं गन्ना किसानों की बकाया रकम लगातार बढ़ती जा रही है।

अकेले उत्तर प्रदेश में ही चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया मार्च 2017 के 4,497 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2019 में 12,700 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। चीनी सब्सिडी पर सात देशों के साथ चर्चा का पहला दौर अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू भी हो गया है। इससे पहले यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान, ब्राजील, कनाडा, मिस्न, कजाकिस्तान, कोरिया, थाईलैंड, ताइवान और श्रीलंका जैसे 12 देश भारतीय निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी को मिली अमेरिकी चुनौती के साथ लामबंद हो गए।

भारत की निर्यात सब्सिडी में वस्तु निर्यात पर दिए जाने वाले इंसेटिव्स यानी प्रोत्साहन भी शामिल हैं। डब्लूटीओ के एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स (एसीएसएम) का हवाला देते हुए अमेरिका ने अनुमान लगाया कि भारत निर्यात के एवज में सात अरब डॉलर की सब्सिडी दे रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में भारत निशाने पर रहा है, लेकिन भारत की सब्सिडी पर सवाल उठाने वाले देशों की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से चिंताजनक है। इसलिए और भी, क्योंकि डब्लूटीओ के कुछ कदम भारत की दुखती रग को और ज्यादा छेड़ते हैं।

डब्लूटीओ में विभिन्न देशों के रवैये के अतिरिक्त कनाडा अमेरिका के साथ मिलकर भारत से बीते कुछ वर्षों में दलहन के एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठा रहा है। इस साल 12 फरवरी को अमेरिका ने कनाडा के साथ मिलकर डब्लूटीओ की कृषि समिति में एक समन देकर भारत से पांच किस्म की दालों की कीमतों के रुख को लेकर जवाब तलब किया। पांच तरह की दालों चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनके समर्थन मूल्य को लेकर भारत ने डब्लूटीओ की परिभाषित सीमा को पार कर लिया है। अमेरिका और कनाडा यह दलील दे रहे हैं कि दालों को लेकर भारत ने अपने समर्थन मूल्य को लेकर सही जानकारी नहीं दी है जो कृषि पर डब्लूटीओ समझौते का उल्लंघन है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और कृषि मंत्री ने अपने दावे में भारत पर यह आरोप लगाते हुऐ कहा कि भारत जानबूझकर सब्सिडी पर पर्दा डालकर ऐसे आंकड़े पेश कर रहा है जिनसे तस्वीर साफ नहीं होती। उनका दावा है कि दालों के लिए भारत 32 से 85 प्रतिशत तक मूल्य समर्थन दे रहा है। इस पर भारत का कहना है कि सभी किस्म की दालों के लिए उसका कुल सब्सिडी समर्थन 1.8 प्रतिशत के आसपास है और यह डब्लूटीओ की दस प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से काफी कम है।

डब्लूटीओ प्रावधानों के अनुसार किसी भी उत्पाद के लिए समर्थन मूल्य उसके समग्र उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जा सकता। समर्थन मूल्य को भी इसमें सब्सिडी माना जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि चने का कुल 500 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ हो तो उसके लिए किसानों को 50 करोड़ रुपये से अधिक समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सकता। जहां अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और अन्य देश शिकायत कर रहे हैं कि सब्सिडी का आकलन करने के लिए भारत डब्लूटीओ की पद्धति से इतर प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है वहीं भारत की दलील है कि वास्तव में शिकायतकर्ता देश ही गलत पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं।

ये देश एमएसपी के आंकड़े लेकर उससे बाह्य संदर्भ मूल्य (ईएसपी) को घटा रहे हैं जिसे डब्लूटीओ ने 1986-89 के आंकड़ों पर स्थिर किया हुआ है। फिर इस घटी हुई राशि को वे किसी विशेष फसल के उत्पादन की मात्रा से गुणा कर देते हैं। इससे बहुत ही बढ़े-चढ़े आंकड़े हासिल होते हैं। हकीकत यह है कि भारत फसल का समूचा उत्पादन ही एमएसपी पर नहीं खरीदता, बल्कि उसका एक हिस्सा ही खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए खरीदता है ताकि समाज के वंचित वर्गों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। इसका सही तरीका यही होना चाहिए कि कुल उत्पादन से गुणा करने के बजाय उतनी ही फसल की मात्रा को गुणा किया जाए जिसे एमएसपी पर खरीदा गया हो। गेहूं और चावल के मामले में भी अमेरिका ने कई अवसरों पर भारत के आकलन को चुनौती दी है।

वर्ष 2013-14 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उसने कहा कि भारत ने वास्तव में गेहूं की 65 प्रतिशत फसल और धान की 77 प्रतिशत फसल को समर्थन मूल्य दिया, लेकिन उससे कम के आंकड़े दिए। वहीं भारत ने दावा किया कि इन दोनों फसलों के लिए एमएसपी का आंकड़ा 10 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से कम ही था। डब्लूटीओ में इस आक्रामक रुख का मकसद यह है कि कृषि एवं डेयरी उत्पादों के लिए और बड़ा बाजार तलाशा जाए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था जब उन्होंने भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों को सामान्य वरीयता तंत्र यानी जीएसपी के तहत मिले फायदों पर विराम लगा दिया था। इसके जवाब में भारत ने अमेरिका के 29 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का एलान तो किया, लेकिन उसमें भी शिथिलता सरकार की व्यापार नीति में कमजोरी को ही जाहिर करती है। आयात शुल्क बढ़ाने की मियाद अब दो मई तक इस उम्मीद के साथ बढ़ा दी गई कि शायद अमेरिका का रवैया कुछ नरम पड़ जाए। बहरहाल डब्लूटीओ के मौजूदा विवाद में भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अमेरिका को इसी मंच पर कैसे घेर पाता है जो अपने किसानों को भारी-भरकम सब्सिडी देता है। वास्तव में हम व्यापार कूटनीति में कमजोरी के परिणाम भुगत रहे हैं। अगर भारत ने घरेलू कृषि के हितों की रक्षा नहीं की तो देश की खाद्य सुरक्षा का दारोमदार उन्हीं किसानों के कंधों पर और बढ़ जाएगा जो पहले से ही मुश्किलों के कारण संकट में फंसे हुए हैं।

(Adapted from Jagran.com)

12. Airlines closed down operations in 7 years- जेट एयरवेज 7 साल में बंद होने वाली छठी एयरलाइन, 20000 कर्मचारियों के भविष्य पर संकट (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

देश की पहली निजी एयरलाइंस जेट एयरवेज ने बुधवार को अस्थाई रूप से सभी उड़ानें बंद करने का ऐलान कर दिया। जेट एयरवेज पिछले 7 साल में बंद होने वाली छठी और दूसरी बड़ी एयरलाइन है। 2012 में माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी। उसके बाद एयर पेगसस, एयर कोस्टा, एयर कार्निवल और जूम एयर को ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे। जेट के ऑपरेशन बंद होने के बाद करीब 20 हजार कर्मचारियों और मैनेजमेंट के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रोजगार को बचाने की अपील की है।

एयरलाइन	संचालन बंद होने का वर्ष
किंगफिशर	अक्टूबर 2012
पेगसस	जुलाई 2016
एयर कोस्टा	फरवरी 2017
एयर कार्निवल	अप्रैल 2017
जूम एयर	जुलाई 2018

अब बिडिंग के जरिए समाधान निकालने की कोशिश

जेट एयरवेज के मैनेजमेंट और कर्मचारियों को अब एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शियम द्वारा जेट की हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली प्रक्रिया पूरी करने का इंतजार है। यह प्रोसेस 10 मई तक पूरी होगी। जेट के कर्जदाताओं का कहना है कि बिडिंग के जरिए जेट के संकट का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है।

एयरलाइन के कर्मचारियों की 3 महीने की सैलरी बकाया

• एयरलाइन के पायलट्स और इंजीनियर्स को अगस्त 2018 से टुकड़ों में वेतन मिल रहा था। पिछले तीन महीने की पूरी सैलरी बकाया है। उम्मीद कर रहे थे कि एयरलाइन को बैंकों से 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कुछ राहत मिलेगी लेकिन कर्जदाताओं ने इनकार कर दिया।

• जेट के पायलट्स के ने प्रधानमंत्री मोदी से नौकरियां बचाने की गुहार लगाई थी। एसबीआई से भी फंड जारी करने की अपील की गई थी। करीब 12 महीने से परेशान स्टाफ परेशानियां झेल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल एयरलाइन ने कॉस्ट कटिंग के तहत कर्मचारियों से 25% सैलरी कम करने के लिए भी कहा लेकिन वो नहीं माने। अब हालत ये हो गई है कि कर्मचारी लोन की किश्त चुकाने के लिए गहने गिरवी रखने को मजबूर हो गए हैं।

• कई कर्मचारी 25-50% तक कम वेतन पर दूसरी एयरलाइंस ज्वॉइन करने को तैयार हैं। एक सूत्र ने बताया कि जेट का संकट बढ़ने के बाद 400 पायलट नौकरी छोड़ चुके हैं। अब जेट के पास 1,300 पायलट रह गए हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

13. Present position of Jet airways- जेट एयरवेज का वर्तमान हाल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

एसबीआई के नेतृत्व वाला बैंकों का कंसोर्शियम बिडिंग करा रहा है। बिडिंग के फेल होने के चांस बहुत कम हैं। जेट एयरवेज पर 8500 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है।

बिडिंग के लिए चार कंपनियां आगे आईं

1. अभी तक एतिहाद एयरवेज, टीपीजी कैपिटल, इंडिगो पार्टनर्स और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्टर फंड ने बिडिंग प्रक्रिया में रुचि दिखाई है। कर्जदाताओं का मत है कि बिडिंग फेल होने पर कंपनी की सिक्युरिटी और वास्तविक परिसम्पत्ति को नीलाम करके पैसे की वसूली की जाए। एजेंसी का कहना है कि बिडर्स के बारे में पूरी जानकारी 10 मई को ही मिल सकेगी।

2. बिडिंग के लिए चार कंपनियां आगे आईं अभी तक एतिहाद एयरवेज, टीपीजी कैपिटल, इंडिगो पार्टनर्स और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्टर फंड ने बिडिंग प्रक्रिया में रुचि दिखाई है। कर्जदाताओं का मत है कि बिडिंग फेल होने पर कंपनी की सिक्युरिटी और वास्तविक परिसम्पति को नीलाम करके पैसे की वसूली की जाए। एजेंसी का कहना है कि बिडर्स के बारे में पूरी जानकारी 10 मई को ही मिल सकेगी।

3. सूत्रों का कहना है कि मौजूदा संकट के लिए कर्जदाताओं को दोष नहीं दिया जा सकता। नौ माह पहले कंपनी पर जब संकट के बादल मंडराने शुरू हुए, तब कर्जदाता मजबूती से प्रबंधन के साथ खड़े थे। लेकिन कंपनी प्रबंधन अगर मगर के भंवर में फंसकर कोई निर्णायक कदम नहीं उठा सका। अब कर्जदाता अपने पैसा निकालने के लिए हाथ-पैर तो मारेंगे ही।

4. पिछले 7 साल में बंद होने वाली छठी एयरलाइन है जेट एयरवेज जेट एयरवेज पिछले 7 साल में बंद होने वाली छठी और दूसरी बड़ी एयरलाइन है। 2012 में माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई थी। उसके बाद एयर पेगसस, एयर कोस्टा, एयर कार्निवल और जूम एयर को ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे।

5. जेट के ऑपरेशन बंद होने के बाद करीब 20 हजार कर्मचारियों और मैनेजमेंट के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके रोजगार को बचाने की अपील की है।

6. एयरलाइन के पायलट्स और इंजीनियर्स को अगस्त 2018 से टुकड़ों में वेतन मिल रहा था। पिछले तीन महीने की पूरी सैलरी बकाया है। ये सभी उम्मीद कर रहे थे कि एयरलाइन को बैंकों से 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे तो कुछ राहत मिलेगी लेकिन कर्जदाताओं ने इनकार कर दिया।

7. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल एयरलाइन ने कॉस्ट कटिंग के तहत कर्मचारियों से 25% सैलरी कम करने के लिए भी कहा लेकिन वो नहीं माने। अब हालत ये हो गई है कि कर्मचारी लोन की किश्त चुकाने के लिए गहने गिरवी रखने को मजबूर हो गए हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

14. I lakh crore rupee deposit in Jan dhan accounts- जन धन खातों में जमा रकम की राशी पहुंची एक लाख करोड़ के करीब, इतने रूपे डेबिट कार्ड जारी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों में जमा रकम जल्द एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जन धन खातों में तीन अप्रैल तक 97,665.66 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके थे।

प्रधानमंत्री जन धन योजना को 28 अगस्त, 2014 को लांच किया गया था। इसका मकसद देशभर के सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना था। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक इसके खाताधारकों की संख्या 35.39 करोड़ को पार कर गई है।

इनमें से 27.89 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को रूपे डेबिट कार्ड भी जारी किया जा चुका है। इसकी सफलता को देखते हुए ही सरकार ने इन खातों के तहत दुर्घटना बीमा की राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी थी।

(Adapted from Jagran.com)

15. एसबीआई इन टच टैप एंड गो डेबिट कार्ड (sbiINTOUCH Tap Go debit card) क्या है? (Relevant for GS Prelims; Economics)

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो sbiINTOUCH के तहत बहुत सी बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करता है। इस कार्ड को PoS पर स्वाइप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ PoS के पास रखकर ही ट्रांजेक्शन की जा सकती है। यह कार्ड एनएफसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है।

एसबीआई इन टच एंड गो डेबिट कार्ड के खास फीचर्स:-

1. एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, इस कार्ड से प्रति 200 रुपये खर्च करने पर एक फ्रीडम रिवार्ड पॉइंट मिलता है।
2. कार्ड जारी होने के एक महीने बाद पहली खरीदारी पर 50 बोनस फ्रीडम रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं।
3. कार्ड जारी होने के एक महीने बाद दूसरी खरीदारी 50 अतिरिक्त फ्रीडम गिफ्ट बोनस पॉइंट मिलते हैं।
4. कार्ड जारी होने के एक महीने बाद तीसरी खरीदारी पर बैंक 100 बोनस फ्रीडम रिवाईज पॉइंट देता है।
5. अगर एक तिमाही में कम से कम 3 खरीदारी के लिए एसबीआई इनटच टैप एंड गो डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रखते हैं तो उस तिमाही के पॉइंट दोगुने हो जाएंगे। इन पॉइंट को जमा किया जा सकता है और गिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
6. शॉपिंग करते वक्त इस कार्ड से बहुत तेजी से भुगतान किया जा सकता है। इस कार्ड का इस्तेमाल मूवी टिकट बुक करने, यात्रा करने, ऑनलाइन शॉपिंग या इंटरनेट पर पेमेंट करने के लिए किया जा सकता है।

(Adapted from Jagran.com)

16. SEBI restrains Leelaventure from parting with property- होटल लीलावेंचर की प्रॉपर्टी बिक्री पर सेबी ने रोक लगाई, आईटीसी और एलआईसी ने शिकायत की थी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

होटल लीला वेंचर के 4 होटल और एक दूसरी संपत्ति की बिक्री पर मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने रोक लगा दी है। सेबी ने कहा है कि उसे आईटीसी से शिकायत मिली थी। आईटीसी और एलआईसी ने शेयरहोल्डर होने के नाते होटल लीला वेंचर पर दबाव बनाने और प्रबंधन में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। आईटीसी के पास होटल लीला वेंचर के 7.92% और एलआईसी के पास 2.36% शेयर हैं।

सेबी ने कहा- अगले निर्देश तक लीलावेंचर कोई लेन-देन ना करे

सेबी की ओर से होटल लीला वेंचर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए आरोपों की जांच की जा रही है। इसलिए अगले निर्देश तक प्रॉपर्टी की बिक्री से जुड़ा कोई लेन-देन नहीं किया जाए। लीला वेंचर ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में खुद यह जानकारी दी है।

आर्थिक तंगी झेल रही लीला वेंचर ने इन्हें कनाडा के इन्वेस्टमेंट फंड म असेट मैनेजमेंट को 3,950 करोड़ रुपए में बेचने का फैसला किया था। 18 मार्च को कंपनी ने बताया था कि वह बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, उदयपुर के होटल्स और एक अन्य प्रॉपर्टी को बेचेगी। इस पर 24 अप्रैल को शेयरधारकों की मंजूरी ली जानी थी।

(Adapted from Bhaskar.com)

17. Problems in airline industry- विमानन उद्योग की मुश्किलें (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

हमारे देश का विमानन उद्योग इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आलम यह है कि जेट एयरवेज को अपनी तमाम उड़ानें बंद करते हुए कारोबार को अस्थायी रूप से समेटना पड़ा है, जबकि एक साल पहले तक ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। जेट एक ऐसी एयरलाइन है, जिसकी कभी घरेलू विमानन कारोबार में 40 फीसद तक हिस्सेदारी रही है। इसकी एक सुदृढ़, टिकाऊ एयरलाइन के रूप में साख थी, जो तब भी टिकी रही, जब दमानिया, मोदीलुफ्त, किंगफिशर और ईस्ट वेस्ट जैसी एयरलाइंस गैर-लाभकारी साबित होते हुए बंद होने को मजबूर हो गई थीं। जेट एयरवेज की असफलता के लिए न सिर्फ नरेश गोयल की अगुआई वाली इस कंपनी का कमजोर प्रबंधन, बल्कि कई ऐसे बाहरी कारक भी जिम्मेदार हैं, जो देश में तमाम विमानन कंपनियों के कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या अन्य विमानन कंपनियां इस मुश्किल दौर से उबर पाएंगी या इसी तरह आखिरकार डूबने को मजबूर होंगी?

जहां तक जेट एयरवेज की बात है तो इसमें मुख्यत: कर्ज के बढ़ते बोझ की वजह से करीब छह महीने पहले उथल-पुथल मचने लगी थी। जेट के बढ़ते कर्ज का यह सिलसिला तब शुरू हुआ था, जब वर्ष 2007 में इसने एयर सहारा का अधिग्रहण किया था। इसके बाद यह हवाई सेक्टर में इंडिगो, स्पाइसजेट और गोएयर जैसी नई बजट एयरलाइंस का मुकाबला करने के लिहाज से पर्याप्त सक्षम नहीं रही। यह तब भी फुल सर्विस एयरलाइन बनी रही, जब विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के दाम तेजी से बढ़ रहे थे और रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा था। इससे इसकी परिचालन लागत पर काफी असर पड़ा। विमानों की कुल परिचालन लागत में तकरीबन 40 फीसद हिस्सा एटीएफ का होता है। इसके अलावा जेट को अपने प्रतिस्पर्धियों से मुकाबले के लिए ग्राहकों को सस्ते किराए की पेशकश भी करनी पड़ी और साथ ही साथ अपनी नई अधिग्रहित बजट हवाई सेवा (जिसका नाम बदलकर जेटलाइट कर दिया गया था) को भी संभालना पड़ा।

हालांकि जेट इकलौती ऐसी एयरलाइन नहीं, जो मुश्किलों में फंसी है। सरकारी-स्वामित्व वाली एयर इंडिया भी भारीभरकम कर्ज के बोझ से दबी है और सरकार द्वारा पिछले वर्षो में इसे किसी निजी निवेशक को बेचने के काफी प्रयास किए गए, लेकिन ऐसा कोई सामने नहीं आया, जो इसे खरीदने का इच्छुक हो। लिहाजा सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रहा कि वह इसे फिर से खड़ा करते हुए इस स्थिति में लाए, जिससे यह खरीदारों की नजर में आकर्षक बन सके। एयर इंडिया की पुनरुद्धार योजना में यह भी शामिल है कि इसके आईकॉनिक नरीमन प्वाइंट टावर समेत अन्य रीयल एस्टेट संपत्तियों को बेचकर नकदी जुटाई जाए। इसके अलावा कुछ अन्य मोर्चो पर कटौती भी की जाए। फिर भी लगता यही है कि एयर इंडिया का तभी कायाकल्प हो सकता है, जब इसे निजी हाथों में सौंप दिया जाए। पिछले साल के अंत तक इसकी विमानन बाजार में 13 फीसद हिस्सेदारी थी, जो जेट के 14 फीसद के मुकाबले थोड़ी ही कम थी। फिलहाल घरेलू विमानन क्षेत्र में सबसे बड़ी खिलाड़ी इंडिगो है, जिसमें देश के तकरीबन 42 फीसद विमान यात्री सफर करते हैं। अन्य विमान सेवाओं की बात करें तो स्पाइस जेट की हिस्सेदारी 12 फीसद है और विस्तारा एवं गोएयर की तकरीबन 9-9 फीसद है। अब जेट का कारोबार बंद होने से ये तमाम समीकरण काफी हद तक बदल जाएंगे और इसके चलते हवाई किरायों में भी इजाफा भी हो सकता है।

हालांकि हवाई सेक्टर में यात्रियों की मांग बराबर बनी हुई है, लेकिन फिर भी विमानन कंपनियों को परिचालन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसकी एक बड़ी वजह एटीएफ के बेहद ऊंचे दाम हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इसी के हिसाब से एटीएफ की लागत भी विमानन कंपनियों के लिए बढ़ रही है। विमानन उद्योग पिछले कुछ समय से मांग कर रहा है कि एटीएफ पर करारोपण की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए। एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने से इन एयरलाइंस को इनपुट क्रेडिट का लाभ मिलेगा और इससे इनकी सालाना करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है।

बहरहाल यह भी दिलचस्प है कि भले ही घरेलू विमानन उद्योग मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, लेकिन इसमें आगे बेहतर संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। भारत हवाई सेवाओं के लिहाज से सबसे तेज बढ़ता बाजार है, जिसमें पिछले साल 17 फीसद वृद्धि देखी गई। अनुमान है कि आने वाले वर्षो में भारतीय विमानन सेक्टर में तकरीबन 35000 करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है। इसके अलावा इसमें कुशल कर्मियों की भी काफी मांग है। फिलहाल भले ही जेट के पराभव से इसके तकरीबन 16000 कर्मचारियों को नौकरी जाने का भय सता रहा हो, लेकिन इनमें से ज्यादातर को अन्य एयरलाइंस द्वारा ले लिया जाएगा, जिन्हें प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत है। इंडिगो और उसके जैसी अन्य एयरलाइंस अपने विमान बेड़े को बढ़ा रही हैं और इस खातिर भी इन्हें पायलट्स एवं केबिन क्रू और अन्य स्टाफ की दरकार है।

क्षेत्रीय एयरलाइंस के मोर्चे पर देखें तो सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लांच की गई बहुचर्चित उड़ान योजना अब तक अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। हालांकि छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को सस्ती दरों में हवाई सेवा उपलब्ध कराने का इसका मकसद सराहनीय है। दिक्कत यह है कि जिन छोटी एयरलाइंस को इस मकसद को साधने में मदद करनी चाहिए थी, वे अब भी पर्याप्त सक्षम नहीं हैं। विमानन उद्योग जहां फिलहाल तमाम तरह की मुश्किलों से जूझ रहा है, वहीं भविष्य में इसमें तीव्र उछाल की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। इस उद्योग की नियति इस पर निर्भर करेगी कि सरकार खासकर विमान ईंधन को लेकर क्या नीति अपनाती है और विमानन कंपनियां अपने प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय या बदलाव करती हैं।

(Adapted from Jagran.com)

18. Increase in Provident fund interest rate- वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दर 8.65% करने को मंजूरी दी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

वित्त मंत्रालय ने 2018-19 के सत्र के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर 8.65 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे विधिवत क्षेत्र में काम करने वाले 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा। सूत्र के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईपीएफ के ग्राहक अपने रिटायरमेंट फंड के उपयोग में ज्यादा फायदा ले सकें। मंत्रालय ने इसके लिए आवश्यक शर्तों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।

आयकर विभाग और श्रम मंत्रालय जारी करेगा नोटिस

1. सूत्र के मुताबिक वित्त मंत्रालय के आर्थिक सेवा विभाग की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सामने 2018-19 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.65 प्रतिशत की ब्याज दर दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया था।

2. फरवरी में श्रम मंत्रालय के मंत्री संतोष गंगवार के नेतृत्व वाले ईपीएफओ की शीर्ष संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने तय किया था कि ईपीएफ राशि पर ब्याज दर 8.65 प्रतिशत की जाए। तीन सालों में की गई यह पहली बढ़ोतरी थी।

3. 2015-16 में यह दर 8.8 प्रतिशत थी। 2016-17 में इसे 8.65 प्रतिशत किया गया था। 2017-18 में ब्याज दर 8.55 प्रतिशत पर आई। 2018-19 के लिए इसे बढ़ाकर 8.65 प्रतिशत किया गया है।

4. वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद आयकर विभाग और श्रम मंत्रालय को 2018-19 के लिए ब्याज दर का नोटिस जारी करना होगा। ईपीएफओ अपने 120 कार्यालयों को निर्देश देगा। इसके बाद ग्राहकों के खातों से संबंधित शर्तों को पूरा किया जा सकेगा।

5. ईपीएफओ के द्वारा ग्राहकों को बीते पांच सालों में सबसे कम ब्याज दर ऑफर की गई जो 8.55 प्रतिशत की थी। यही कारण है कि ईपीएफ ने तय किया है कि ग्राहकों को 8.65 फीसदी की ब्याज दर से राशि दी जाए।

(Adapted from Bhaskar.com)

19. India notified agreement with US to stop tax evasion by MNCs- मल्टीनेशनल कंपनियों की टैक्स चोरी पकड़ने के लिए भारत ने यूएस के साथ एग्रीमेंट नोटिफाई किया (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

भारत ने मल्टीनेशनल कंपनियों (एमएनसी) की आय और टैक्स की कंट्री-बाय कंट्री (सीबीसी) रिपोर्ट साझा करने के लिए अमेरिका के साथ किए गए एग्रीमेंट को नोटिफाई कर दिया है। टैक्स चोरी रोकने के लिए मार्च में यह एग्रीमेंट हुआ था जिसे 25 अप्रैल को नोटिफाई किया गया है।

यूएस की कंपनियों को भारत में अलग से रिपोर्ट फाइल नहीं करनी पड़ेगी

एग्रीमेंट के तहत दोनों देश 1 जनवरी 2016 और उसके बाद एमएनसी द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट्स शेयर कर सकेंगे। अब अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों की भारतीय सब्सिडियरी को अलग से रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत भी नहीं होगी।

सीबीसी रिपोर्ट में टैक्स के भुगतान की जानकारी के अलावा उस ग्रुप की सभी कंपनियों की लिस्ट भी होती है। साथ ही हर कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियों का ब्यौरा होता है।
75 करोड़ यूरो (5500 करोड़ रुपए) या इससे ज्यादा सालाना रेवेन्यू वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी पेरेंट फर्म वाले देश में सीबीसी रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।

(Adapted from Bhaskar.com)

पर्यावरण एवं जैव विविधता

1. Earth Day- पृथ्वी दिवस (Relevant for GS Prelims; Environment)

पृथ्वी दिवस (Earth Day) 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन पृथ्वी दिवस नेटवर्क (Earth Day Network) द्वारा विश्व स्तर पर समन्वयित किया जाता है।

पृष्ठभूमि
1969 में, सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन में, शांति कार्यकर्ता जॉन मैककनेल ने पृथ्वी और शांति की अवधारणा का सम्मान करने के लिए एक दिन का प्रस्ताव दिया, जो 21 मार्च 1970 था। इस दिन को बाद में संयुक्त राष्ट्र में स्वीकृत किया गया था। एक महीने बाद, 22 अप्रैल 1970 को यूएस सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने एक अलग पृथ्वी दिवस की स्थापना की शुरुआत की। कई समुदाय पृथ्वी सप्ताह का जश्न मनाते हैं, जो दुनिया भर के पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित गतिविधियों पर आयोजित होता है।

(Adapted from PrepMate- Cengage Environment book)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. Successful launch of Emisat- 'इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटेलीजेंस सेटेलाइट' (एमिसैट) का सफल प्रक्षेपण (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

पहले ही प्रयास में एंटी-सेटेलाइट (ए-सैट) मिसाइल का सफल परीक्षण कर अपनी क्षमता का डंका बजाने वाले भारत ने एक हफ्ते के भीतर अंतरिक्ष की दुनिया में एक और कदम बढ़ा दिया है।

एमिसैट का प्रक्षेपण

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सैन्य सेटेलाइट 'इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटेलीजेंस सेटेलाइट' (एमिसैट) का सफल प्रक्षेपण किया। 436 किलोग्राम के एमिसैट की खूबियों को देखते हुए इसे अंतरिक्ष में भारतीय जासूस की संज्ञा दी जा रही है। हालांकि इसरो ने सेटेलाइट के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इन्कार किया है।

28 विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया

एमिसैट के साथ इसरो ने 28 विदेशी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया। इसरो ने पहली बार एक साथ तीन अलग-अलग कक्षाओं में प्रक्षेपण का मिशन पूरा कर अपने नाम एक और उपलब्धि दर्ज कराई है।

पीएसएलवी-सी 45 का प्रयोग किया गया था

इसरो के रॉकेट पीएसएलवी-सी 45 ने एमिसैट समेत कुल 29 उपग्रहों के साथ श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सोमवार सुबह 9:27 बजे उड़ान भरी। 28 विदेशी सेटेलाइट में अमेरिका के 24, लिथुआनिया के दो और स्पेन व स्विट्जरलैंड का एक-एक उपग्रह शामिल था।

मिशन की विस्तारपूर्वक जानकारी

इसरो प्रमुख के। सिवन ने बताया कि पीएसएलवी सी-45 ने 27 घंटे की उलटी गिनती खत्म होते ही नारंगी रंग का धुआं छोड़ते हुए उड़ान भरी। इसके करीब 17 मिनट बाद 9।44 बजे एमिसैट को 748 किमी ऊंची उसकी कक्षा में छोड़ा गया तो वैज्ञानिकों के चेहरे चमक उठे। इसके बाद कुल 28 विदेशी उपग्रहों को एक-एक कर 504 किमी ऊपर उनकी निर्धारित कक्षाओं में छोड़ा गया। इन 28 सेटेलाइट का कुल वजन 220 किलोग्राम था। सभी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के बाद रॉकेट के चौथे स्टेज को पुन: चालू किया गया और यह 485 किमी की कक्षा में गया। सिवन ने इसरो के सभी साथी वैज्ञानिकों को सफल मिशन के लिए बधाई दी है।

प्राइवेट उद्योगों का योगदान

95 फीसदी हार्डवेयर बाहरी उद्योगों में बने : इसरो प्रमुख ने बताया कि इस मिशन में उद्योगों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। करीब 95 फीसदी हार्डवेयर इसरो के बाहर अन्य उद्योगों में तैयार किए गए। इतना ही नहीं सेटेलाइट के भी 60 से 70 फीसद हिस्से बाहरी उद्योग में बने। बेंगलुरु की एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने इसमें अहम भूमिका निभाई। इसरो ने प्रक्षेपण देखने के लिए एक गैलरी भी बनाई थी। यहां से करीब 1,200 लोगों ने प्रक्षेपण का दृश्य देखा। प्रक्षेपण केंद्र से महज तीन किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई यह गैलरी इसरो के प्रस्तावित स्पेस थीम पार्क का हिस्सा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने और छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान की ओर अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह थीम पार्क बनाया जाएगा। भारत ने हाल ही में 300 किमी दूर अंतरिक्ष में अपने ही एक सक्रिय सेटेलाइट को ए-सैट मिसाइल से मार गिराया था। इस उपलब्धि के साथ ही भारत स्पेस वार की क्षमता वाले अमेरिका, रूस व चीन जैसे देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया है।

(Adapted from Jagran।com)

2. America agreed to sell 24 Sea Hawk helicopters to India- अमेरिका ने भारत को 24 सीहॉक हेलिकॉप्टर बेचने को मंजूरी दी (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)

अमेरिका ने भारत को 24 एमएच-60आर रोमियो सीहॉक हेलिकॉप्टरों को बेचे जाने को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक- भारत को ये हेलिकॉप्टर 2.4 अरब डॉलर (करीब 16 हजार करोड़ रुपए) में बेचे जाएंगे। हेलिकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अलावा जहाजों को खदेड़ने और समुद्र में सर्च-बचाव अभियान में कारगर साबित होंगे।

सी किंग हेलिकॉप्टर की जगह लेंगे

1. रोमियो सीहॉक हेलिकॉप्टरों को लॉकहीड-मार्टिन कंपनी ने बनाया है। ये ब्रिटिश सी किंग हेलिकॉप्टरों की जगह लेंगे। मंगलवार को ट्रम्प प्रशासन ने भारत को 24 हेलिकॉप्टर बेचे जाने का नोटिफिकेशन जारी किया।

2. नोटिफिकेशन के मुताबिक- हेलिकॉप्टरों की प्रस्तावित बिक्री से भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते मजबूत होंगे। भारत, अमेरिका का बड़ा डिफेंस पार्टनर है। डील से इंडो-पैसिफिक और दक्षिण एशिया में स्थायित्व-शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। वहीं, रोमियो हेलिकॉप्टरों से भारतीय फौजों की एंटी-सरफेस (जमीन) और एंटी-सबमरीन सुरक्षा क्षमता में इजाफा होगा।

3. अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि इन हेलिकॉप्टर्स की मदद से घरेलू स्तर पर भारत की सुरक्षा मजबूत होगी और उसे क्षेत्रीय दुश्मनों से निपटने में मदद मिलेगी। भारत को इन हेलिकॉप्टरों को सेना में शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

4. इन रोमियो एमएच-60आर को दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरीटाइम हेलिकॉप्टर माना जाता है। फिलहाल यह अमेरिकी नेवी में एंटी-सबमरीन और एंटी-सरफेस वेपन के रूप में तैनात हैं। रक्षा विशेषज्ञों की मानें तो यह मौजूदा हेलिकॉप्टरों में सबसे आधुनिक हैं। इसे जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट किया जा सकता है।

5. अमेरिकी नेवल एयर कमांड के मुताबिक- सीहॉक हेलिकॉप्टर एंटी-सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, युद्धक सर्च और बचाव, गनफायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर हैं।

(Adapted From Bhaskar)

3. Project-75 aims to build 6 submarines-500 किमी. रेंज वाली मिसाइलों से लैस 6 पनडुब्बियां बनाने का प्रस्ताव, बजट 50 हजार करोड़ रु. (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

भारतीय नौसेना ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत 6 सबमरीन हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी लागत 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। जितने भी विदेशी विक्रेताओं ने इस बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने की रूचि दिखाई, उनके लिए नौसेना ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है।

50 फीसदी बड़ी पनडुब्बी चाहती है नौसेना

भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत ऐसी 6 डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन का निर्माण करवाना चाहती है, जो फिलहाल मुंबई की माजागोन डॉकयॉर्ड्स लिमिटेड में बन रही स्कॉर्पिन सबमरीन से 50 फीसदी बड़ी हो। नौसेना का प्रस्ताव है कि यह सबमरीन 500 किमी रेंज वाली मिसाइलों से लैस हों।

भारतीय पार्टनर्स को भी आमंत्रित किया गया

सूत्र ने बताया कि जो भी विदेशी विक्रेता इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए प्राथमिक मसौदा जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी के अंतर्गत भारतीय पार्टनर्स के सुझावों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि इसके निर्माण में उनके सुझाव भी शामिल हों।

नौसेना की मांग- सबमरीन पर क्रूज मिसाइल हो

नौसेना की योजना है कि इस सबमरीन पर जमीन पर हमला करने वाली 12 क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ एंटी-शिप क्रूज मिसाइल भी मौजूद हों। सूत्रों ने बताया कि नौसेना ने यह स्पष्ट किया कि वे चाहते हैं कि यह पनडुब्बी 18 भारी-भरकम टॉर्पेडो को लादने और लॉन्च करने में सक्षम होना चाहिए।

नई पनडुब्बियां भारी-भरकम टॉर्पेडो से लैस

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नेवी अधिकारी को बनाया है। स्कॉर्पिन सबमरीन की तुलना में यह पनडुब्बी न सिर्फ भारी-भरकम टॉर्पिडो से लैस होगी बल्कि सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी इस पर होगी।

चीन का सामना करने के लिए तैयारी

भारतीय नौसेना के पास सौ से ज्यादा पनडुब्बियां और युद्ध करने में सक्षम जहाज मौजूद हैं जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या केवल 20 हैं। हालांकि भारतीय नौसेना की यह तैयारी चीनी नौसेना से सामना करने के लिए है।

(Adapted from Bhaskar.com)

4. Maximum Space debris due to America, India has contributed only 1.07%- अमेरिका की वजह से अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कचरा, कुल कचरे का सिर्फ 1.07% भारत का (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत के एंटी-सैटेलाइट हथियार के परीक्षण से निकले मलबे को खतरनाक बताया है। डीआरडीओ ने 27 मार्च को एंटी-सैटेलाइट मिसाइल (ए-सैट) का परीक्षण किया था। नासा प्रमुख जिम ब्राइडनस्टाइन ने हाल ही में कहा कि भारत के इस परीक्षण से 400 टुकड़े हुए जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) और उसमें रह रहे एस्ट्रोनोट्स के लिए खतरा है। नासा प्रमुख का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां भविष्य में मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए सही साबित नहीं होंगी। हालांकि, नासा के खुद के आंकड़ों के मुताबिक, अंतरिक्ष में बाकी देशों के मुकाबले अमेरिका का कचरा सबसे ज्यादा है। वहीं, भारत ने कहा है कि ए-सैट के परीक्षण से जो टुकड़े अंतरिक्ष में मौजूद हैं, वे कुछ ही समय में नष्ट होकर धरती पर आ गिरेंगे।

अंतरिक्ष में 19,173 टुकड़े, इनमें से 34% अमेरिका के

• अंतरिक्ष में मौजूद कचरे को नासा अपने हिसाब से मॉनिटर करता है। नासा की नवंबर 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरिक्ष में 19,173 टुकड़े घूम रहे हैं, जिनमें से 34% अमेरिका और सिर्फ 1.07% भारत के हैं। अंतरिक्ष में अमेरिका के टुकड़े 6,401 घूम रहे हैं, जबकि भारत के सिर्फ 206 हैं।

• नासा के मुताबिक, अंतरिक्ष में भारत के 89 टुकड़े पेलोड और 117 टुकड़े रॉकेट के हैं। भारत से करीब 20 गुना ज्यादा कचरा चीन का है। उसके 3,987 टुकड़े अंतरिक्ष में हैं।

• भारत के एंटी-सैटेलाइट परीक्षण के बाद नासा का कहना है कि इससे 400 टुकड़े बिखर गए। इस हिसाब से मानें तो अभी अंतरिक्ष में भारत के 606 टुकड़े मौजूद होंगे। उसके बाद भी ये कुल कचरे का सिर्फ 3.12% हैं।

10 साल में अमेरिका के 2,142 टुकड़े बढ़े, भारत के सिर्फ 62 बढ़े

नासा के आंकड़ों के मुताबिक, 10 साल में अंतरिक्ष में करीब 50% कचरा बढ़ा है। सितंबर 2008 तक अंतरिक्ष में 12,851 टुकड़े मौजूद थे, जिनकी संख्या नवंबर 2018 तक बढ़कर 19,173 पहुंच गई। इस दौरान अंतरिक्ष में अमेरिका की गतिविधियों से जहां 2,142 टुकड़े बढ़े, वहीं भारत से सिर्फ 62 टुकड़े बढ़े। सितंबर 2008 तक अंतरिक्ष में अमेरिका के 4,259 और भारत के 144 टुकड़े थे।

देश/ संस्था	बड़े टुकड़े (नवंबर 2018 तक)	बड़े टुकड़े (सितंबर 2008 तक)
चीन	3,987	2,774

कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (सीआईएस)	6,590	4,528
यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ईएसए)	144	74
फ्रांस	555	376
भारत	206	144
जापान	281	175
अमेरिका	6,401	4,290
अन्य	1,009	521
कुल	19,173	12,851

चीन ने 2007 में परीक्षण किया था, इससे करीब 2,500 से ज्यादा टुकड़े बिखरे थे

चीन ने सबसे पहले 2007 में केटी-1 रॉकेट से एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था। इससे चीन ने अपने मौसम उपग्रह फेंग युन 1-सी को धरती से 800 किमी की ऊंचाई पर लो-अर्थ ऑर्बिट में मार गिराया था। इस परीक्षण के बाद 2,500 से ज्यादा टुकड़े बिखर गए थे। नासा के आंकड़े भी यही कहते हैं। नासा के मुताबिक, सितंबर 2006 तक अंतरिक्ष में चीन के 376 टुकड़े मौजूद थे, जिनकी संख्या अक्टूबर 2007 तक बढ़कर 2,631 हो गई। वहीं, सितंबर 2008 तक अंतरिक्ष में चीन के 2,774 टुकड़े थे।

भास्कर नॉलेज: क्या होता है अंतरिक्ष का कचरा और इसका क्या होता है?

• अंतरिक्ष में जो कचरा होता है, उसे 'स्पेस डेब्रिस' या 'ऑर्बिटल डेब्रिस' कहते हैं। ये कचरा अंतरिक्ष में इंसानों की भेजी गई चीजों से होता है। इसमें रॉकेट के टुकड़े, सैटेलाइट के टुकड़े, एस्ट्रोनॉट द्वारा छोड़ा गया सामान शामिल होता है। कुल मिलाकर, यह ऐसा कचरा होता है, जिसका अब अंतरिक्ष में कोई इस्तेमाल नहीं बचा। नासा के अनुमान के मुताबिक, रोजाना कम से कम एक टुकड़ा धरती पर आता है। ये टुकड़ा या तो धरती पर कहीं न कहीं गिर जाता है या फिर वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अंतरिक्ष का ज्यादातर कचरा पानी में ही गिरता है, क्योंकि धरती पर 71% हिस्से में पानी है।

• अप्रैल 2018 में चीनी स्पेस स्टेशन थियांगोग के पृथ्वी से टकराने का अनुमान था। इसे लेकर काफी चिंता जताई गई थी, लेकिन ये समुद्र में गिर गया था। इससे पहले 1979 में नासा का स्पेस सेंटर स्कायलैब भी धरती पर गिरा था, लेकिन वो भी समुद्र में ही गिरा था।

• 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट 'स्पूतनिक' लॉन्च किया था। इसके बाद से अब तक 8,950 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े जा चुके हैं। इनमें से 1,950 सैटेलाइट ही काम कर रहे हैं।

• यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गणना नासा से अलग है। इसके मुताबिक, अंतरिक्ष में जनवरी 2019 तक 10 सेंटीमीटर से बड़े 34 हजार टुकड़े मौजूद हैं। जबकि 1-10 सेमी तक के 9 लाख और 1 सेमी से छोटे 12.80 करोड़ टुकड़े हैं।

(Adapted from bhaskar.com)

5. South Korea- 1st nation to start 5G- दक्षिण कोरिया कल 5जी सर्विस शुरू करने वाला पहला देश बनेगा, अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ेगा (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

दक्षिण कोरिया शुक्रवार को कॉमर्शियल 5जी सर्विस शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। सैमसंग के नए 5जी स्मार्टफोन की लॉन्चिंग के साथ यह सर्विस शुरू हो रही है। सैमसंग भी दक्षिण कोरिया की ही कंपनी है। 5जी सर्विस सबसे पहले शुरू करने के लिए दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका में होड़ थी। अमेरिका में टेलीकॉम कंपनी वेराइजन 11 अप्रैल को दो शहरों में 5जी सर्विस शुरू करने वाली है। चीन में भी चुनिंदा शहरों में इसका ट्रायल शुरू हुआ है। द. कोरिया को उम्मीद है कि 5जी सर्विस से देश में स्मार्ट सिटी और ड्राइवरलेस कार जैसे क्षेत्रों में तेजी आएगी, और इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। द. कोरिया की अर्थव्यवस्था लगातार धीमी हो रही है और 2018 में ग्रोथ की दर छह साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई थी। 5जी सर्विस शुरू करने जा रही द. कोरिया की टेलीकॉम कंपनियों में से एक एसके टेलीकॉम के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रियू योंग सांग ने कहा, 'इससे कई क्षेत्रों को फायदा होगा। गेमिंग सेक्टर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्मार्टफोन पर बिना लैग के गेम खेले जाएंगे।'

5जी सर्विस से उपभोक्ताओं को 4जी की तुलना में 20 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी को भी मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया की टेलीकॉम कंपनियों ने हाल के दिनों में अपनी-अपनी 5जी सर्विस की मार्केटिंग पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। एसके टेलीकॉम को 2019 के अंत तक 10 लाख से ज्यादा 5जी उपभोक्ता जोड़ने की उम्मीद है। इसके पास अभी 2.7 करोड़ उपभोक्ता हैं। इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी केटी कॉर्प 5जी के लिए 4जी से भी सस्ता प्लान ऑफर कर रही है।

सैमसंग ने फरवरी में अपना पहला 5जी स्मार्टफोन गैलेक्सी 10 5जी पेश किया था। इसकी कीमत करीब 2 हजार डॉलर (1.38 लाख रुपए) है। विशेषज्ञों के मुताबिक सैमसंग ने इस कदम से 5जी हैंडसेट बनाने की रेस में काफी बढ़त हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया की ही कंपनी एलजी भी इसी महीने अपना 5जी हैंडसेट लॉन्च करने वाली है।

15 साल में विश्व की अर्थव्यवस्था में 5जी से आएंगे 39 लाख करोड़

5जी टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। घर के टोस्टर से लेकर टेलीफोन, इलेक्ट्रिक कार से लेकर पावर ग्रिड तक को इससे फायदा होगा। साथ ही रोबोटिक्स, ड्रोन और इंटरनेट से जुड़े सभी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक 5जी टेक्नोलॉजी से विश्व अर्थव्यवस्था में 2034 तक 39 लाख करोड़ रुपए आएंगे।

भारत में अगले साल तक शुरू हो सकती है 5जी सेवा

5जी के लिए इस साल जुलाई या अगस्त में स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की उम्मीद है। स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद कंपनियां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी। फिर सर्विसेज शुरू होंगी। माना जा रहा है भारत में 5जी सेवा अगले साल ही शुरू हो पाएगी।

(Adapted from Bhaskar.com)

6. C-DAC to make India's first 64-bit microprocessor- भारत का पहला 64 बिट माइक्रोप्रोसेसर बनाएगी सी-डैक, 2022 तक तैयार होगा सुपर कम्प्यूटर (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)

प्रीमियर इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सी-डैक (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग) 64 बिट क्वाडकोर माइक्रोप्रोसेसर तैयार कर रही है, यह भारत में बनाया गया पहला चिपसेट होगा। सी-डैक सुपर कम्प्यूटर के निर्माण को लेकर भी काम कर रही है, जो एक बिलियन-बिलियन तक की गणना एक सेकंड में करता है, इसे 2022 तक भारत में लॉन्च किया जाएगा।

डिफेंस क्षेत्र के लिए भी बना रहे नई एप्लीकेशन

1. सी-डैक के महानिदेशक हेमंत दरबारी ने कहा कि " हम एक्सास्केल कम्प्यूटिंग (सुपर कंप्यूटर) के लिए एक बेहतरीन ऑर्किटेक्चर तैयार करने की और काम कर रहे हैं, जिसे 2022 तक तैयार कर लिया जाएगा "

2. संस्था द्वारा तैयार किया जा रहा एक्सास्केल कम्प्यूटिंग सिस्टम एक एक्साफ्लोप यानी बिलियन बिलियन तक की गणना एक सेकंड में करता है, जबकि दुनिया के सबसे कम्प्यूटर 143.5 पेटाफ्लोप यानी एक हजार मिलियन-मिलियन तक की गणना एक सेकंड में करने में सक्षम है।

3. भारत के पहले 64 बिट क्वाडकोर माइक्रोप्रोसेसर को बनाने के अलावा सी-डैक इमेज प्रोसेसिंग और स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए नए प्रोसेसर रेंज तैयार करने को लेकर भी काम कर रही है।

4. साथ ही संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज कम्प्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग (कॉन्सेप्ट जिसमें किसी भी डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ा जा सके) और सिक्योर कम्प्यूटिंग जैसे पांच मुख्य क्षेत्रों के लिए डिजाइन सिस्टम और एप्लीकेशन तैयार कर रहा है।

5. लैंग्वेज कम्प्यूटिंग के क्षेत्र में सी-डैक जल्द ही स्पीच-टू-स्पीच ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसमें अंग्रेजी को किसी भी भारतीय भाषा में बदला जा सकेगा।

6. पिछले कुछ महीनों में सी-डैक ने कई एप्लीकेशन बनाई है, जो ब्लॉकचेन समेत कई उभरती हुई नई तकनीक का इस्तेमाल करती है।

7. दरबारी ने कहा, "हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक बनाई है, जिसका उपयोग हम वर्तमान में आंध्र प्रदेश में एक लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं। यह रक्षा और स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन में उपयोग की जा सकेगी जहां सिक्योरिटी की काफी जरूरत पड़ती है।

8. इसके अलावा एक अन्य परियोजना किसानों को कीटों, पौधों की बीमारी और सिंचाई शेड्यूल की जानकारी जैसे व्यक्तिगत सुझाव भेजने के लिए वायरलेस सेंसर के उपयोग से संबंधित है।

(Adapted from bhaskar.com)

7. First photographs of black hole released- Black Hole की पहली तस्वीर हुई जारी, जानें इससे जुड़े रोचक तथ्य (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)

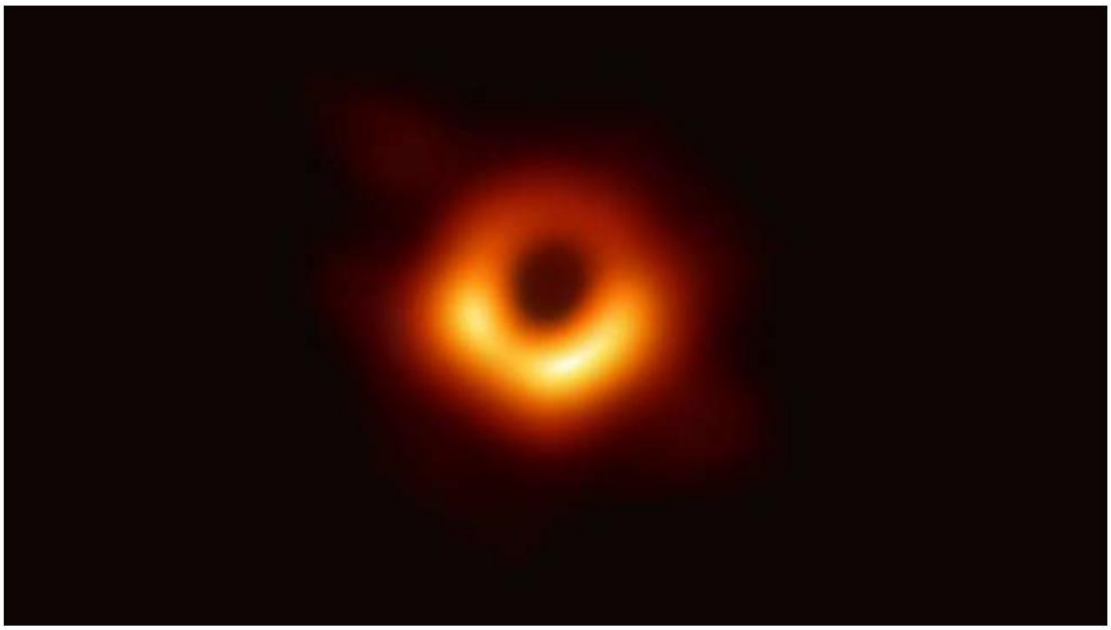

Black hole की पहली तस्वीर जारी की गई है। खगोल वैज्ञानिकों इसे कैप्चर करने में कामयाब रहे हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में यह पहली बार है जब हम सभी Black Hole की असली तस्वीर देख सकते हैं। ब्रम्हांड में इसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में अब तक खगोल वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा ही लगा पा रहे थे, लेकिन अब हमारे पास इसकी तस्वीरें भी उपलब्ध है। इसकी रियल पिक्चर में यह एक डस्ट और गैस का प्रभामंडल दिख रहा है, इसके आस-पास ब्लैक रंग में आउटलाइन दिखाई दे रही है। यह हमारे ग्रह पृथ्वी से 87 गैलेक्सी और 55m लाइट इयर्स दूर है।

पिक्चर में Galaxy Messier 87 के मध्य में एक Black Hole दिख रहा है। यह पृथ्वी से 53 मिलियन लाइट इयर्स दूर है। Event Horizon Telescope researchers के अनुमान के अनुसार, इस Black Hole में सूरज से 6 बिलियन गुना अधिक बड़ा है। इस Black Hole की पिक्चर लेने के लिए Event Horizon Telescope इस्तेमाल किए गए। यह टेलिस्कोप सिंगल टेलिस्कोप नहीं है बल्कि यह 8 रेडियो टेलिस्कोप को रेफेर करता है। इन्हें 5 महाद्वीपों पर लगाया गया था। इसे अप्रैल 2017 में एक हफ्ते के लिए स्पेस के एक ही एरिया को अलग-अलग जगह से टारगेट कर के लगाया गया था।

(Adapted from Jagran.com)

8. First commercial drone delivery service- दुनिया की पहली कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू, 18 महीने ट्रायल के बाद मंजूरी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Tecnology)

ड्रोन के जरिए सामान की डिलीवरी की कोशिश में कई कंपनियां लगी हैं। इसके हजारों ट्रायल भी हुए। लेकिन दुनिया में पहली कॉमर्शियल ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू करने का श्रेय गूगल को मिला है। अमेरिकी कंपनी को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में इस सर्विस की इजाजत मिल गई है। गूगल विंग कैनबरा में करीब 100 घरों को ड्रोन के जरिए खाना, कॉफी और दवाओं की डिलीवरी करेगी। गूगल 2014 से ही इसकी टेस्टिंग कर रही थी। डेढ़ साल से इसका ट्रायल भी चल रहा था। ट्रायल के दौरान कंपनी ने 3,000 पार्सल की डिलीवरी की।

ट्रायल के दौरान फीडबैक के आधार पर दूर कीं शिकायतें

1. शुरुआत में लोगों ने ड्रोन से बहुत ज्यादा आवाज आने की शिकायतें आईं। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई गई। इसके बाद गूगल ने इसमें कई सुधार किए। तब जाकर इसकी कॉमर्शियल सर्विस की अनुमति दी गई है।

2. गूगल ने बयान जारी कर कहा कि लोगों के फीडबैक से सिस्टम को सुधारने में काफी मदद मिली है। उम्मीद है कि हम इसे समय के साथ और बेहतर बनाएंगे और यह सर्विस बड़े पैमाने पर अन्य शहरों में भी शुरू होगी।

3. गूगल ने बयान जारी कर कहा कि लोगों के फीडबैक से सिस्टम को सुधारने में काफी मदद मिली है। उम्मीद है कि हम इसे समय के साथ और बेहतर बनाएंगे और यह सर्विस बड़े पैमाने पर अन्य शहरों में भी शुरू होगी।

4.2030 तक ऑस्ट्रेलिया में 25% डिलीवरी ड्रोन से होने का अनुमान

गूगल का मानना है कि सिर्फ कैनबरा में ही ड्रोन डिलीवरी सर्विस 4 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर (करीब 200 करोड़ रुपए) का बिजनेस कंपनी को देगी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में 25% डिलीवरी ड्रोन के जरिए होगी।

5. अमेजन और अलीबाबा भी ड्रोन डिलीवरी सर्विस पर काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने ब्रिटेन, अमेरिका और चीन में इसके कई ट्रायल भी आयोजित किए हैं। लेकिन इन्हें अब तक इजाजत नहीं मिली है।

6. सड़क या भीड़ वाले इलाके के ऊपर उड़ने की मनाही , देर रात डिलीवरी नहीं होगी

ड्रोन सर्विस के लिए कई नियम बनाए गए हैं

o ड्रोन सड़कों या भीड़भाड़ वाले इलाकों के ऊपर से नहीं उड़ सकता है।

o सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सर्विस उपलब्ध रहेगी।

o रविवार को यह सर्विस सुबह 8 से रात 8 बजे तक रहेगी।

7. ड्रोन में खरीदार का पता जीपीएस से फीड होता है

ड्रोन में खरीदार के घर का पता जीपीएस के जरिए फीड किया जाता है। पार्सल स्ट्रिंग के जरिए ड्रोन से जुड़ा होता। ड्रोन खरीदार के गार्डन के ऊपर जाकर पार्सल को ड्रॉप कर ड्रोन वापस चला जाता है।

(Adapted from Bhaskar.com)

9. Tik Tok removed from Play store- गूगल ने प्ले स्टोर से टिकटॉक ऐप हटाया, मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

गूगल ने भारत में चाइनीज मोबाइल ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को केंद्र सरकार से कहा था कि टिकटॉक को बैन किया जाए क्योंकि इससे पोर्नोग्राफी और बच्चों के प्रति यौन हिंसा को बढ़ावा मिला है। ऐप को बैन करने के लिए एक जनहित याचिका दायर हुई थी।

टिकटॉक को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

1. टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस टेक्नोलॉजी ने हाईकोर्ट के आदेश को पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस हाईकोर्ट को भेज दिया। मंगलवार को हाईकोर्ट ने टिकटॉक की अपील खारिज कर दी।

2. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने एपल और गूगल को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कहा था।

3. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक हटा लिया गया है लेकिन मंगलवार शाम तक एपल के प्लेटफॉर्म पर ऐप मौजूद था। गूगल ने कहा है कि वह इंडिविजुअल ऐप पर कमेंट नहीं कर सकता लेकिन स्थानीय कानून का पालन करता है। एपल की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

4. टिकटॉक के यूजर स्पेशल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं। ऐप एनालिटिक्स फर्म सेंसर टावर के मुताबिक फरवरी तक भारत में 24 करोड़ लोग टिकटॉक डाउनलोड कर चुके थे।

(Adapted from Bhaskar.com)

10. Heart made through 3-D printing- वैज्ञानिकों ने पहली बार 3डी प्रिंटिंग की मदद से बनाया कोशिकाओं और धमनियों वाला दिल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

इजराइली रिसर्चर्स ने हाल ही में 3डी प्रिंटिंग तकनीक की मदद से कोशिकाओं और धमनियों वाले दिल का निर्माण किया है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों ने मानव शरीर की टिश्यू (ऊतक) ही बनाए थे। वह भी बिना धमनियों वाले। खास बात यह है कि इसे एक इंसानी कोशिकाओं से ही बनाया गया है।

इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों द्वारा बनाया गया यह दिल अभी पूरी तरह काम करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, पहली बार वैज्ञानिक 3-डी तकनीक से कृत्रिम दिल बनाने के इतना करीब पहुंचे हैं। इससे पहले की कोशिशों में तो वैज्ञानिक सिर्फ दिल का डिजायन ही तैयार कर पाए थे, लेकिन उनमें रक्त धमनियां बनाना नामुमकिन साबित हो रहा था। धमनियों सहित दिल पहली बार तैयार हुआ है।

दिल बनाने के लिए बेहतर संसाधनों की जरूरत

3-डी प्रिंटेड दिल को खरगोश के दिल के आकार का बनाया गया है। हालांकि, रिसर्चर्स को विश्वास है कि जल्द ही वह इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाने लायक दिल भी तैयार कर लेंगे। दरअसल, इस जेनरेशन के 3-डी प्रिंट रेजोल्यूशन के मामले में सीमित हैं। ऐसे में ज्यादा महीन रक्त धमनियां बनाना मुश्किल साबित होता है। इस मुश्किल से पार पाते ही इंसानों के लिए दिल बनाना संभव हो जाएगा।

दिल को काम कराने की कोशिश जारी

कृत्रिम दिल बनाने वाली टीम के सदस्य और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर तल द्विर के मुताबिक, कोशिकाओं को अभी अपनी खुद की पम्पिंग क्षमता बनानी होगी। अभी वह सिकुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें एकसाथ काम करवाना असल चुनौती है। द्विर के मुताबिक, अगले 10 दिनों में वह लगातार दिल को काम कराने की कोशिश जारी रखेंगे।

दिल की बीमारी से हर साल करोड़ों मौतें

दुनियाभर में दिल की बीमारी हर साल करोड़ों लोगों की मौत हो जाती है। भारत, अमेरिका, यूरोप समेत लगभग सभी देशों में दिल की बीमारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गंभीर दिल की बीमारी के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट एक विकल्प के तौर पर उभर रहा है। हालांकि, आमतौर पर यह सिर्फ हार्ट फेल होने की आखिरी स्टेज में ही संभव है। साथ ही कई बार लोगों को सही दानकर्ता का इंतजार करना पड़ सकता है, जो कि बेहद खतरनाक है।

(Adapted from Bhaskar.com)

11. Chances of Ban on PUBG- PUBG Mobile Ban: भारत और नेपाल के बाद अब इस देश के लोग भी नहीं खेल पाएंगे यह गेम (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

PUBG Mobile को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस गेम को बैन किए जाने की खबरें तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर इस गेम को बैन कर दिया गया है और कई जगह होने वाले हैं। खासतौर से पेरेंट्स इस गेम को बैन करने की मांग कर रहे हैं। पेरेंट्स की मांग पर PUBG को गुजरात में बैन कर दिया गया था। अब UAE में भी ऐसा होने वाला है। पॉपुलर बैटल रॉयल गेम PUBG Mobile पर भारत में कई जगह पर बैन कर दिया गया है। इसके बाद इसे नेपाल में भी बैन किया गया है। अब खबर है की इराक में भी इसे बैन करने की बात चल रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मुद्दे को इराकी पार्लियामेंट द्वारा उठाया गया है। पार्लियामेंट द्वारा एक ड्राफ्ट लॉ सब्मिट किया गया है। इसमें लिखा है की PUBG लोगों की दिमाग पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसी के साथ इस गेम को बैन करने को लेकर मांग की गई है। कमेटी की हेड Sameaa ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा की - यूथ और बच्चों के बीच कमेटी इस इलेक्ट्रॉनिक गेम के बढ़ते क्रेज को लेकर परेशान है। यह गेम इराकी कम्युनिटी पर बूरा प्रभाव डाल रहा है और लोगों में हिंसा की मानसिकता पैदा कर रहा है।

इससे पहले इस गेम को नेपाल की फेडरल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी द्वारा बैन किया गया है। अथॉरिटी ने ISP, मोबाइल प्रोवाइडर्स और नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को PUBG को ब्लॉक करने के लिए बोल दिया था। इस कदम के लिए अथॉरिटी ने पुख्ता कारण दिए। अथॉरिटी को कई पेरेंट्स की शिकायत आई की इससे बच्चों की पढाई और उनके व्यवहार दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है।

(Adapted from Jagran.com)

12. Mars colony model in Gobi desert- गोबी के रेगिस्तान में बनाया मंगल ग्रह का मॉडल, लोग यहां देख सकेंगे कि लाल ग्रह पर जीवन कैसा होता है (Relevant for GS Prelims; Science & Tecnology)

चीन के जिन्चांग शहर से 40 किमी दूर गोबी रेगिस्तान में नकली मंगल ग्रह बनकर तैयार है। इसे लाल ग्रह का मॉडल या सिमुलेटर कहा जा रहा है। आम लाेगाें के लिए बुधवार काे इसे खाेल दिया गया। पहले दिन यहां 100 स्टूडेंट पहुंचे। यह करीब 5 घंटे खोला गया। यहां आने वाले सैलानी लाल ग्रह का अनुभव लेने के साथ ही उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। यहां जीवन कैसा होगा, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इसे 'मार्स बेस-1' नाम दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, यहां करीब 2 हजार 500 करोड़ रु. निवेश करने की योजना है। यहां हर साल 20 लाख पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है।

चीन का मिशन 'मार्स विलेज', हर साल 20 लाख पर्यटक पहुंचने की उम्मीद

चीन ने 2016 में अपने 2020 मार्स मिशन- 'मंगल गांव' की घोषणा की थी। इसके तहत वह 2020 तक मानवरहित यान भेजने की तैयारी में है। मार्स विलेज को मार्स मिशन 2022 का ही हिस्सा कहा जा रहा है। इस जगह को मंगल गांव के लिए इसलिए चुना गया है, क्योंकि इस पूरे इलाके में मंगल ग्रह जैसी पर्यावरणीय स्थितियां मौजूद हैं। यानी इसकी सतह मंगल ग्रह जैसी है- बंजर और पथरीली। यह पूरा प्रोजेक्ट 67,000 वर्ग किमी में फैला है।

(Adapted from Bhaskar.com)

13. Gene editing to treat lung disorders- वैज्ञानिकों ने विकसित की नई तकनीक, जीन में बदलाव करके ठीक किए जाएंगे फेफड़े संबंधी रोग (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में लगातार हो रहे बदलावों के कारण पिछले कुछ दशकों में श्वास रोगियों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। कई बार तमाम चिकित्सकीय उपचार भी रोगी को इससे छुटकारा नहीं दिला पाते। ऐसे में वैज्ञानिकों ने शोध कर इससे बचाव के उपाय बताए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि उनका यह प्रयोग अभी जानवरों पर सिद्ध हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आगामी समय में यह मनुष्यों को भी नई जिंदगी दे।

वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चूहों में घातक फेफड़े संबधी रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए जन्म से पूर्व ही उनके जीन में कुछ बदलाव (एडिटिंग) कर इन्हें बचाया गया है, क्योंकि यह बीमारी इतनी घातक है कि जन्म के कुछ घंटों बाद ही शिशु की मौत हो जाती है। साइंस ट्रांसलेशन मेडिसन जर्नल में प्रकाशित वैज्ञानिकों की इस अवधारणा में कहा गया है कि जन्म से पूर्व ही गर्भाशय में किए गए कुछ बदलाव फेफड़े संबंधी रोगों के उपचार के संबंध में नई राह दिखाते हैं।

अमेरिका के फिलाडेल्फिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल (सीएचओपी) की शोधकर्ता विलियम एच पेरांतेऊ ने कहा 'भ्रूण के विकास के दौरान उसके जन्मजात गुण उसे जीन एडिटिंग के लिए अनुकूल बनाते हैं।' उन्होंने कहा कि जन्म से पहले जीन एडिटिंग करने से रोग से बचाव और उसे कम करने में सहायता मिलती है। गर्भ में ही उसकी विकृतियों ठीक करने की यह प्रक्रिया अपने आप में बेहद रोमांचक है। शोधार्थियों की टीम ने उम्मीद जताई है कि इसके जरिए जन्म से ही फेफड़े स्वस्थ्य रहेंगे।

बाल अस्पतालों में 22 फीसद रोगी श्वास संबंधी:

बाल चिकित्सालयों में लगभग 22 प्रतिशत रोगी श्वसन संबंधी विकारों के भर्ती होते हैं। श्वास रोगियों की अच्छी देखभाल और उनके कारणों की गहरी समझ के बावजूद भी यह जन्मजात विकार बेहद घातक सिद्ध होते हैं, क्योंकि फेफड़ों का बाहरी वातावरण से सीधे संबंध होता है। इसीलिए, दोषपूर्ण जीन को ठीक करने के लिए यह थेरेपी सहायक सिद्ध हो सकती है। आम तौर यह देखा जाता है कि यह जन्मजात श्वास संबंधी रोग सर्फेक्टेंट प्रोटीन की कमी, सिस्टिक फाइब्रोसिस और अल्फा -1 एंटीट्रिस्पिन के कारण होते हैं।

अमेरिका की पेनसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड ई मौरिसे ने कहा कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह कैसे काम करता है। इस तकनीक के जरिये हम कैसे जीन में बदलाव कर सीधे फेफड़ों के वायुमार्ग की उन कोशिकाओं को ठीक कर सकते हैं जो इन रोगों का कारण बनती हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने दिखाया कि चूहे के भ्रूण के विकास के दौरान एमनियोटिक द्रव को (सीआरआइएपीआर) जीन एडिटिंग के जरिये ठीक समय में गर्भाशय में फैलाया गया। इससे चूहे के फेफड़ों में भी परिवर्तन देखा गया।

(Adapted from Jagran.com)

14. Possible health effects of E-cigarette: ई-सिगरेट पीने वाले हो जाएं सावधान, कैंसर समेत कई रोगों के हो सकते हैं शिकार (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

आमतौर पर धूमपान के विकल्प के रूप में पेश की जाने वाली ई-सिगरेट भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। एक शोध के मुताबिक, ई-सिगरेट में भी अस्थमा समेत ऐसी बीमारियों के कारक हो सकते हैं, जिनसे फेफड़े को खतरा होता है। अध्ययन में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ई-सिगरेट के 75 लोकप्रिय उत्पादों को शामिल किया। इनमें एक बार प्रयोग होने वाले और रीफिल किए जा सकने वाले उत्पाद शामिल थे। अध्ययन में 27 फीसद उत्पादों में एंडोटॉक्सिन पाया गया। यह एक माइक्रोबियल एजेंट है, जो ग्राम-नेगेटिव बैक्टीरिया पर पाया जाता ह। वहीं 81 फीसद उत्पादों में ग्लूकन के कण पाए गए। ग्लूकन अधिकतर फंगस की कोशिकाओं की दीवारों पर मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, ई-सिगरेट उत्पादों में इन तत्वों की उपस्थिति यह बताने की लिए पर्याप्त है कि इनके कारण भी अस्थमा और फेफड़े की अन्य बीमारियां हो सकती हैं।

सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए बाजार में आई ई-सिगरेट युवाओं के बीच काफी पसंद की जा रही है, लेकिन यह भी कम खतरनाक नहीं है। इसमें प्रयुक्त केमिकल जानलेवा हैं, इसके दुष्प्रभावों से पॉपकॉन लंग्स एवं लंग्स कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ई-सिगरेट के दुष्प्रभाव पर जीएसवीएम के रेस्पेरेटरी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ. सुधीर चौधरी अध्ययन कर रहे हैं। उनके मुताबिक ई-सिगरेट युवक, युवतियां और गर्भवती भी इस्तेमाल कर रही हैं। इसका उत्पादन करने वाली कंपनी व्यावसायिक लाभ के लिए इसे हानिकारक नहीं बताते हैं जबकि यह सिगरेट के बराबर हानिकारक है।

ई-सिगरेट क्या होती है

ई-सिगरेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक इन्हेलर है, जिसमें निकोटीन और अन्य केमिकलयुक्त लिक्विड भरा जाता है। ये इन्हेलर बैट्री की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है जिससे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसा एहसास होता है। लेकिन ई-सिगरेट में जिस लिक्विड को भरा जाता है वो कई बार निकोटिन होता है और कई बार उससे भी ज्यादा खतरनाक केमिकल। इसलिए ई-सिगरेट को सेहत के लिहाज से बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता है।

इस तरह आई ई-सिगरेट

वर्ष 2003 में चीन में ई-सिगरेट का अविष्कार हुआ। यह बैटरी से चलने वाला निकोटिन डिलीवरी का यंत्र है। इसमें द्रव्य पदार्थ, जिसे भाप कहते हैं, को गर्म करने के बाद मुंह से खींचा जाता है। इसे यह सोचकर बनाया गया था कि बिना टॉर या कार्बन के फेफड़े तक कम मात्रा में निकोटिन जाएगा। व्यावसायिक फायदे के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए, जिससे अधिक मात्रा में निकोटिन फेफड़े में जाने लगा।

क्या ई-सिगरेट सुरक्षित हैं?

ज्यादातर ई-सिगरेट्स में जो केमिकल भरा जाता है वो लिक्विड निकोटिन होता है। निकोटिन नशीला पदार्थ है इसलिए पीने वाले को इसकी लत लग जाती है। थोड़े दिन के ही इस्तेमाल के बाद अगर पीने वाला इसे पीना बंद कर दे, तो उसे बेचैनी और उलझन की समस्या होने लगती है। निकोटिन दिल और सांस के मरीजों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता है।

हो जाएंगे पॉपकॉन लंग्स से पीड़ित

महानगरों में ई-सिगरेट एवं हुक्का बार का चलन तेजी से बढ़ा है। हुक्का बार में फ्लेवर्ड ई-लिक्विड होता है जबकि ई-सिगरेट में केमिकल वेपर के रूप में होता है। दोनों में हानिकारक डाई एसिटाइल केमिकल (बटर जैसा जो पॉपकॉन में मिलाते थे, अब प्रतिबंधित) होता है। इसके सेवन से फेफड़े में पॉपकॉन जैसा उभरने पर पॉपकॉन लंग्स कहते हैं। इस बीमारी को ब्रांक्योलाइटिस आब्लिट्रेन कहा जाता है। इसमें फेफड़ों की छोटी श्वांस नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जो आगे चलकर आइएलडी में परिवर्तित हो जाती है। इसकी चपेट में आकर युवा एवं महिलाएं तेजी से फेफड़े की बीमारी का शिकार हो रहे हैं।

ई-सिगरेट के खतरे

- युवाओं में ई-सिगरेट तेजी से पॉपुलर हो रहा है
- ई-सिगरेट को बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जा सकता है
- ई-सिगरेट में सामान्य सिगरेट की तरह तंबाकू का इस्तेमाल नहीं होता है
- निकोटिन नशीला पदार्थ है इसलिए पीने वाले को इसकी लत लग जाती है

ई-सिगरेट की क्वाइल में हानिकारक मेटल

ई-सिगरेट के वेपर को गर्म करने के लिए क्वाइल का इस्तेमाल होता है। क्वाइल में निकोटिन, फार्मालडिहाइड, फेनाले, टिन, निकिल, कॉपर, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक एवं डाई एसेटाइल मेटल हैं।

(Adapted from Jagran.com)

15. Removal of Ban on Tik Tok app - आप फिर से बना पाएंगे TikTok, जानें ऐप पर लगे बैन की पूरी कहानी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

TikTok पर मद्रास हाईकोर्ट से बैन लगने के बाद कंपनी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने ऐप पर बैन लगाते हुए इसे Google Play Store और Apple App Store से बैन कर दिया था। लेकिन अब यह बैन हट चुका है। कोर्ट ने TikTok के अंतरिम बैन को अब हटा दिया है। TikTok ने कोर्ट से कहा है कि पिछले 7 महीनों से किसी भी तरह के अभद्र कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रीमूव करने के लिए कंपनी कई तरीके लागू कर रही है। साथ ही यह ऐप किसी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं करती है। आपको बता दें कि कोर्ट ने अभी केवल अंतरिम बैन हटाया है। TikTok फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म को बिना किसी रूकावट के ऑपरेट कर सकती है। यहां हम आपको TikTok पर लगे बैन से संबंधित पूरी कहानी बता रहे हैं।

जानें मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है?

मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok पर से अंतरिम बैन को हटा दिया है। कोर्ट की बेंच ने कहा है कि वो बच्चों को साइबर अपराध से बचाने में रुचि रखता था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि साइबर स्पेस में बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत के पास US COPPA जैसा कानून नहीं है।

इससे पहले क्या हुआ था?

मद्रास हाईकोर्ट ने भारत में TikTok पर अंतरिम बैन लगाया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यह प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट को प्रमोट कर रहा था। इसी के चलते TikTok के डाउनलोड्स पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था। इसे Google Play Store और Apple App Store से डाउनलोड करने पर कोर्ट ने बैन किया था।

TikTok प्ले स्टोर पर क्यों नहीं है उपलब्ध?

वैसे तो कोर्ट ने इस ऐप पर से बैन हटा दिया है। इस बैन को 24 अप्रैल को हटाया गया है। ऐसा हो जाने के बाद, सरकार को इस मामले को लेकर Google और Apple को आधिकारिक तौर पर सूचित करना होगा। यानी सरकार Google और Apple से इस ऐप पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कहा जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है और यही वजह है कि फिलहाल यूजर्स इस ऐप को अभी तक ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।

TikTok ने खुद का कैसे किया बचाव?

TikTok ने कहा कि बिना कंपनी की बात सुने कोर्ट ने उसकी ऐप पर बैन लगा दिया। कंपनी ने दावा किया है कि उनके पास एक ऐसी तकनीक है जो किसी भी तरह के गलत या अश्लील कंटेंट को ऑनलाइन जाने से रोकती है। TikTok इस तकनीक को कम्यूनिटी गाइडलाइन्स को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कंपनी के वकील ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कंपनी संविधान के मानदंडों का पालन नहीं कर रही है।

TikTok का क्या होगा अगला कदम?

जब इस बैन को हटाया गया तो TikTok ने कहा कि वो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि उसके प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह का गलत या अश्लील कंटेंट न जाए। साथ ही चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। TikTok ने आधिकारिक बयान में कहा है, "हम इस निर्णय को सुनकर बहुत खुश हैं। हम इस बात के आभारी है कि हमें अपने यूजर्स को बेहतर सर्विस देने का दोबारा मौका मिला है। हम इस बात से खुश हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने के हमारे प्रयासों को मान्यता दी गई है।"

TikTok के बैन को लेकर दर्ज की थी याचिका:

TikTok को बैन करने के पीछे का कारण यह रहा था की इस ऐप के खिलाफ याचिका दायर किया गयी थी। इस याचिका में कहा गया था की इस ऐप में हमारी संस्कृति को अपमानित किया जा रह है। इसी के साथ ऐप में कंटेंट के सब्जेक्ट को लेकर भी कुछ परेशानी थी। TikTok पर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन भी कर रहा है। इससे ऐप को इस्तेमाल करने वाले काम उनर के बछ्कों पर गलत असर पड़ रहा था। इस याचिका में एक उदाहरण भी दिया गया था जिसके मुताबिक, कुछ बच्चों ने ऐप के कारण आत्महत्या कर ली। इसमें दावा किया गया था कि इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं हैं।

(Adapted from Jagran.com)

16. What is card cloning- कैसे होती है कार्ड क्लोनिंग, जान लीजिए आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

पिछले कुछ सालों में कार्ड क्लोनिंग एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। पिछले कुछ महीनों में कार्ड क्लोनिंग से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। कार्ड क्लोनिंग की वजह से लोगों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। कई गिरोह को नकली एटीएम कार्ड का उपयोग कर पैसा लूटने के लिए पकड़ा गया है।

कार्ड क्लोनिंग क्या है?

क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग या स्किमिंग में कोई फ्रॉड व्यक्ति आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी, पिन, एक्सपायरी डेट, नाम आदि जैसी जानकारी को एकत्रित करता है। इसके बाद उस जानकारी को नकली या फर्जी कार्ड पर कॉपी करता है और उसके बाद क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पिछले कुछ सालों में वेटर्स, शॉप असिस्टेंट, कुरियर बॉय, पूर्व बैंक कर्मचारी, पेट्रोल पंप कर्मी और एमबीए स्टूडेंट्स को कार्ड की जानकारी चुराने और करोड़ों रुपये का फ्रॉड करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

कार्ड कैसे क्लोन किए जाते हैं?

कार्ड होल्डर को बिना बताए कार्ड क्लोन करने के लिए स्कैनिंग स्लॉट वाली डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मशीन दिखने में PoS मशीनों की जैसी होती है, जिसकी वजह से कार्ड होल्डर को पता भी नहीं चलता और नुकसान हो जाता है। कई जालसाज डिवाइस के जरिए ग्राहकों के क्रेडिट-डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं। फ्रॉड के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इन मशीनों में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें 3 हजार कार्ड तक की जानकारी रखी जा सकती है।
जब कार्ड की जानकारी स्कैन और कॉपी की जाती है और उसके बाद कार्ड का क्लोन बनाने के लिए किसी एक्सपायर्ड, खाली या चोरी हुए कार्ड पर कॉपी कर सकते हैं। इस क्लोन कार्ड से अब क्रेडिट कार्डधारक के बैंक अकाउंट से लेनदेन करने के लिए किया जा सकता है।

ऐसे कर सकते हैं बचाव: आरबीआई ने मैगस्ट्रिप कार्ड की जगह ईएमवी चिप-बेस्ड कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। EMV कार्ड में माइक्रोचिप्स होती है। जब कोई इस कार्ड को स्कैन करने की कोशिश करता है तो सिर्फ एन्क्रिप्टेड जानकारी ही मिलती है। वर्तमान में आप मैगस्ट्रिप कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बदल कर ईएमवी चिप-बेस्ड कार्ड को इस्तेमाल करें।

सार्वजनिक स्थान पर कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त यह देख लें वो जगह कैमरों से छिपी हुई है और ताकि ऐसी जगह पर आपका कार्ड नंबर और कार्ड की अन्य जानकारी आदि किसी और के पास न जाए। पीओएस मशीनों में कार्ड पिन दर्ज करते वक्त उसे अपने हाथ से कवर करना चाहिए।
रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप या अन्य किसी जगह पर पीओएस मशीनों से कार्ड स्वाइप करने के लिए मशीन को ठीक से देख लीजिए। अगर मशीन सामान्य से अधिक भारी है तो किसी और तरह से पेमेंट करने पर विचार कीजिए।

अगर आपका कार्ड क्लोन हो जाता है आपके बैंक से बार-बार कार्ड स्वाइप होने पर कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो ऐसे में मंथली स्टेटमेंट के अलावा जानकारी एकत्रित करना का कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए हमेशा बैंक अलर्ट जारी रहना चाहिए और समय-समय पर इसे देखना चाहिए।

(Adapted from Jagran.com)

17. Payment of small amount without swiping from the card-बिना स्वाइप किए इस कार्ड से हो जाता है छोटी रकम का पेमेंट, जानें कैसे करता है यह काम (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

अगर आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया है और बैंक ने आपको नया कार्ड भेजा है तो जरा देखिए कि क्या कार्ड के फ्रंट साइड पर वाई-फाई जैसा चिन्ह बना हुआ है? अगर ऐसा है तो आपका यह कार्ड कॉन्टेक्टलैस कार्ड है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको छोटी खरीदारी करते वक्त इस कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत नहीं है। नवीनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित कॉन्टेक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग के लिए किया जा सकता है।

कॉन्टेक्टलेस कार्ड 2000 रुपये से कम की खरीदारी के पेमेंट का सबसे फास्ट तरीका है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस कार्ड की लिमिट तय की है। किसी भी बैंक की तरफ से जारी इस तरह के सभी क्रेडिट या डेबिट कार्ड एक ही लिमिट के अंदर आते हैं। इन कार्डों के अंदर टर्मिनल से रेडियो फ्रिक्वेंसी की पहचान करने के लिए एक चिप और एक एंटीना होता है। जब कोई ग्राहक कार्ड रीडर के 4 सेंटीमीटर के अंदर कार्ड पर टैप करता है तो एन्क्रिप्टेड कार्ड और पिन की जानकारी वायरलेस तरीके से टर्मिनल में पहुंच जाती है और उससे पेमेंट पूरी हो जाती है।

यह भी जरूरी है उस स्टोर का स्वाइप डिवाइस (कार्ड रीडर) नियर-फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) टेक्नोलॉजी से लैस हो, जिससे आपका कार्ड सिर्फ एक टैप से पेमेंट कर पाने में सक्षम हो। अगर ऐसा हो सकता है तो 2,000 रुपये से कम के सभी ट्रांजेक्शन सिर्फ एक टैप के जरिए पूरी हो जाएंगी और पिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अगर ट्रांजेक्शन 2,000 रुपये से अधिक की है तो आपको कॉन्टेक्टलेस कार्ड का उपयोग भी सामान्य डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह ही करना होगा। स्टोर कीपर को इसे डिप करना होगा या इसे स्वाइप करना होगा और फिर आपको अपना पिन डालना होगा।

(Adapted from Jagran.com)

सामाजिक मुद्दे

1. Hearing in Supreme Court to ban Tik Tok app- सुप्रीम कोर्ट में TikTok ऐप बैन को लेकर सुनवाई (Relevant for GS Mains Paper I; Social Issues)

TikTok ऐप को बैन करने का मामला हाईकोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया वीडियो क्रिएटर ऐप TikTok पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर एक अपील दायर की गई। इसी अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

मद्रास हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में केन्द्र सरकार से इस शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप TikTok को बैन करने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मीडिया हाउस को TikTok ऐप द्वारा बनाए गए फनी और अन्य तरह के वीडियोज को टेलीकास्ट करने से भी रोका था।

हाई कोर्ट ने क्या तर्क दिया था
मद्रास हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को इस चीनी ऐप को बैन करने के पीछे एक बड़ा तर्क दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये चीनी ऐप भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एन किरूबाकरण और एसएस सुंदर ने केन्द्र सरकार से 16 अप्रैल से पहले जबाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केन्द्र सरकार से ये भी जवाब मांगा है कि क्या केन्द्र सरकार अमेरिका की तरह चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट की तरह ही कोई नीति ला सकती है जो बच्चों को ऑनलाइन विक्टिम बनने से रोक सके?

TikTok ऐप के बारे में

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TikTok ऐप के इस समय भारत में 54 मिलियन यानी 5.4 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि एक बड़ा सवाल है। मद्रास हाईकोर्ट ने TikTok ऐप के विरोध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए इस ऐप को बैन करने का आदेश दिया है। मदुरै के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजिक कार्यकर्ता मूथू कुमार ने कल्चरल डिग्रेडेशन, चाइल्ड अब्यूज और सुसाइड को बढ़ावा देने के लिए TikTok ऐप के विरोध में याचिका दायर की थी।

(Adapted from Jagran.com)

2. Problem of ageing in Japan- जापान में बुजुर्गों की बढ़ती आबादी बन रही बड़ी चुनौती, 2050 तक 79 फीसद लोग होंगे बूढ़े (Relevant for GS Prelims & Mains Paper- I; Social issues)

ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने आगाह किया है कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी जापान के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। जापान में 2017 में 50 फीसद आबादी की उम्र 65 वर्ष से ऊपर थी। वर्ष 2050 तक इसके बढ़कर 79 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

देश की कामगार आबादी में यह गिरावट जापान के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ओईसीडी की महासचिव एंजेल गुरिया ने सोमवार को यहां अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, 'जापान में 2017 में जन्म लेने वाले बच्चों में से आधे की 107 साल की उम्र तक जीवित रहने की संभावना है।'

जापान के जनांकिकी आंकड़े सामने रखते हुए ओईसीडी की महासचिव ने कहा कि अगर यही आगे भी चलता रहा तो 2050 तक देश के कामगार लोगों की आबादी में 25 फीसद तक की कमी हो सकती है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए रिपोर्ट में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की सिफारिश की गई है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रखने के लिए ओईसीडी ने सरकार से विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखने की सिफारिश भी की है।

(Adapted from Jagran.com)

3. Muslim women seeking entry in moque- मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश और नमाज की इजाजत की मांग, कपल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Social Issues)

पुणे में मुस्लिम कपल ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश को लेकर याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग और सेंट्रल वक्फ काउंसिल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि सरकार का इसमें क्या रोल है। कपल की ओर से दायर इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाओं को नमाज पढ़ने की अनुमित होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की दलील है कि पवित्र कुरान और मोहम्मद साहेब ने महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश का कभी विरोध नहीं किया।

कोर्ट में दी गईं ये दलीलें

- इसी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान अलग-अलग दलीलें दी गईं। एक पक्ष ने बताया कि कनाडा में मस्जिद के अंदर महिलाओं को प्रवेश की इजाजत है। जबकि दूसरी दलील ये दी गई कि सऊदी अरब के मक्का-मदीना में भी मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश दिया जाता है।

- इन तमाम दलीलों के बीच पीठ ने पूछा कि क्या इस मसले पर अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या मस्जिद और मंदिर सरकार के हैं। जैसे आपके घर में कोई आना चाहे तो आपकी इजाजत जरूरी है। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में सरकार की क्या भूमिका है।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

- याचिकाकर्ता ने अपनी अपील में कोर्ट को बताया कि भारत में मस्जिदों के अंदर महिलाओं को नमाज पढ़ने की इजाजत न होना न सिर्फ अवैध है, बल्कि संविधान की मूल आत्मा का भी उल्लंघन है। ऐसा कहते हुए मुस्लिम कपल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि महिलाओं को भी मस्जिद में नमाज अदा करने की परमिशन दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है, इसी फैसले का हवाला देते हुए याचिकार्ताओं ने मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग की।

(Adapted from Bhaskar.com)

4. By 2020, Aged will constitute 20% of Indian population- 2050 तक 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी बुजुर्गों की संख्या (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Social Issues)

भारत की जनसंख्या में 2050 तक 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या में 20 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। बीते कुछ सालों में भारत में बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह क्रम लगातार बना रहने वाला है। सोमवार को यह बात यूएन में भारत के स्थाई अभियान की पहली सचिव पालोमी त्रिपाठी ने उम्रवृद्धि को लेकर काम करने वाले समूह से कही।

2050 में 8 से 20% लोग 60 साल के ऊपर होंगे

1. त्रिपाठी ने बताया कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं, जहां लोग पहले के मुकाबले अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं। 2050 में कुल जनसंख्या के 8-20 प्रतिशत लोग 60 साल से ज्यादा के होंगे।

2. मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ने 2002 में उम्रवृद्धि पर हुई दूसरी विश्व सभा में प्रस्ताव रखा था कि 21वीं सदी में उम्रवृद्धि से निपटने के लिए बोल्ड एजेंडा होना चाहिए।

3. इसके अंतर्गत तीन प्राथमिकताएं तय की गईं। इसमें बुजुर्ग व्यक्ति और विकास, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था और उनके प्रति सहयोगीपूर्व वातावरण उपलब्ध कराए जाने की बात हुई।

4. यूएन ने कहा कि व्यक्तियों के अनुपात के अनुसार 2007 से 2050 के बीच 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। हो सकता है कि कई देशों में ऐसे लोगों की संख्या वास्तविक तौर पर तीन गुनी बढ़ जाए।

5. त्रिपाठी ने कहा, "हमें वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, बढ़ता निवेश और अंतराल को दर्शाता डाटा इस प्रक्रिया में अहम होंगे।"

6. यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 की रिपोर्ट बीते सप्ताह जारी की गई। 2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 बिलियन है। 1994 में भारत की जनसंख्या में छह फीसदी लोग 65 साल या इससे बड़े थे।

7. त्रिपाठी के मुताबिक भारत में बुजुर्ग व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम' लॉन्च की गई। भारत में भी जन्म-मृत्यु दर में सुधार आया है। 1969 में औसत आयु 47 साल, 1994 में 60 साल थी। 2019 में यह आंकड़ा 69 साल हो गया है।

8. त्रिपाठी ने कहा, "भारत बुजुर्गों के जीवन स्तर में सुधार करने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें उम्रवृद्धि को लेकर बनाए गए मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन और 2030 के लिए सुनिश्चित किए गए एजेंडे को पूर्ण रूप से लागू करना शामिल है।"

(Adapted from Bhaskar.com)

5. TikTok App ban in India: जानें अब तक की हर छोटी बड़ी डिटेल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper I; Social Issues)

TikTok एक लोकप्रिय वीडियो क्रिएटिंग और शेयरिंग ऐप है। इतनी लोकप्रिय होते हुए भी इसे भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। ऐप को बैन करने का फैसला मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच की तरफ से लिया गया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया था। TikTok ऐप ByteDance की कंपनी के तहत आती है। TikTok ने इस बैन पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। इसकी अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

Google और Apple ने रिमूव की TikTok ऐप

Google और Apple ने अपने ऐप स्टोर से TikTok को रिमूव कर दिया है। Google के प्रवक्ता ने कहा है कि पॉलिसी के तहत हम किसी ऐप पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं लेकिन हम जिस देश में ऑपरेट करते हैं वहां के नियमों का पालन करना जरूरी है। इसका सीधा मतलब यह कि अब से कोई नया यूजर इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएगा।

TikTok ने जारी किया ये बयान

जिन यूजर्स ने अपने मोबाइल पर TikTok ऐप डाउनलोड की ही है वो इसे बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमे सुप्रीम कोर्ट में बैन हटाने को लेकर अपील की है जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। **TikTok** ने अपनी ऐप पर इसके लिए एक अंतरिम ऑर्डर भी जारी किया है जिसका स्क्रीनशॉट हमने आपको नीचे दिया है।

TikTok के बैन को लेकर दर्ज की गई थी याचिका

TikTok को बैन करने की याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि इस ऐप पर हमारी संस्कृति को अपमानित किया जा रहा है। साथ ही अनुचित कंटेंट को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह बच्चों पर गलत असर डालता है। इस याचिका में एक उदाहरण भी दिया गया था जिसके मुताबिक, कुछ बच्चों ने ऐप के कारण आत्महत्या कर ली। इसमें दावा किया गया था कि इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसके अलावा TikTok पर यह आरोप भी लगाया गया था कि वो यूजर्स की प्राइवेसी पॉलिसी का उल्लंघन भी कर रहा है।

मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप को किया था बैन

मद्रास हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केन्द्र सरकार से TikTok को बैन करने की सलाह दी थी। इसके अलावा कोर्ट ने किसी भी मीडिया हाउस को TikTok ऐप द्वारा बनाए गए वीडियो को टेलिकास्ट करने से भी मना किया था। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से ऐप को बैन करने के आदेश में कहा था कि यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रही है।

(Adapted from Jagran.com)

आंतरिक सुरक्षा

1. Proect to acquire 6 submarines-नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियां हासिल करने की प्रक्रिया शुरू (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Internal Security)

रक्षा मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी सामरिक साझेदारी मॉडल के तहत नौसेना के लिए छह अत्याधुनिक पनडुब्बियां हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पर करीब 45 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

इन पनडुब्बियों का निर्माण पी-75(आइ) कार्यक्रम के तहत भारतीय रक्षा निर्माण कंपनी और विदेशी पनडुब्बी निर्माता द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इनमें एंटी-शिप क्रूज मिसाइलें और अन्य विध्वंसक हथियार भी लगाए जाएंगे।

सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि प्रमुख पनडुब्बी निर्माताओं को चार हफ्ते में 'एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट' जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस मेगा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जनवरी में गठित अधिकार प्राप्त समिति पहले ही चुनिंदा भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ बातचीत कर चुकी है।

इन कंपनियों में अडानी डिफेंस, लार्सन एंड टुब्रो और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने 'एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट' का मसौदा पहले ही तैयार कर लिया है और इसे संभावित कंपनियों के साथ साझा भी किया गया है। मालूम हो कि 'प्रोजेक्ट 75' के तहत पहले ही नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इनका डिजायन फ्रांसीसी कंपनी नैवल ग्रुप ने तैयार किया है।

(Adapted from Jagran.com)

2. Raids against ISIS module in Hyderabad and Wardha- भारत में ISIS मॉड्यूल के खिलाफ NIA ने हैदराबाद और महाराष्ट्र के वर्धा में की छापेमारी (Relevnat for GS Mains Paper-III; Internal Security)

भारत में ISIS के विस्तार के शक में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) पूरी तरह से चौकन्नी है। भारत में आइएसआइएस मॉड्यूल के खिलाफ एनआइए हैदराबाद और वर्धा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। शनिवार सुबह एनआइए ने हैदराबाद के दो और वर्धा में एक जगह पर छापेमारी की है।

बता दें कि इसके पहले एनआइए ने अगस्त 2018 में छापेमारी के दौरान आइएसआइएस से जुड़े दो संदिग्धों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इन दोनों संदिग्धों पर भारत में आइएसआइएस

की विचारधारा को फैलाने का आरोप था। अगस्त 2018 में हुई गिरफ्तारी में दोनों संदिग्धों की पहचान मोहम्मद अब्दुल्ला बाषित और मोहम्मद अब्दुल कादिर के तौर पर हुई थी।

(Adapted from Jagran.com)

विविध विषय

1. Facebook deleted 687 pages associated with Congress- फेसबुक का कड़ा कदम, डिलीट किए कांग्रेस से जुड़े 687 पेज (Read only for understanding)

आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह होने से बचाने के लिए फेसबुक ने बड़ा कदम उठाया है। फेसबुक ने कांग्रेस की आइटी सेल से जुड़े ऐसे 687 पेज और अकाउंट को हटा दिया है, जिनकी पहचान संदिग्ध थी। इन्हें संचालित करने वाले लोग पहचान छुपाकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। फेसबुक ने भाजपा के समर्थन में पोस्ट करने वाली एक आइटी कंपनी से जुड़े 15 पेज और अकाउंट भी हटाए हैं। इन सभी को को-ऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर का दोषी पाया गया।

फेसबुक में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रमुख नाथनियल ग्लीचर ने बताया कि जिन पेज को हटाया गया है, उनमें से ज्यादातर को फेसबुक के ऑटोमेटेड सिस्टम ने पहले ही पहचान कर सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने बताया, 'हमने इन्हें हटा दिया, क्योंकि इन्हें संचालित करने वाले लोग फर्जी अकाउंट के जरिये अपनी पहचान छिपा रहे थे। हम लगातार को-ऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर में लिप्त अकाउंट और पेज की पहचान काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए हो।' ग्लीचर ने बताया कि इन पेज और अकाउंट से स्थानीय खबरों और राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी पोस्ट की जाती थी। उम्मीदवारों व कांग्रेस पार्टी के विचार तथा भाजपा की आलोचना वाली पोस्ट भी इनसे बहुतायत में की जाती थी। जांच करने पर इनका संबंध कांग्रेस आइटी सेल से जुड़े लोगों से पाया गया। इनके अलावा फेसबुक ने भाजपा का समर्थन करने वाली आइटी फर्म सिल्वर टच से जुड़े 15 पेज, ग्रुप व अकाउंट हटाने की बात भी कही है। इनमें भी संचालित करने वालों ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी।

क्या है को-ऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर? : कुछ पेज या अकाउंट द्वारा मिलकर एक-दूसरे की पहचान छिपाने की कोशिश को को-ऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर कहा जाता है। सभी पेज या अकाउंट मिलकर लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसा होने से इनकी पोस्ट देख रहे यूजर को यह अंदाजा नहीं लग पाता है कि पेज या अकाउंट को संचालित कौन कर रहा है। माना जाता है कि राजनीतिक दल अपने विरोधी दल के लोगों की पहचान चुराकर ऐसे पेज बनाते हैं।

फेसबुक ने बताया कि कांग्रेस के आइटी सेल से जुड़े जिन पेज व अकाउंट को हटाया गया है, उनकी ओर से फेसबुक पर विज्ञापन भी दिया जाता था। पहला विज्ञापन अगस्त, 2014 में और आखिरी विज्ञापन मार्च, 2019 में दिया गया था। इन विज्ञापन पर कुल 39,000 डॉलर (करीब 27 लाख रुपये) का खर्च किया गया था।

(Adapted From Jagran.com)

2. Nugen Mobility Summit- न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 (Relevant for GS Prelims)

अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीएटी) 27 - 29 नवंबर, 2019 के दौरान एनसीआर स्थित मानेसर में 'न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019' का आयोजन करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य स्मार्ट एवं हरित भविष्य के लिए उन्नत ऑटोमोटिव तकनीकों के त्वरित अनुपालन, समावेशन एवं विकास हेतु नये विचारों, जानकारियों, वैश्विक अनुभवों, नवाचारों और भावी तकनीकी रुझानों को साझा करना होगा। इस आयोजन से ऑटोमोटिव उद्योग के सभी हितधारकों को एकजुट करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी जहां प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हुई प्रगति को समझने के लिए चर्चाएं होंगी।

आईसीएटी क्या है?

आईसीएटी मानेसर भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अधीनस्थ नैट्रिप इम्प्लीमेंटेशन सोसायटी (नैटिस) का एक प्रभाग है। यह सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए परीक्षण, प्रमाणीकरण, डिजाइन और संगतता (होमोलोगेशन) से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराता है। इसने वाहन आकलन और कलपुर्जों के विकास से जुड़ी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने में ऑटोमोटिव उद्योग की मदद करने का मिशन शुरू किया है, ताकि विश्वसनीयता एवं टिकाऊपन के साथ-साथ नई पीढ़ी के मोबिलिटी सॉल्यूशंस से जुड़े वर्तमान एवं भावी नियम-कायदों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

(Adapted from PIB)

3. UPSC Civil Services Result 2018: कनिष्क, अक्षत, जुनैद, श्रेयांस और सृष्टि देशमुख हैं टॉपर्स, देखें लिस्ट (केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़े)

संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा की फाइनल परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। इसमें बांबे आइआइटी से बी. टेक कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है, जबकि सृष्टि जयंत देशमुख महिलाओं में अव्वल आई हैं। वैसे ओवर ऑल में उनकी पांचवीं रैंक है।

यूपीएससी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयोग ने आइएएस, आइपीएस, आइएफएस जैसी सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 759 (577 पुरुष तथा 182 महिला) उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की है। अनुसूचित जाति से आने वाले कटारिया ने कंप्यूटर साइंस में बी. टेक किया है। उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में गणित लिया था। महिलाओं में शीर्ष आने वाली देशमुख, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से केमिकल इंजीनियरिंग में बी.ई हैं। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा तीन जून 2018 को आयोजित की गई थी।

सृष्टि ने कहा- यह उनका बचपन का सपना था

यूपीएससी फाइनल परीक्षा में महिलाओं में भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख ने टॉप किया है। अव्वल आने के बाद सृष्टि जयंत देशमुख ने कहा कि यह उनका बचपन का सपना था। सृष्टि जयंत देशमुख ने अपने पहले ही प्रयास में यह कामयाबी हासिल की है। उन्होंने भोपाल के कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग में बीई की उपाधि हासिल की है। अव्वल आने की सूचना के बाद सृष्टि जयंत देशमुख ने अपने परिजनों के साथ जश्न मनाया।

इस परीक्षा के लिए कुल 10,65,552 उम्मीदवारों ने आवेदन सौंपा था। इनमें से कुल 4,93,972 ही परीक्षा में शामिल हुए। लिखित (मुख्य) परीक्षा के लिए कुल 10,468 उम्मीदवार सफल हुए थे। यह परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2018 में ली गई थी। व्यक्तित्व जांच के लिए कुल 1994 उम्मीदवार चुने गए थे।

फरवरी-मार्च 2019 में व्यक्तित्व जांच आयोजित की गई। शीर्ष 25 उम्मीदवारों में 15 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। जिन उम्मीदवारों की अनुसंशा की गई है उनमें 36 दिव्यांग हैं। दूसरे स्थान पर आने वाले अक्षत जैन आइआइटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। जयपुर निवासी अक्षत के पिता आइपीएस अधिकारी हैं जबकि मां भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने गृह प्रदेश राजस्थान में सेवा देना चाहूंगा।

ये हैं टॉपर

1. कनिष्क कटारिया
2. अक्षत जैन
3. जुनैद अहमद
4. श्रेयांस कुमात
5. सृष्टि जयंत देशमुख
6. शुभम गुप्ता
7. कर्नाटी वरूणरेड्डी
8. वैशाली सिंह
9. गुंजन द्विवेदी
10. तन्मय वशिष्ठ शर्मा

759 का परिणाम घोषित

बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से यह परीक्षा नौकरशाही के उच्च पदों के लिए आयोजित की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सितंबर-अक्टूबर 2018 में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके परिणाम के बाद फरवरी-मार्च 2019 में इंटरव्यू हुआ। जिसके बाद आज अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं।

संघ लोक सेवा आयोग की ओर से इस बार कुल 759 उम्मीदवारों ((577 पुरुष और 182 महिलाएं) के परिणाम घोषित किए गए हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के 361, अन्य पिछड़े वर्गों से 209, अनुसूचित जाति के 128, अनुसूचित जनजाति के 61 उम्मीदवार शामिल हैं। इन उम्मीदवारों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के अलावा केंद्रीय सेवाओं की प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उम्मीदवार शामिल हैं।

ऐसे देखें परिणाम

संघ लोक सेवा की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अपना परिणाम निम्न प्रकार से चेक कर सकते हैं।

- सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://upsc.gov.in) पर जाएं।
- यहां आपको दाईं ओर What's News का कॉलम मिलेगा।
- इस कॉलम में 'Final Result: Civil Service Examination, 2018' पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करने के बाद परीक्षा परिणाम की फाइल (PDF File) खुल जाएगी।
- इस फाइल में परीक्षार्थी अपना रोल नंबर चेक सकते हैं।

(Adapted from Jagran.com)

4. Indian Air force presented evidence of shooting down F-16 - वायुसेना ने रडार इमेज जारी कर कहा- पाक के एफ-16 मार गिराने के हमारे पास विश्वसनीय सबूत (Read only for understanding)

भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर पाक वायुसेना की घुसपैठ के दौरान उनके एक एफ-16 फाइटर जेट को मार गिराने का सबूत पेश किया। वायुसेना ने एयरबॉर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवाक्स) रडार द्वारा खींची गई तस्वीरों को जारी किया। इसमें पाकिस्तान के दो एफ-16 और एक जेएफ-17 दिखाई दे रहे हैं।

आईएएफ ने बयान में कहा- हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि पीएएफ ने 27 फरवरी को एफ-16 का इस्तेमाल किया था। यह भी तथ्य है कि हमारे मिग-21 बायसन ने एफ-16 को मार गिराया था। इसमें कोई शक नहीं है कि 27 फरवरी को हवाई मुठभेड़ में दो एयरक्राफ्ट नष्ट हुए थे। एक हमारा बायसन था और दूसरा पाक का एफ-16। इसकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रेडियो ट्रांस्क्रिप्ट के जरिए भी हुई।

पाक के बयानों से हमारे दावे की पुष्टि हुई- एयर वाइस मार्शल

एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने कहा कि हमारे पास और ज्यादा विश्वसनीय सबूत हैं कि घुसपैठ के दौरान पाकिस्तान ने अपना एफ-16 फाइटर खोया था। लेकिन, सुरक्षा और गोपनीयता के चलते हम इस सूचना को सबके सामने नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन (डीजी-आईएसपीआर) द्वारा जारी कुछ बयानों से भी हमारे दावे की पुष्टि होती है।

पाक ने पायलटों को लेकर झूठ बोला- वायुसेना

कपूर ने बताया- डीजी-आईएसपीआर ने अपने शुरुआती बयान में कहा था कि 3 पायलट हैं। इनमें से एक को हिरासत में लिया गया है और दो अभी क्षेत्र में हैं। हालांकि, इसके बाद डीजी-आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरा के सामने कहा था कि हमारे पास दो पायलट हैं। इनमें से एक कस्टडी में और दूसरा अस्पताल में भर्ती है। इस बयान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के

बयान ने भी पुष्ट किया था। इससे साबित होता है कि उस दिन 2 एयरक्राफ्ट मार गिराए गए थे।

पाक वायुसेना के रेडियो सिग्नल भी इंटरसेप्ट किए थे- सूत्र

इससे पहले वायुसेना के सूत्र ने कहा था कि 27 फरवरी को भारत पर हुए हमले के दौरान आईएएफ ने पाकिस्तान की वायुसेना के रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट किए थे। उसने बताया कि विंग कमांडर अभिनंदन ने एफ-16 को पाकिस्तान की सीमा के 7-8 किलोमीटर भीतर मार गिराया था। इसमें पाकिस्तानी वायुसेना ने रेडियो पर हुई बातचीत में खुद इस बात की पुष्टि की थी कि उनका एफ-16 बेस पर नहीं लौटा है।

(Adapted from Bhaskar.com)

5. HRD ministry released ranking of educational institutions-एचआरडी मिनिस्ट्री ने जारी की देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की लिस्ट, IIT मद्रास टॉप पर (Relevant for GS Prelims)

भारत सरकार की मानव संसाधन मंत्रालय (एचआरडी) ने सोमवार को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की। इसमें शीर्ष के 10 स्थानों में सात आइआइटी का जलवा देखने को मिला। इस रैंकिंग में सबसे पहला स्थान आइआइटी मद्रास को मिला है।

यह सूची एचआरडी विभाग ने जारी की है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु को दूसरा स्थान और आइआइटी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। इस लिस्ट में टॉप 10 के शिक्षण संस्थानों में ज्यादातर आइआइटियों का कब्जा दिखने को मिल रहा है। आइआइटी को देश के शिक्षण संस्थानों में अहम स्थान प्राप्त है।

जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) को सातवां स्थान मिला है जबकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दसवें पायदान पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के मिरांडा हाउस को देश के सभी कॉलेजों में बेस्ट माना गया है।

वहीं सेंट स्टीफन कॉलेज को चौथा स्थान मिला है। बता दें कि एचआरडी मिनिस्ट्री 2016 से नेशनल इंस्टीट्यूटों की रैंकिग जारी कर रहा है।

(Adapted from Jagran.com)

6. Highest polling station of the world- विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, ऊंचाई है 15256 फुट; मतदाता की संख्या है मात्र 49 (Relevant for GS Prelims)

मंडी संसदीय क्षेत्र का टशीगंग मतदान केंद्र एक सप्ताह के भीतर सड़क से जुड़ जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। लोक निर्माण विभाग यहां सड़क बहाली का काम युद्धस्तर पर कर रहा है। टशीगंग 15256 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मतदान केंद्र में कुल 49 मतदाता हैं। इसमें 29 पुरुष व 20 महिलाएं हैं।

इतनी ऊंचाई पर यह मतदान केंद्र पहली बार मतदाताओं के लिए तैयार किया गया है। पहले यह मतदान केंद्र कम ऊंचाई वाले सामुदायिक भवन में था। बरसात से सामुदायिक भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब इसे राजकीय प्राथमिक स्कूल टशीगंग के भवन में स्थापित किया गया है।

इससे यह विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला मतदान केंद्र बन गया है। मतदान केंद्र व इसको जोड़ने वाली सड़क पर अब भी तीन से चार फुट तक बर्फ जमी हुई है। सड़क से बर्फ हटाने में कम से कम एक सप्ताह लगेगा 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र का 49 वोटरों वाला टशीगंग पोलिंग बूथ कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' 2004 में ही भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ने 'कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ' पर जोर दिया। नारे का लोगों पर इतना असर हुआ कि उसने कांग्रेस को सत्ता पर बैठा दिया। 2003 के आखिर में हिंदी पट्टी के बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी।

(Adapted from Jagran.com)

7. Census 2021 will make use of app for data collection- जनगणना 2021 -डाटा इकट्ठा करने में पहली बार मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा (Relevant for GS Prelims)

140 सालों में पहली बार 2021 में जनगणना में डाटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। इसमें सरकार अंतिम रूप देने के लिए जुटी है। 2021 में हाेने वाली 16वीं जनगणना की तैयारियों के लिए चल रही दो दिन की कॉन्फ्रेंस के दौरान केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने यह जानकारी दी।

जनगणना में 33 लाख कर्मचारी लगेंगे

1. गौबा ने बताया कि दुनिया की इस सबसे बड़ी जनगणना के लिए 33 लाख कर्मचारियों की जरूरत होगी। इसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। इनके पास अपना मोबाइल इस्तेमाल करने का विकल्प होगा और इसके लिए उन्हें अलग से राशि दी जाएगी। मोबाइल का इस्तेमाल न करने वाले कर्मचारियों को कागज पर आंकड़े इकट्ठा करके ऐप में डालना होगा।

2. गृह सचिव ने कहा, आंकडे जुटाते वक्त गोपनीयता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आंकड़ों का दुरूपयोग न हो।

3. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में एक अक्टूबर 2020 से जनगणना का काम शुरू हो जायेगा जबकि बाकी देश में यह एक मार्च 2021 से होगा।

4. गौबा ने बताया, जनगणना का मतलब केवल लोगों की गिनती से नहीं है, इससे देश के बारे में सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी हासिल होते हैं। इनके आधार पर नीतियां बनाई जाती हैं और संसाधनों का आवंटन होता है।

5. इन आंकडों के आधार पर ही आर्थिक विकास और कल्याण की योजनाएं बनाई जाती हैं। जनगणना से ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षित सीटों के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है।

(Adapted from bhaskar.com)

8. PM Modi accorded Russia's highest honour- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान, दूतावास ने दी जानकारी (Relevant for GS Prelims)

रूस दूतावास ने शुक्रवार को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल प्रदान किया जाएगा। मोदी को यह सम्मान रूस और भारत के बीच विशेषाधिकृत कूटनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा।

यूएई ने किया था जायेद मेडल से सम्मानित

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायेद अल नहयन ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल से सम्मानित किया था। जायेद मेडल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। मोदी को यह सम्मान दोनों देशों के बीच दोस्ती और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया।

मोदी को इस साल मिले दो बड़े सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी साल फरवरी में दक्षिण कोरिया के सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मोदी यह पुरस्कार पाने वाले 14वें व्यक्ति थे। 1988 में सियोल ओलिंपिक के सफल आयोजन के बाद यह पुरस्कार शुरू किया गया था। हालांकि, मोदी ने पुरस्कार में मिली 1।30 करोड़ की रकम को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए दे दी थी। इसके अलावा पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मोदी को इसी साल संयुक्त राष्ट्र का चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवॉर्ड दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नई दिल्ली में मोदी को इस सम्मान से नवाजा था।

(Adapted from bhaskar.com)

9. France newspaper claim that Anil Ambani firm was given tax relaxation in France- फ्रांस के अखबार का दावा- अनिल अंबानी का 14 करोड़ यूरो का टैक्स माफ हुआ, रिलायंस का इनकार (Read only for understanding)

फ्रांस के राष्ट्रीय अखबार ले मोंडे ने दावा किया कि भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की फ्रांस में स्थित टेलीकॉम कंपनी का 14 करोड़ यूरो का कर्ज राफेल डील की घोषणा के बाद माफ किया गया। हालांकि, रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस दावे को खारिज किया है। कंपनी ने कहा कि टैक्स से जुड़ा मामला फ्रांस के कानून के आधार पर ही सुलझाया गया है।

मंत्रालय ने कहा- दोनों मामलों में कोई कनेक्शन नहीं

1. रक्षा मंत्रालय ने कहा, हमने वह रिपोर्ट्स देखी जिसमें निजी कंपनी को टैक्स में दी गई छूट और राफेल डील की प्रक्रिया के बीच कनेक्शन का अनुमान लगाया गया। मगर जिस सत्र के लिए टैक्स में छूट मिली और राफेल डील की प्रक्रिया शुरू हुई, इसके समय में कोई समानता नहीं है। ऐसे में कनेक्शन की बात पूरी तरह से गलत है। यह तोड़-मरोड़कर पेश की गई है।

2. दूतावास ने कहा- सैटलमेंट में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं

फ्रांस दूतावास ने जारी किए गए बयान में कहा, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस फ्लैग और फ्रेंच टैक्स अथॉरिटीज के बीच जो सैटलमेंट हुआ, वो 2008-2012 के बीच को लेकर था। यह पूरी प्रक्रिया टैक्स प्रशासन के नियमों के आधार पर हुई। दूतावास ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ।

कांग्रेस का आरोप- सरकार ने राफेल में दलाली की

रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस फ्लैग फ्रांस में टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर और केबल नेटवर्क का संचालन करती है। फ्रांस के आयकर अधिकारियों ने रिलायंस फ्लैग एटलांटिक फ्रांस से 7.3 लाख यूरो का टैक्स लिया जबकि मांग 15 करोड़ यूरो की थी।

3. रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस फ्लैग एटलान्टिक फ्रांस की जांच, अधिकारियों ने 2007 से 2010 के सत्र को लेकर की। इसके अंतर्गत कंपनी पर 6 करोड़ यूरो का टैक्स बकाया पाया गया। हालांकि रिलायंस ने इसके लिए 7.6 लाख यूरो चुकाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे फ्रेंच अधिकारियों ने ठुकराया था। इसके बाद अधिकारियों ने 2010 से 2012 के सत्र को लेकर फिर जांच की। कंपनी को 9 करोड़ यूरो का टैक्स और देने को कहा।

4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एफ. ओलांदे से भी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस में बातचीत की थी। इसके बाद 36 राफेल विमान खरीदने की घोषणा हुई। यह डील 23 सितंबर 2016 को फाइनल हुई। इसके बाद फ्रांस के अधिकारियों ने रिलायंस के 7.3 लाख यूरो की टैक्स राशि चुकाने का ऑफर स्वीकार कर लिया, जबकि मूल मांग 15 करोड़ यूरो की थी।

5. रिलायंस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्रांस की टैक्स की मांग पूरी तरह से अवैधानिक थी। कंपनी ने इस मामले को सुलझाने के लिए किसी तरह के पक्षपात का सहारा नहीं लिया। अधिकारी ने कहा, "फ्रांस के अधिकारियों ने 2008 से 2012 के बीच के समय की जांच की। यह करीब 10 साल पहले की बात है। कंपनी को उस समय फ्लैग फ्रांस के क्रियान्वयन में 20 करोड़ रुपए (2.7 मिलियन यूरो) का नुकसान हुआ। फ्रांस अधिकारियों ने उसी समय 1100 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की। आखिर में 56 करोड़ रुपए के भुगतान का फाइनल मसौदा तैयार हुआ।"

6. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर एयरक्राफ्ट पर 1,670 करोड़ रुपए की दलाली कर रही है जबकि यूपीए सरकार ने इसके लिए 526 करोड़ रुपए तय किए थे। कांग्रेस ने सरकार पर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को देसोल्ट एविएशन के लिए ऑफसेट पार्टनर घोषित करने के लिए भी आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया।

(Adapted from Bhaskar.com)

10. Higher income levels in Kasmir in comparison to rest of country- कश्मीरी लोग देश में सबसे समृद्ध, बाकी राज्यों से ज्यादा खर्च करते हैं (Relevant for GS Prelims)

कश्मीर सिर्फ कुदरत से अमीर नहीं है, वह देश के सबसे अमीर घरों वाला राज्य भी है। यहां के परिवार बाकी देश के परिवारों से औसतन ज्यादा समृद्ध हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं। कश्मीर तीन दशकों से आतंकवाद झेल रहा है। वहां किसी भी फैक्ट्री या सरकारी प्रोजेक्ट को पहुंचने और पूरा होने में बाकी देश से 5 साल ज्यादा लगते हैं। नौकरियां कम हैं, कर्फ्यू या अलगाववादियों की हड़ताल के चलते आधे दिन कारोबार बंद रहता है। बावजूद इसके लोग यहां ज्यादा खर्च करते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।

घरेलू उपभोक्ता खर्च पर हुए सर्वे के डेटा का एनालिसिस

1. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ के घरेलू उपभोक्ता खर्च को लेकर हुए सर्वे के डेटा पर आधारित इस रिसर्च में खर्च और समृद्धि को लेकर राज्य और देश के स्तर पर एनालिसिस किया गया है। ये डेटा इसलिए भी अहम है, क्योंकि इन्हीं के जरिए सरकारी संस्थान अपनी नीतियां तैयार करती हैं।

2. 1993-94, 1999-2000, 2004-05 और 2011-12 के डेटा को इस सर्वे में शामिल किया गया है। इसमें वह दौर भी शामिल है, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। पिछले तीन दशकों में किसी कश्मीरी घर का खर्च देश के किसी भी घर के खर्च से ज्यादा रहा है।

3. 2005-2011 के बीच का समय कश्मीर में तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण रहा है। इस दौरान जो पैसा कश्मीरी घरों ने खर्च किया और जो औसतन देश ने खर्च किया उसका अतंर काफी कम है।

4. 1993-94 के बीच कश्मीरी घर का औसतन खर्च, देश के औसतन खर्च से थोड़ा कम रहा। लेकिन उसके बाद से कश्मीरी घरों का खर्च देश की तुलना में हमेशा ज्यादा ही रहा है।

5. कश्मीर के शहरी इलाकों में यह खर्च लगातार बढ़ा है। हालांकि 2011-12 के बीच ये देश के औसत से नीचे गया है। कश्मीर के ग्रामीण घरों का महीने का खर्च देश के शहरी और कश्मीर के शहरी इलाकों से कम है। लेकिन देश के ग्रामीण घरों के खर्च से काफी ज्यादा है।

6. कश्मीर में हर महीने का खर्च (रुपए प्रति व्यक्ति)

वर्ष	कश्मीर में खर्च	देशभर में खर्च
1993-94	313	325
1999-2000	735	579
2004-05	836	648
2011-12	1634	1599

7. आतंकवाद के दिनों में फिक्स्ड लाइन टेलीफोन पर खर्च काफी कम था। जो सिक्योरिटी प्रोसीजर कम होने के बाद थोड़ा बढ़ा लेकिन बाकी देश के मुकाबले कम ही रहा। 1993-94 के मुकाबले 2011-12 में मनोरंजन के सामान पर खर्च कश्मीर घाटी के घरों में बाकी देश के औसत घरों से ज्यादा रहा है। इनमें रेडियो, टेलीविजन, कैमरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं।

(Adapted from Bhaskar.com)

11. Fire in Nore Dame Church-आग से तबाह फ्रांस की ऐतिहासिक Notre Dame चर्च (Relevant for GS Prelims)

फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित 12वीं सदी का नोट्रे डाम कैथेड्रल चर्च भीषण आग में तबाह हो गया। आग से चर्च की पूरी छत और मीनारें ध्वस्त हो गईं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने देशवासियों से वादा किया है कि वह पांच साल के भीतर 850 साल पुराने इस ऐतिहासिक चर्च का पुनर्निर्माण कराएंगे। उन्होंने इस चर्च को देश की आत्मा करार दिया। चर्च के पुनर्निर्माण के लिए मदद मिलने लगी है, दूसरे दिन अब तक 100 करोड़ यूरो की मदद मिल चुकी है। फायर ब्रिगेड के प्रमुख जीन-क्लाउड गैलेट ने मंगलवार को कहा, 'नोट्रे डाम कैथेड्रल चर्च के मुख्य ढांचे और दो बेल टावर्स को बचा लिया गया है। लेकिन पूरी छत नष्ट हो गई और मुख्य मीनार भी नहीं बची।'

आग का कारण स्पष्ट नहीं

ऐतिहासिक चर्च में आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है। चर्च में बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा था। जांच अधिकारियों ने जीर्णोद्धार में लगे मजदूरों से पूछताछ की, लेकिन अधिकारियों ने किसी भी तरह की अनहोनी से इन्कार कर दिया और फिलहाल इसे एक हादसा बताया है।

युद्धों में सुरक्षित रहा था चर्च

एक पुल से धू-धू कर जलते चर्च को देखने वाले कंसल्टेंट स्टीफन सिग्नेयूरी ने कहा, 'नोट्रे डाम कैथेड्रल सभी युद्धों और बमबारी में बचा रहा। हमने यह कभी नहीं सोचा था कि यह आग में तबाह हो सकता है।'

यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल

यूनेस्को ने 1991 में इस चर्च को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया था। इस चर्च का निर्माण साल 1163 से 1345 के बीच कराया गया था। चर्च को देखने के लिए हर साल एक करोड़ से ज्यादा सैलानी आते हैं।

कई राष्ट्राध्यक्षों ने जताया दुख

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर चर्च में आग लगने पर दुख जताया और कहा, 'भीषण आग को देखना बहुत दुखद है।' जबकि जर्मनी की चांसलर एंजिला मर्केल ने इस चर्च को यूरोपीय संस्कृति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस और वेटिकन ने भी दुख व्यक्त किया है।

(Adapted from Jagran.com)

12. New Japnese emperor- देश को 30 साल बाद मिलेगा नया राजा; अगली पीढ़ी में राज परिवार के पास इकलौता वारिस (Relevant for GS Prelims)

जापान के सम्राट अकिहितो 30 साल के शासन के बाद बुधवार को राजगद्दी अपने पुत्र नारुहितो को सौंप देंगे। राजसत्ता के साथ ही इस देश में युग परिवर्तन भी होता है। अकिहितो का काल 'हेईसेई' के नाम से जाना जाता रहा। नारुहितो का शासनकाल 'रिवा' के नाम से जाना जाएगा।

राज परिवार में एक राजकुमार, बाकी तीन राजकुमारियां

1. जापान में राज परिवार की परंपरा के अनुसार सिर्फ पुरुष ही राजा बन सकता है। इस लिहाज से देखें तो चिंता की बात यह है कि अकिहितो के नाती-पोतों में सिर्फ एक राजकुमार ही बचता है। बाकी तीन राजकुमारियां हैं।

2. बेटियों से छिन सकता है राजपरिवार का दर्जा

राज परिवार में नियम यह भी है कि अगर कोई राजकुमारी किसी गैर राजपरिवार में विवाह करती है तो उसका राजपरिवार का दर्जा स्वत: छिन जाता है। सम्राट अकिहितो की एक बेटी ने बीते साल एक सरकारी अफसर से शादी की थी। इसके बाद उनका राज परिवार की सदस्य होने का दर्जा छिन गया था।

3. ये हैं राज परिवार के सदस्य

सम्राट अकिहितो की उम्र 85 साल है। उनकी पत्नी मिचिको शोदा हैं। शोदा की आयु 84 वर्ष है। शोदा जापान के एक अमीर परिवार से आती हैं। अंग्रेजी साहित्य में स्नातक हैं और बच्चों की किताबों का जापानी भाषा में अनुवाद करती रही हैं।

4. 1957 में मिचिको और अकिहितो की पहली मुलाकात हुई। दो साल बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों ने अपने तीनों बच्चों की परवरिश परंपरा से कुछ अलग की। उन्हें महल के स्टाफ के सुपुर्द करने के बजाए आमलोगों से मिलने-जुलने और विदेश में शिक्षा का अवसर मुहैया कराया।

5. नारुहितो : पहले राजकुमार जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण की

प्रिंस नारुहितो की उम्र 59 साल है। वो जापान के 126वें राजा बनेंगे। राज परिवार के वे पहले ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण की। माना जा रहा है कि नारुहितो पिता के काम को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में भी उनकी भूमिका अब बड़ी होगी।

6. नारुहितो ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और थेम्स नदी पर उनका एक शोधपत्र भी प्रकाशित हुआ था। पत्नी का नाम मसाको ओवादा है। दोनों की 17 साल की एक बेटी है और उसका नाम 'आइको' है।

7. अकिहितो के दूसरे बेटे हैं प्रिंस फुमिहितो

सम्राट अकिहितो के दो बेटे हैं। नारुहितो के छोटे भाई का नाम प्रिंस फुमिहितो है। उनकी उम्र 53 साल है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नारुहितो के बाद फुमिहितो राजसत्ता नहीं संभालेंगे, बल्कि इसे अपने बेटे हिशाहितो को सौंप देंगे।

8. ऐसा इसलिए भी संभव है कि जब नारुहितो राजगद्दी छोड़ेंगे तब तक फुमिहितो की उम्र करीब 83 साल हो चुकी होगी। अभी उनके बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है और उस वक्त 42 साल का हो जाएगा। फुमिहितो की पत्नी का नाम 'प्रिंसेस किको' है। वैसे इस युगल की दो बेटियां भी हैं। एक का नाम प्रिंसेस माको (27) है जबकि दूसरी का नाम प्रिंसेस काको (24) है।

(Adapted from Bhaskar.com)

13. 3000 kgs of solid garbage cleaned from Mount Everest- माउंट एवरेस्ट से 3 हजार किलो कचरा साफ किया, पर्यावरण दिवस पर दिखाया जाएगा (Relevant for GS Prelims)

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रंखला माउंट एवरेस्ट से 3 हजार किलो कचरा साफ किया गया है। नेपाल सरकार ने 14 अप्रैल से 45 दिनों का एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन शुरू कर रखा है। इसके तहत 10 हजार किलो कूड़ा इकट्ठा करने का लक्ष्य है। अभियान पर तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख रुपये खर्च होने हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से कूड़ा मिल रहा है, उससे साफ है कि पर्वत श्रंखला कूड़े के ढेर में तब्दील हो रही है। सारा कूड़ा काठमांडू लाकर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी 5 जून के दिन लोगों को दिखाया जाएगा और फिर इसका निस्तारण किया जाएगा।

29 मई को पूरा होगा सफाई अभियान

1. पर्यटन विभाग के निदेशक डंडू राज घिमिरे का कहना है कि सफाई अभियान 29 मई को पूरा होगा। इसी दिन एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे ने 1953 में पहली बार एवरेस्ट पर फतह पाई थी।

2. पर्वतारोहियों के साथ कुलियों के जरिए पहुंच रहा कूड़ा

सूत्रों का कहना है कि एवरेस्ट में जो कूड़ा मिला है, उसे या तो पर्वतारोही वहां पहुंचा रहे हैं, या फिर ऊंचे क्षेत्रों में काम करने वाले कुली। समय-समय पर शेरपा भी एवरेस्ट का भ्रमण करते हैं, उनसे भी कूड़ा वहां पहुंच रहा है। जो कूड़ा एकत्र किया गया है, उसमें प्लास्टिक, बीयर की बोतलों, कास्मेटिक के कवर जैसी चीजें शामिल हैं।

3. घिमिरे का कहना है कि जो कूड़ा एकत्र किया गया है, उसमे से 2 हजार किलो ओखलधुंगा भेजा जा रहा है, जबकि बाकी 1 हजार किलो को नेपाली सेना के हेलिकॉप्टरों के माध्यम से काठमांडू लाकर निस्तारित किया जाएगा।

4. उनका कहना है कि 5 हजार किलो कूड़ा बेस कैंप एरिया से एकत्र होना है, जबकि 2 हजार किलो दक्षिणी क्षेत्र और 3 हजार किलो कैंप2, कैंप3 एरिया से इकट्ठा किया जाना है। उनका कहना है कि कूड़ा एकत्र करने वाली टीमों को निर्देश दिया गया है कि ऊपर अगर कोई शव मिले तो उसे भी नीचे लाया जाए। उनका कहना है कि अभी तक 4 शव ऊपरी क्षेत्र में मिले हैं।

5. एवरेस्ट को साफ रखने के लिए सरकार ने पहले भी प्रयास किए हैं। 2014 में कानून बनाया गया था कि जो भी पर्वतारोही एवरेस्ट पर जाएगा, वह नीचे आते समय कम से कम 8 किलो सॉलिड वेस्ट अपने साथ लेकर आएगा। सरकार की कोशिश थी कि एक पवर्तरोही जितना कूड़ा पहाड़ पर फैलाए, कम से कम उतना तो वह नीचे लेकर आ जाए।

(Adapted from Bhaskar.com)